HP/129/SML/2019-2021 Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500 16-30 सितम्बर, 2019

द रीव टाइम्स
The RIEV Times

हिमाचल,
वर्ष 2/ अंक 29/ पृष्ठ: 16
मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com

समस्या को समस्या नहीं समाधान के दृष्टिकोण से देखें : डॉ॰ एल.सी. शर्मा

Welcoming Step of Shimla Municipal Corporation- Auction of Book Café

Dr. L.C. Sharma
Editor in Chief

Since 1991, when the Indian economy opened for trade and investment for the private sector to encourage competition, the process of globalisation of the economy started taking shape after the economic crisis of 1990. India had to pledge 20 tonnes of gold to Union Bank of Switzerland and the additional 47 tonnes to the Bank of England as part of a bailout deal with the International Monetary Fund (IMF), which forced most of the economic reforms upon India.

It was the dynamic leadership of P.V. Narsimha Rao, the Prime Minister of India at that time, to initiate liberalisation of the economy with the support of Dr. Manmohan Singh, the then Finance Minister. Dr Singh, being an economist, had the idea of liberalisation but lacked the courage to implement it, which was supplemented by PM Rao; without courage, ideas are barren if they are not converted into actions.

An extended step on disinvestment was taken by Atal Bihari Vajpayee and his tenure heading the National Democratic Alliance (NDA) between 1999 and 2004, can be described as the "golden period" for privatisation under the seasoned statesman Arun Shourie as per the lay out designed by Subramanian Swami.

At present, the Narendra Modi Government 2.0 has also set an ambitious target to realise Rs 1.05 Lakh Crore from disinvestment from Public Sector Enterprises and this movement is going on as this is the need of the hour to rejuvenate our economy. No government can afford to underutilise its assets and stay away from the optimum utilisation of its resources for the public good.

There is dire need to redefine the role of a government; do we see the government as a facilitator or a business entity? Apparently, the government cannot be a business entity. Its role is to be a facilitator for the growth of its people and to ensure that it creates an environment when an individual can evolve to the level of higher self and society as a whole can grow and prosperous with harmony. The second role comes as a regulator where the State has to ensure social justice. The State may have different roles in different perspectives, but the major roles are of being a Facilitator and a Regulator only from citizens' perspective.

Starting commercial ventures and continuously bearing losses for decades cannot be justified on the government's part. The unaccountable deployment of the bureaucrats and their frequent relocation paralyses the public enterprises and such enterprises easily become vulnerable to

political and bureaucratic influence.

The same happened to the public sector banks which have been encountering with the NPA of approximately Rs 10.00 lakh crore for the years. However, the latest data revealed by Finance Minister Nirmala Sitharaman indicates that the NPA stands at around Rs 8.06 lakh crore.

Such issue is being faced by the Himachal Pradesh government as well because many of the hotels of the HPTDC have also been going through the same situation. As per the reports, 28 out of 52 HPTDC properties are running at loss. The state-owned company has leased out some of its restaurants in different locations, but still, are carrying the burden of the remaining 28 loss-making units. The state is already under the burden of almost Rs 50,000 crore loan, which means every Himachali is under the debt of Rs 66,000 at present.

Not only this, every child born in Himachal acquires the debt of Rs 66,000 even without any mistake or deed of its own.

In such a scenario, the state seems ready to continue increasing the losses without involving private players in the management of its private properties. If done so, this may cause displeasure to the people with political and bureaucratic labels when the facilities of 'Royalty with Respect' will cease.

In such a scenario, no one with good intention should hesitate to welcome Municipal Corporation Shimla's step to lease out its Book Cafe for a monthly rent of more than Rs 1.00 lakh, instead of earlier revenue of Rs 8,000 to Rs 10,000 per month.

There are many such areas where MC Shimla needs to brainstorm to bring economic equilibrium to this municipality which once had lent to the MC Mumbai, but today is a victim of political ignorance, unclear vision and the stale functioning style clubbed with the less-effective and self-styled public representation. This first right step in the direction of the economic balancing is expected to create more such avenues and may encourage the state government to rise above the conventional beliefs and political fear of criticism.

आईआईआरडी ने गेल इंडिया के साथ किए बड़े अनुबंध....

बिहार, आसाम और पश्चिम बंगाल में संस्था करेगी शौचालयों का निर्माण

इन राज्यों के अलावा झारखंड में भी स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल के लिए भी हुआ एमओयू

द रीव टाइम्सः हेम राज चौहान

आईआईआरडी द्वारा सामाजिक प्रतिबद्धता में देश भर में अभूतपूर्व सेवाऐं प्रदान की जा रही है । लगभग प्रत्येक राज्यों में संस्था ने अपनी बेहतर कार्यप्रणाली और कुशल प्रगतिशील क्षमताओं के कारण बड़ी परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाया है । इसी के चलते अब बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम में भी संस्था गेल इंडिया की वृहद् परियोजना के माध्यम से सरकारी विद्यालयों, सार्वजनिक और अन्य वांछित स्थलों पर अत्याधुनिक सुविधाओं वाले शौचालयों का निर्माण करेगी । इन शौचालयों को सरकारी विद्यालयों में बनाया जाऐगा तथा आवश्यकता आधारित स्थलों को चयन करके वहां भी निर्माण होगा । संस्था इसके लिए सबसे पहले सर्वेक्षण करवाएगी तथा इसी के आधार पर पूरी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा । यानि जिन स्कूलों में शौचालयों की आवश्यकता है, ऐसे स्थल जो कि सार्वजनिक हैं तथा वहां शौचालयों की आवश्यकता है, वहां ही संस्था इन शौचालयों का निर्माण करेगी । यह एक वृहद् परियोजना है तथा इसके तहत सरकार की स्वच्छता नीति और लोगों को स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने की कवायद कहा जा सकता है । बिहार और पश्चिम बंगाल में आईआईआरडी द्वारा इससे पूर्व भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर सेवाऐं दी जा चुकी है तथा यह प्रयास जारी है । इन आधुनिक शौचालयों के निर्माण में गुणवत्ता की सुनिश्चितता को बनाए रखने के लिए संस्था प्रतिबद्ध है । इन शौचालयों में टाइलस्, पानी की समुचित व्यवस्था, जल टैंक एवं अन्य समस्त वांछित सुविधाओं को भी सुनिश्चित बनाया जाऐगा । कुल 115 से अधिक शौचालयों का निर्माण होगा और इसी वित्तिय वर्ष में इनका निर्माण संस्था द्वारा पूरा कर लिया जाएगा ।

बिहार, पश्चिम बंगाल व आसाम में स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल और आर ओ सिस्टम लगाऐगी आईआईआरडी

आईआईआरडी द्वारा एक और बड़ी परियोजना पर एम ओ यू हस्ताक्षरित हुआ है जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और आर. ओ. सिस्टम को लगाने में संस्था सेवाऐं देगी । 250 से अधिक सरकारी विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा को सुनिश्चित बनाया जाऐगा जिसके लिए बेहतर गुणवत्ता के आर.ओ. सिस्टम को स्थापित करेगा । स्कूलों में शुद्ध-स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिए संस्था इस परियोजना को अमलीजामा पहनाऐगी । इसके लिए सर्वेक्षण का कार्य संस्था द्वारा आरंभ किया जा चुका है जिसके अंतर्गत ऐसे स्कूल और स्थानों को इन राज्यों में चयन होगा जहां सबसे अधिक आवश्यकता इस परियोजना की होगी ।

झारखंड के गिरिधि में भी सरकारी विद्यालयों में आर.ओ. सिस्टम स्थापित करने का आईआईआरडी ने अनुबंध किया है । इसके तहत 30 सिस्टम स्थापित किए जाऐंगे तथा विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है ।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में संस्था आधुनिक कुड़ेदान करेगी स्थापित

आईआईआरडी एक और परियोजना पर सेवाऐं दे रही है। मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन में अत्याधुनिक गारबेज बिन स्थापित करेगी । उज्जैन में हर वर्ष सैंकड़ों की तादात में श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं तथा इस नगरी में पर्यटकों की संख्या भी अधिक है । ऐसे में वहां की सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 60 से अधिक आधुनिक कुड़ेदान लगाए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इस परियोजना का उद्देश्य उज्जैन को स्वच्छ और सुंदर, कुड़ा-कचरा रहित बनाने में अब आईआईआरडी अपनी सेवाऐं देगी जिसके प्रथम चरण में आधुनिक कुड़ेदान लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी श्रद्धालु या पर्यटक एक समुचित दूरी पर लगे इन कुड़ेदान का ही उपयोग करें। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी आईआईआरडी अनेक बड़ी परियोजनाओं पर सेवाऐं दे रही है जिसमें इंडोर स्टेडियम से लेकर गैस पाईप लाईन सर्वेक्षण आदि शामिल है । कई राज्यों में आधुनिक कुड़ेदान एवं शौचालयों का निर्माण कर संस्था ने अपनी सामाजिक विकास की प्रतिबद्धता आगे ले जाने के लिए कृतसंकल्प है ।

आईआईआरडी दूसरी बार सी एस आर टाइम्स अवार्ड 2019 विजेता

राष्ट्रीय सी एस आर समिट एवं अवार्ड 2019 में 18 सितंबर को होगी सम्मानित

द रीव टाइम्स

आई.आई.आर.डी. ने सफलता की एक और सीढ़ी पार करते हुए लगातार दूसरी बार सी एस आर टाइम्स अवार्ड 2019 को पाने का गौरव प्राप्त हो रहा है। यह पुरस्कार 18 सितंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सी एस आर समिट एवं अवार्ड 2019 में प्रदान किया जाऐगा। गौरतलब है कि संस्था देश के अधिकतर राज्यों में सी एस आर परियोजनाओं एवं विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से सेवाऐं दे रही है । विगत वर्षों में अनेक पुरस्कारों से संस्था सम्मानित हो चुकी है ।

रीव फीड सप्लिमेंट की आपूर्ति अब जालंधर और कपूरथला में

गोशालाओं में मिशन रीव ने किया फीड वितरित

द रीव टाइम्स, हेम राज चौहान

मिशन रीव के अंतर्गत रीव फीड सप्लिमेंट के हिमाचल में बेहतर परिणामों के बाद अब जालंधर और कपूरथला में भी गोशालाओं में वितरित किया जा रहा है। इसके लिए मिशन रीव की टीम आन्नद नायर की अगुवाई में कपूरथला एवं जालंधर में गोशालाओं के प्रतिनिधियों से मिले। वहां पर रीव फीड सप्लिमेंट पर न केवल चर्चा की गई अपितु उसको उपयोग करने को व्यवहारिक रुप से बताया गया। गोशाला में विभिन्न नस्लों की गायों को रखा

गया है। गोशाला संचालकों ने माना कि दूध के उत्पादन और गायों की स्वस्थता के लिए इस प्रकार के उत्पाद की बहुत आवश्यकता है। इसका परीक्षण करने के बाद बेहतर परिणाम की स्थिति में मिशन रीव के साथ आगामी अनुबंध किया जाऐगा। कपूरथला स्थित गोशालाओं में सैंकड़ों गायों एवं सांड को संरक्षण मिला है। इन गायों की कई नस्लें विद्यमान है। रीव फीड सप्लिमेंट बेहद पौष्टिक एवं गुणवत्ता से तैयार किया गया उत्पाद है जिससे हिमाचल प्रदेश में भी लोगों ने पशुधन को उपयोग में लाने के दौरान सराहा है। मिशन रीव, रीव जैविक खाद के साथ-साथ रीव फीड सप्लिमेंट में भी अपने बेहतरीन उत्पादों के साथ लोगों के बीच उतरा है। रीव फीड सप्लिमेंट को हिमाचल में उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया मिलने के बाद इसे हरियाणा और पंजाब में भी किसानों एवं गौशालाओं में रीव फीड सप्लिमेंट को प्रचारित एवं वितरित किया जा रहा है। कपूरथला में गोशाला प्रमुख ने बताया कि उनके यहां 1000 से अधिक गायों एवं बैंलों को रखा गया है। इनमें कई नस्लों की गाय हैं लेकिन भविष्य के लिए देसी गाय की नस्ल को तैयार किया जा रहा है। ऐसे में रीव फीड सप्लिमेंट को दुधारु गायों को फीड के रुप में दिया जा रहा है तथा बेहतर परिणाम आने के बाद इसे प्रदेश की अन्य गोशालाओं एवं किसानों को भी दिया जाएगा। गोशालाओं में सेवा दे रहे सुभाष मकरंदी ने विशेष तौर पर कपूरथला एवं जालंधर में गोशालाओं का भ्रमण करवाकर वहां पर किसानों से भी बात करवाई और इस फीड के फायदे बताऐ।

पंजाब और जम्मु-कश्मीर के प्रतिनिधियों को बताये रीव फीड के फायदे

जालंधर के वत्सल योग आश्रम में समस्त पंजाब एवं जम्मु-कश्मीर के गो-सेवकों, गो-संरक्षकों एवं संचालकों के प्रतिनिधियों का सेमिनार हुआ जिसमें शिमला से विशेष तौर पर मिशन रीव से रीव फीड सप्लिमेंट पर जानकारी देने के लिए टीम रीव ने शिरकत की। इस सेमिनार की अगुवाई गो-सेवक एवं संचालक व प्रांत प्रभारी चंद्रकांत की अध्यक्षता में पूरी हुई। इस बैठक में चालीस से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य गाय संरक्षण में हो रहे सेवा कार्यों की समीक्षा एवं समस्याओं पर मंथन करना था। इसके लिए पंजाब एवं जम्मु-कश्मीर से गो ज़िला प्रभारी एवं संचालक एकत्रित हुए। इस सेमिनार में देसी गायों के संरक्षण, गाय के दूध एवं उनसे बनने वाले उत्पादों की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है तथा उनके लाभ प्रतिनिधियों के माध्यम से किसानों एवं लोगों तक ले जाने के लिए मंथन किया गया। इसी प्रक्रिया में मिशन रीव की ओर से आन्नद नायर ने रीव फीड सप्लिमेंट पर चर्चा करते हुए बताया कि इस सेमिनार में आए प्रतिनिधियों की अधिकतर समस्याओं का हल रीव फीड सप्लिमेंट है जिसे यदि सही मात्रा एवं सही प्रकार से फीड करवाया जाए तो इसके फायदे बहुत दूरगामी है। उन्होंने गो-सेवा प्रमुखों एवं संचालकों को बताया कि इस फीड के कारण न केवल दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है बल्कि दूध को गाढ़ा करके इसके उत्पाद भी बेहतरीन एवं गुणकारी हो जाते हैं। बीमार पशुओं को इस फीड से लाभ हुआ है साथ ही इससे चारा की मात्रा में भी कमी आ जाती है। इसके अलावा गो सेवकों एवं संचालकों को रीव स्पिरु उत्पाद के लाभ एवं उपयोग करने के फायदों पर भी जानकारी दी गई। गौरतलब है कि मिशन रीव का बेहतरीन न्यूट्रिशियन उत्पाद स्पिरु हिमाचल एवं अन्य राज्यों में बड़ी मांग में है। इसके कैप्सूल एवं कॉस्मेटिक उपयोग के बाद बेहतर परिणामों को देखते हुए इसे मार्केट में लाया गया है। इस कार्यक्रम में चंद्रकांत के साथ राकेश चोपड़ा, सुभाष मकरंदी, मिशन रीव से आनंद नायर ने भाग लिया।

द रीव टाइम्स को मिली सराहना

द रीव टाइम्स के अंक अब पंजाब एवं हरियाणा में भी लोगों को पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। गोशालाओं में तथा किसानों की समस्याओं एवं रीव फीड सप्लिमेंट पर बड़ी कवरेज़ में प्रतिनिधित्व मिला है। इसके लिए गोशाला के संचालकों एवं किसानों ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि इस समाचार पत्र में गो सेवकों की सामाजिक गतिविधियों एवं किसानों की समस्याओं को स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि मिशन रीव की इस क्षेत्र में अभूतपूर्व सेवाओं की जानकारी भी हमें हमारे प्रांत में मिल रही है।

युवाओं को प्रशिक्षण का बेहतर मौका दे रहा मिशन रीव

शिमला के बाद अब सुन्नी और कुमारसेन में भी पीएमकेवीवाई सेंटर

द रीव टाइम्सः हेम राज चौहान

रोजगार के क्षेत्र में आईआईआरडी ने मिशन रीव के अंतर्गत अब तक सैंकड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया है। इसी पहल में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत शनान में स्थित सेंटर में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है जिन्हें प्रशिक्षण के बाद गारंटीशुदा रोजगार से जोड़ा जाऐगा।

अब दूसरा सेंटर सुन्नी में खोला गया है जिसमें शिमला ग्रामीण के सुन्नी क्षेत्र के युवाओं को एक बेहतरीन अवसर घर पर ही उपलब्ध हो रहा है। इस सेंटर में युवाओं को रिटेल सेलस् ऐसोसियेट्स् का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें प्रशिक्षण के बाद समस्त युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाऐगा। इस सेंटर में बेरोजगार युवाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने के लिए एक सुनहरा मौका मिशन रीव के अंतर्गत प्राप्त हो रहा है। सुन्नी के बाद कुमारसेन में भी युवाओं को इस प्रकार के प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त होने जा रहा है।

बिलासपुर एवं चंडीगढ़ में ग्रीन स्पिरु और फीड सप्लिमेंट पर दी जानकारी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मिशन रीव के अंतर्गत रीव फीड सप्लिमेंट और ग्रीन स्पिरु (न्यूट्रिशियस फूड सप्लिमेंट) के प्रचार को रीव टीम जदरौर बिलासपुर और चंडीगढ़ में डॉक्टर और लोगों से मिली। इस टीम की अगुवाई अनुपमा ने की तथा वहां डॉक्टर की टीम को बताया कि किस प्रकार ग्रीन स्पिरु से प्राकृतिक तौर पर हम स्वयं को स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। इसके लिए इसके एक या दो कैप्सूल (आयु के अनुसार) दो समय लेकर आंतरिक और बाहरी तौर पर स्वयं को स्वस्थ रखा जा सकता है।

इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह उत्पाद समुद्री घास से तैयार होता है तथा किसी भी आयु वर्ग के लोग इसे उपयोग कर सकते है। इसके अलावा ग्रीन स्पिरु का दूसरा प्रारुप कॉस्मेटिक है जो पाउडर के रुप में मिलता है। इससे किसी भी प्रकार की झुर्रियां, मुहांसे, कालापन आदि साफ होता है और इसके कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। इसके लिए एक खास प्रकार का प्राकृतिक हरि घास जो कि समुद्र में मिलती है, का उपयोग किया गया है। लोग भी इस उत्पाद को उपयोग करने के लिए तैयार हैं।

इसी प्रकार चंडीगढ़ में भी ग्रीन स्पिरु की मांग बढ़ी है तथा इस बाबत वहां डॉक्टर, ब्यूटी पार्लर और लोगों से बात कर जानकारी दी गई। चंडीगढ़ में आयुर्वेदिक एवं एलोपेथी के डॉक्टर से भेंट कर उन्हें भी इस उत्पाद पर संपूर्ण जानकारी दी गई।

चिकित्सकों ने बताया कि इस उत्पाद को उपयोग में लाया जाऐगा तथा इसे मरीज़ों को एक बेहतरीन न्यूट्रिशियस के रुप में दिया जायेगा। डाईटिशियन से भी इस उप्पाद को लेकर बात की गई तथा उन्होंने भी इसको लाभप्रद बताते हुए भोजन में उपयोग करने की बात मानी।

सहकारी सभा में 33 करोड़ के घोटाले में 10 गिरफ्तार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के बिलासपुर जिले के तलाई सेवा सहकारी सभा समिति में हुए 33 करोड़ के गोलमाल मामले में पुलिस ने 10 और लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी तत्कालीन सभा समिति के पदाधिकारी और सदस्य रहे हैं। इस मामले के मुख्य आरोपी सभा सचिव और दो अन्य लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इन सभी पर 33 करोड़ के गोलमाल का आरोप है। आरोप हैं कि सभा ने नियमों को ताक पर रख कर करोड़ों रुपये के ऋण अपने दायरे से बाहर के लोगों बांट दिया। ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तलाई ग्राम सेवा सहकारी सभा समिति के सचिव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। छानबीन के बाद सामने आया कि इस घोटाले में और भी शामिल हैं।

हिमाचल में उपचुनाव के बाद लागू होगा नया मोटर व्हीकल एक्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में मोटर व्हीकल एक्ट - 2019 विधानसभा उपचुनाव के बाद ही लागू होगा। धर्मशाला और पच्छाद उपचुनाव के चलते प्रदेश सरकार जनता पर बोझ नहीं डालना चाहती है। परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट - 2019 को लागू करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया था। इसमें नियमों के उल्लंघन पर केंद्र की ओर से तय जुर्माने में डेढ़ गुना (फैक्टर 1.5) बढ़ोतरी का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, लेकिन विधि विभाग ने आपत्तियां लगाकर इसे लौटा दिया है। अब परिवहन विभाग फैक्टर वन यानी केंद्र की ओर से तय जुर्माने के अनुसार ही प्रस्ताव तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। नए एक्ट को लेकर केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के दिए बयान के बाद सीएम ने प्रदेश में एक्ट लागू करने पर स्थिति स्पष्ट की है। ऊना जिले के हरोली पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकार नए एक्ट का पूरा अध्ययन कर रही है, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

बांड तोड़ने वाले 27 डॉक्टरों को नोटिस, दूसरे राज्यों में दे रहे सेवाएं

द रीव टाइम्स ब्यूरो

बांड तोड़कर दूसरे राज्यों में सेवाएं देने वाले 27 डॉक्टरों को सरकार ने फिर नोटिस जारी किए हैं। हिमाचल में पीजी और एमडी करने के बाद ये चिकित्सक बाहरी राज्यों में सेवाएं दे रहे हैं। सरकार ने इन्हें बांड जमा करने को कहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

सरकार डॉक्टरों पर लाखों रुपये खर्च करती है, लेकिन जब सेवाएं देने की बारी आती है को कई चिकित्सक हिमाचल में सेवाएं देने की बजाय दूसरे राज्यों में सेवाएं देना पसंद करते हैं। इसका कारण दूसरे राज्यों में ज्यादा पैसा मिलना है। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि बांड तोड़कर जाने वाले डॉक्टरों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। पीजी करने के बाद जब डॉक्टर एमडी और एमसीएच करते हैं तो उन्हें शपथपत्र में बांड मनी भरनी होती है। अगर कोई डॉक्टर बाहर जाना चाहता है तो उनसे यह पैसा रिकवर किया जाता है। दो डॉक्टरों ने 55 लाख रुपये जमा करा दिए हैं।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

राहेडू -रामपुर में भी युवाओं का हुनर तराशेगा आईआईआरडी पीएमकेवीवाई के तहत शुरु होगा प्रशिक्षण केंद्र

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के युवाओं का हुनर तराशने के लिए आईआईआरडी की ओर से हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के साझेदार के तौर पर पीएमकेवीवाई केंद्र खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों पर युवाओं के कौशल को तराशने के बाद उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला के रामपुर और रोहड़ू में भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केंद्र खोले जाने की योजना है। इन केंद्र पर रामपुर और आसपास के युवाओं और युवतियों को रिटेल सेल्स एसोसिएट्स के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण करीब तीन सौ घंटों का होगा और इसके लिए केंद्र में कंप्यूटर लैब खास तौर पर स्थापित की गई है। प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षार्थियों की नियम और शर्तों के मुताबिक प्लेसमेंट भी की जाएगी।

मिशन रीव ने बताया मृदा परीक्षण और जीवन बीमा का महत्व रामपुर में विशेष शिविरों का आयोजन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में गांव में कृषि का विशेष महत्व है। इसलिए जरूरी है कि कृषि के आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों के बारे में किसानों और बागवानों को जानकारी दी जाए और उन्हें यह सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाए। मिशन रीव के तहत किसानों-बागवानों को इसी तरह की सुविधा प्रदान की जा रही है। हाल ही में रामपुर के विभिन्न क्षेत्रों में मिशन रीव के प्रतिनिधियों की ओर से जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। गौरा मशनू, गोपालपुर और रचोली समेत अन्य स्थानों पर आयोजित इन शिविरों में गांव के लोगों को मिशन रीव के तहत प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही गांव के लोगों को बताया गया कि कैसे मिशन रीव की सहायता से सरकारी योजनाओं का लाभ अपने घर पर ही आसानी से ले सकते हैं। मिशन रीव के अतिरिक्त सहायक कार्यक्रम अधिकारी अंकुश नगरैक ने बताया कि रामपुर में लोगों को मृदा जांच और जीवन बीमा के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। स्थानीय लोगों ने मिशन रीव की ओर से दी जा रही सेवाओं की खूब सराहना की।

हिमाचल में उद्योग लगाने के लिए 246 प्लॉट तैयार, रेट लिस्ट जारी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

देवभूमि में नए उद्योग लगाने के लिए 246 प्लॉट तैयार हो चुके हैं। उद्योग विभाग ने छह जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों के इन प्लॉटों की रेट लिस्ट जारी कर दी है। सोलन के बद्दी में उद्योग लगाने के लिए 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से प्लॉट मिलेंगे।

चंबा के गरनोटा औद्योगिक क्षेत्र में 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन उपलब्ध है। वहीं, कांगड़ा के कंदरोड़ी में जमीन के दाम 12 गुना अधिक हैं। कंदरोड़ी में 1800 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन मिलेगी।

कांगड़ा जिला में सबसे ज्यादा 88 प्लॉट बेचने को तैयार हैं। इसके अलावा ऊना जिला में 62, बिलासपुर में 19, चंबा में 23, शिमला में 19 और सोलन में 35 प्लॉटों की रेट लिस्ट जारी की गई है।

उद्योग विभाग कांगड़ा के महाप्रबंधक ने कहा कि विकसित और अविकसित प्लॉटों की रेट सूची जारी की गई है। उन्होंने कहा कि जो भी निवेशक औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के लिए जमीन खरीदना चाहता है, विभाग से संपर्क कर सकता है।

किस जिले में कितने दाम (प्रति वर्ग मीटर रुपये में)

बिलासपुर	750 से 850
चंबा	150 से 250
कांगड़ा	250 से 1800
शिमला	750
ऊना	333 से 2000
सोलन	350 से 4300

कैजुअल कर्मचारियों पर प्रसारभारती और केन्द्रों में तैनात स्टाफ द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरोध में दिल्ली में धरना प्रदर्शन

द रीव टाइम्स हेम राज चौहान

देश भर में आकाशवाणी केन्द्रों में महिला कैजुअल कर्मचारियों पर प्रसारभारती और केन्द्रों में तैनात स्टाफ द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरोध में देश भर के आकाशवाणी केन्द्रों से कैजुअलस् उद्घोषकों एवं कंपीयर ने दिल्ली में महिला आयोग और आकाशवाणी निदेशालय के सामने धरना प्रदर्शन किया । इसमें शिमला आकाशवाणी उद्घोषक संघ से भी पदाधिकारियों ने भाग लिया। यह धरना दिन भर चला तथा कैजुअलस् ने आरोप लगाया कि आकाशवाणी में महिला कैजुअलस् कर्मचारियों का शोषण किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है । इतना ही नहीं कैजुअलस् कर्मचारी सभी प्रभागों में अपनी सेवाऐं देते हुए आज भी रेडियो को जिंदा रखे हुए हैं । लेकिन इन्हीं कैजुअलस् के साथ आकाशवाणी प्रशासन का रवैया ग़ैरजिम्मेदाराना रहता है और प्रताड़ना भी की जाती है । जानबूझकर रात्रि सेवाओं में महिलाओं की ड्यूटी लगाना भी इसमें शामिल है । इतना ही नहीं कैजुअलस् की ड्यूटी भी कम कर दी गई है । वर्षों से नियमितिकरण एवं पॉलिसी बनाने की मांग आज भी जानबूझकर ठंडे बस्ते में डाली जा रही है । कैजुअलस को 2013 से बढ़ी फीसों पर रोक लगा रखी है और सुविधाओं के नाम पर शोषण किया जा रहा है । इन सब मांगों पर यह धरना प्रदर्शन किया गया । इन समस्याओं के बारे में बहुत पहले से पत्राचार एवं अन्य माध्यमों से प्रसारभारती को अवगत करवाया जाता रहा है । लेकिन कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं होता है । इसी के चलते दिल्ली में शिमला संघ एवं राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष हरि कृष्ण शर्मा की अगुवाई में सैंकड़ों कैजुअलस् ने धरना प्रदर्शन किया तथा समस्या का समाधान न होने की सूरत में आगामी आंदोलन की रुपरेखा तैयार की । शिमला आकाशवाणी केन्द्र से भी अनेक कैजुअलस् इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए ।

श्राद्ध पक्ष 2019: विधिपूर्वक पितरों का श्राद्ध करने से दूर होते हैं दोष

रीव टाइम्स ब्यूरो

श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का समय है। श्राद्ध पक्ष 2019, 14 सितंबर से शुरू हो गया है। इससे एक दिन पहले 13 सितंबर यानि शुक्रवार को पूर्णिमा का श्राद्ध हुआ। 16 दिन तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष के दौरान लोग पितरों को श्रद्धा अर्पित करेंगे। इसके अतिरिक्त 25 सितंबर को एक साथ दो श्राद्ध होंगे। 28 सितंबर को श्राद्धों का समापन होगा। द्वितीय श्राद्ध 15 सितंबर की दोपहर 12:24 बजे से लेकर 16 सितंबर की दोपहर 2:36 बजे तक रहेगा। बताया कि द्वितीय तिथि बढ़ी हुई है। 25 सितंबर को एकादशी और द्वादशी के श्राद्ध एक साथ होंगे। 28 सितंबर को सर्व पितृ श्राद्ध किए जाएंगे। इसके बाद 29 सितंबर से नवरात्र शुरू होंगे जोकि 8 अक्तूबर तक होंगे।

कब कौन सा श्राद्ध

14 सितंबर 2019 पहला श्राद्ध
15 से 16 सितंबर 2019 तक दूसरा श्राद्ध
17 को तृतीय श्राद्ध
18 को चतुर्थी श्राद्ध
19 को पंचमी श्राद्ध
20 को षष्टी श्राद्ध
21 को सप्तमी श्राद्ध
22 को अष्टमी श्राद्ध
23 को नवमी श्राद्ध
24 को दशमी श्राद्ध
25 को एकादशी और द्वादशी का श्राद्ध
26 को त्रयोदशी श्राद्ध
27 चतुर्दशी श्राद्ध
28 सर्व पितरी श्राद्ध

हिमाचल पुलिस ने नशे के खात्मे को लिया बड़ा फैसला

द रीव टाइम्स ब्यूरो

डीजीपी एसआर मरडी ने कहा कि पुलिस नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। नशे के बढ़ते प्रचलन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस-महा जागरूकता अभियान शुरू कर रही है। पंचायत के वार्ड स्तर तक नशा निवारण कमेटियों का गठन किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ते चिट्टे (हिरोईन) के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। पुलिस ने ऐसा प्रावधान किया है कि जिस भी व्यक्ति के पास से चिट्टा पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ धारा 308 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास) लगाई जाएगी। इस धारा के तहत आरोपी को कड़ी सजा होगी। डीजीपी ने यह बात एसपी दफ्तर धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। एक प्रश्न के जवाब में डीजीपी एसआर मरडी ने कहा कि हिमाचल में पुलिस कर्मचारियों की संख्या 1972 में तय किए गए स्टाफ के बराबर है। 37 वर्ष बीतने के बाद जनसंख्या भी बढ़ी है। ऐसे में अपराध को रोकने के लिए ज्यादा स्टाफ की आवश्यकता है। हालांकि, पुलिस में भर्ती प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन, जरूरत के मुताबिक स्टाफ की भर्ती के लिए पुलिस विभाग ने प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद है कि प्रदेश सरकार इस पर आवश्यक कार्रवाई कर रही होगी। डीजीपी ने दावा किया कि प्रदेश में पिछले वर्ष के मुकाबले हत्या के मामलों की संख्या कम हुई है। पिछले साल 71 जबकि इस वर्ष हिमाचल में 43 मर्डर हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में

होगा। बीच में वह अपने रिश्तेदार के घर पर गया था। पुलिस ने रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। कांगड़ा जिला के नूरपुर में एसपी दफ्तर खोलने को लेकर पुलिस विभाग ने प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा है। डीजीपी ने कहा कि अपराध को कम करने के लिए वह प्रदेश के हर महत्वपूर्ण स्थान पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाएंगे। इससे अपराधी का अपराध करके भागना मुश्किल हो जाएगा। डीएसपी को अपने उपमंडल का ब्योरा देना होगा कि उसके इलाके में कितने सीसीटीवी कैमरे सही चल रहे हैं।

सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका

हिमाचल में जेओए और जेई समेत 10 पोस्ट कोड की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 10 विभिन्न पोस्ट कोड के तहत होने वाली छंटनी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) और जेई समेत 10 पोस्ट कोड की परीक्षाएं 12 अक्तूबर से होंगी। पोस्ट कोड 709 क्लर्क और लेखाकार की परीक्षा 12 अक्तूबर को सुबह के सत्र में, पोस्ट कोड 715 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सायंकालीन सत्र में होगी।

पोस्ट कोड 712 इलेक्ट्रिशियन एवं सब स्टेशन अटेंडेंट की परीक्षा 13 अक्तूबर को सुबह और पोस्ट कोड 714 जूनियर इंजीनियर सिविल की परीक्षा सायंकालीन सत्र में होगी। पोस्ट कोड 723 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा 20 अक्तूबर को सुबह तथा पोस्ट कोड 738 फिटर की परीक्षा सायंकालीन सत्र में होगी। पोस्ट कोड 702 ग्रेड एक पब्लिसिटी असिस्टेंट की परीक्षा तीन नवंबर को सुबह, पोस्ट कोड 675 ग्रेड दो पब्लिसिटी असिस्टेंट की परीक्षा पांच नवंबर को सुबह, पोस्ट कोड 734 डिस्पेंसर की परीक्षा सायंकालीन सत्र में, जबकि पोस्ट कोड 742 तकनीकी सहायक की परीक्षा छह नवंबर को सुबह के सत्र में होगी। आयोग के सचिव डॉ. जितेंद्र कंवर ने बताया कि परीक्षा से पंद्रह दिन सभी अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

हिमाचल में राजस्व विभाग में 1195 पदों पर पटवारी भर्ती

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल सरकार ने पटवारियों की भर्ती के लिए आवेदन की तिथि निर्धारित कर दी है। पटवारियों के 1195 पद भरने के लिए राजस्व विभाग ने 30 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। 933 पटवारी के पद मुहाल में और 262 पद सेटलमेंट विभाग में भरे जाएंगे। 18 से 45 वर्ष की आयु वाले भर्ती के लिए पात्र होंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 5 साल की छूट मिलेगी। इस भर्ती में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

किस जिले में कितने पद

राजस्व विभाग के अनुसार बिलासपुर में 31, चंबा में 68, हमीरपुर में 80, कांगड़ा में 220, किन्नौर में 19, शिमला में 174, मंडी में 115, सिरमौर में 52, सोलन में 63, ऊना में 69 पटवारियों के पद भरे जाएंगे। आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन पदों पर आवेदन के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता बारहवीं पास रखी गई है। सामान्य श्रेणी को 300 और आरक्षित वर्ग को 150 रुपये की फीस चुकानी होगी। आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए मुहाल के 89 पद आरक्षित रखे गए हैं। सेटलमेंट के 262 में से 26 पद आर्थिक तौर पर कमजोर अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन संबंधित जिला उपायुक्त के कार्यालय में जमा करवाना होगा।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

मांगों को लेकर मिड-डे-मील वर्कर्स यूनियन तल्ख

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

मिड-डे-मील वर्कर्स यूनियन ने बुधवार को सीआईटीयू के बैनर तले मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। यूनियन के पदाधिकारियों ने मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भी भेजा। यूनियन के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की कि मिड-डे-मील वर्कर्स को न्यूनतम वेतन 7500 रुपये दिया जाए। इसके अलावा 10 माह का वेतन 12 माह का करने और सभी मीड-डे-मील वर्कर्स को नियमित करने की मांग की है। यूनियन के पदाधिकारियों ने स्कूलों में 25 छात्रों की शर्त को हटाने की मांग की है।

मीड-डे-मील वर्कर्स यूनियन ने सरकार से मांग की कि मिड-डे-मील वर्कर्स को सभी संवैधानिक अवकाश आकस्मिक अर्जित और मेडिकल अवकाश देने तथा महिला वर्कर्स को वेतन सहित प्रसूति अवकाश देने की मांग की है। यूनियन ने सरकार से मिड-डे-मील योजना में केंद्रीय किचन खोलने, योजना को ठेके और एनजीओ को देने के फैसले को वापस लेने की मांग की है। यूनियन ने 45वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक मिड-डे-मील वर्कर्स को दर्जा देने और ग्रेज्यूटी, पेंशन तथा ईपीएफ योजना को लागू करने की मांग की। इसके अलावा बंद किए जा रहे स्कूलों के मीड-डे-मील वर्कर्स स्टाफ की तरह अन्य स्कूलों में नौकरी देने की मांग की है।

स्मार्ट क्लासेज ने बदली तस्वीर, 65 से 106 तक पहुंची बच्चों की संख्या

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

काम के प्रति समर्पण, सहयोगी शिक्षकों, समाज और विद्यार्थियों की सहभागिता किसी भी अध्यापक की सफलता का मूल मंत्र है। यह कहना है राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले जिला ऊना के नारी प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक सितेंद्र कुमार मिन्हास का उन्होंने पुरस्कार को सामूहिक प्रयास का नतीजा बताते हुए सभी सहयोगियों को इसका श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि 18 अप्रैल, 1992 को राजकीय प्राथमिक पाठशाला धमांधरी में बतौर नियमित शिक्षक ज्वाइनिंग के बाद से उनका हमेशा प्रयास रहा कि सहयोगियों के साथ समाज के सहयोग से विद्यालय में आदर्श बनाया जाए। वहां पढ़ने वाले बच्चों को उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप अधिकतम लाभ मिले। बच्चों को शिक्षण में रुचि हो इसके लिए उनके साथ एक स्नेहपूर्ण बर्ताव भी इसकी एक कुंजी है। उन्होंने बताया कि स्कूल में स्मार्ट क्लास रूम बनाया गया है। इसमें पचपन इंच की एलईडी स्क्रीन के माध्यम से बच्चों को नई तकनीक से पढ़ाया जाता है। टीचिंग लर्निंग मैटीरियल को मॉडल बनाकर उसके माध्यम से विषय को समझाया जाता है। जैसे कि सोलर सिस्टम का मॉडल बनाकर बच्चों को ग्रहों की जानकारी देने पर वह बेहतर समझ पाते हैं और यह याद भी रहता है। स्कूल में सहयोगी स्टाफ सदस्यों और कम्यूनिटी के सहयोग से रसोईघर के लिए फ्रिज, स्मार्ट क्लास रूम के लिए एलईडी, डीटीएच कनेक्शन, स्मार्ट क्लास रूम में बच्चों की शिक्षा और अभिरुचि को ध्यान में रखकर कलर्ड पिक्चर्स, स्कूल में सीसीटीवी कैमरे और कम्यूनिटी के सहयोग से फ्लोर टाइल्स लगाई गई हैं। इसका नतीजा है कि लगभग चार वर्ष पहले जिस स्कूल में बच्चों की संख्या पैंसठ थी, वहां आज 106 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

करोड़ों की ठगी करने का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

एसएमएस कर घर बैठे हर माह एक आईडी पर पांच हजार कमाने का झांसा देकर जिले में सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी करने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने एक साल बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने सर्विलेंस के आधार पर मुख्य आरोपी प्रवीण उर्फ मोहित को हरियाणा के मुरथल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से एक फार्च्यूनर गाड़ी और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। आरोपी के फोन से ठगी से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। इससे पहले पुलिस ने ठगी के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ठीक एक साल बाद पुलिस ने ठगी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि करीब 2 साल पहले ऊना में इंडिया एडवटाइजमेंट सर्विस के नाम से एक कंपनी शुरू हुई। लोगों को एंड्रॉइड एप्प के जरिए एसएमएस भेजकर पैसे कमाने का लालच दिया गया।ऊना ही नहीं बल्कि हिमाचल, पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों के हजारों लोगों ने कंपनी के झांसे में आकर करोड़ों रुपये की कमाई उक्त कंपनी पर लुटा दी। लोगों को ठगी का पता तब चला जब चार सितंबर 2018 को कंपनी ऊना का ऑफिस बंद करके फरार हो गई। इसके बाद ऊना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंपनी से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया था। कंपनी के एमडी और मुख्य आरोपी प्रवीण उर्फ मोहित ने हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली। पुलिस ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और हाईकोर्ट ने प्रवीण की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद से ही आरोपी अंडर ग्राउंड रहा। उसकी तलाश में ऊना पुलिस ने कई राज्यों में दबिश दी, लेकिन हर बार खाली हाथ ही लौटना पड़ा। पुलिस ने एक साल बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हरियाणा के मुरथल में दबिश देकर मुख्य आरोपी प्रवीण उर्फ मोहित को गिरफ्तार किया है।

कार्य में देरी करने वाले होंगे ब्लैक लिस्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने लोक निर्माण विभाग को विकासात्मक कार्यों में हो रही अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार पाए गए ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। वह बनाट पंचायत के फागू में आयोजित जन मंच की अध्यक्षता कर रहे थे। इस कार्यक्रम में 63 शिकायतें व मांगें प्राप्त हुई जिनमें से 20 का मौके पर निपटारा किया गया। डा. बिन्दल ने कहा कि जन मंच लोगों की शिकायतों एवं समस्याओं की सुनवाई के लिए एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है जिसका उन्हें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जन मंच के दौरान आने वाले प्रत्येक शिकायत एवं मांग पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने राजगढ़ क्षेत्र की सड़कों को पक्का करने के सभी मापदण्डों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जिनके लिए 18.87 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

सिरमौर के चार स्वास्थ्य खंडों में भरे जाएंगे आशा वर्करों के 13 पद

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सिरमौर की ओर से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आशा वर्करों के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की जाएगी। सीएमओ ने बताया कि स्वास्थ्य खंड राजपुर के पातलियों-2, पातलियों मालवा, शिवपुर, शिवा व नगर परिषद पांवटा के वार्ड नंबर 8 में एक-एक आशा वर्कर का पद भरा जाएगा। पच्छाद स्वास्थ्य खंड के खोजर नारब, बागर, करियुथ व अडवान, संगड़ाह स्वाथ्य खंड के तहत बड़ग व जरग और शिलाई स्वास्थ्य खंड के तहत आने वाले अजरौली व मानल में एक-एक पद भरा जाएगा।

आशा वर्करों के कुल 13 पद भरे जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 20 सितंबर शाम तीन बजे से पहले संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में वांछित दस्तावेज भेजना सुनिश्चित करें। इसके बाद आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि इस पद के लिए आवेदनकर्ता की उम्र 25–45 के बीच होनी चाहिए। शादीशुदा, विधवा, तलाकशुदा व पति से अलग रह रही महिला को वरीयता दी जाएगी। आवेदनकर्ता स्थानीय भाषा बोलने में निपुण हो। शहरी क्षेत्र से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आठवीं पास अनिवार्य है। राशन कार्ड, आधार कार्ड, दसवीं व आठवीं पास प्रमाण, चरित्र प्रमाण पत्र, एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल, शादीशुदा, विधवा व तलाकशुदा का प्रमाण पत्र की छाया प्रतियों के अलावा पोसपोर्ट साइज फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि आधे-अधूरे दस्तेवाज स्वीकार नहीं होंगे। विभाग की ओर से किसी भी समय रिक्तियों में फेरबदल किया जा सकता है। चयनकर्ता समिति के अध्यक्ष बिना कारण बताए किसी भी आवेदन को निरस्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालयों में संपर्क किया जा सकता है।

पांवटा में आईसीडीओएल परीक्षा केंद्र खोलने की मांग

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

श्री गुरु गोविंद सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय पांवटा साहिब में वर्ष 2015 से मास्टर डिग्री की कक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं। लेकिन, चार वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक सैकड़ों विद्यार्थियों को आईसीडीओएल और निजी परीक्षाएं देने 45 से 50 किमी दूर नाहन कॉलेज परीक्षा केंद्र में जाना पड़ रहा है। कई युवा निजी इकाइयों में नौकरी कर अपनी शिक्षा जारी रख रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों को आर्थिक चपत के साथ समय की भी बरबादी होती है। इसलिए, पांवटा साहिब कॉलेज में ही परीक्षा केंद्र शुरू करने की मांग उठने लगी है। गिरिपार और पांवटा क्षेत्र निवासी कपिल ठाकुर, अनुज कुमार, अमित चौहान, रवि तोमर, गणेश शर्मा, राहुल शर्मा, सपना तोमर, प्रिया ठाकुर, रितु चौधरी, पूनम शर्मा और दिनेश कुमार का कहना है कि पांवटा और गिरिपार क्षेत्रों के विद्यार्थियों को ज्यादा परेशानी हो रही है। पांवटा कॉलेज में संचालित केंद्र में एमए, एम-कॉम और एमएससी करने वाले युवाओं को काफी परेशानी होती रही है। आईसीडीओएल और निजी शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं, जिनको घर की आर्थिक तंगी के चलते पार्ट टाइम, फुल टाइम, प्राइवेट फर्म या किसी निजी कंपनी में नौकरी करनी पड़ रही है। युवाओं का कहना है कि नियमित विद्यार्थियों की परीक्षाएं वर्ष-2015 से होती आ रही हैं।

इसलिए प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन को कोई भी अतिरिक्त प्रबंध नहीं करना पड़ेगा। आईसीडीओएल और निजी परीक्षा का पांवटा कॉलेज में केंद्र शुरू कर यहां के सैकड़ों विद्यार्थियों की दिक्कतों को कम किया जा सकता है।

देश – विदेश में ऑनलाइन मिलेगी मशरुम की जानकारी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

किसानों को अब मशरूम उत्पादन से संबंधित जानकारियां ऑनलाइन मिल सकेंगी। खुंब अनुसंधान निदेशालय चंबाघाट ने ई-पोर्टल की सुविधा शुरू कर दी है। इसका विमोचन को निदेशालय चंबाघाट में आयोजित राष्ट्रीय मशरूम मेले के दौरान उप महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली डॉ. आनंद कुमार सिंह ने किया। इसमें अब किसानों और अन्य लोगों को मशरूम के उत्पादन सहित कारोबार से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को अहनलाइन निपटारा कर सकेंगे। खुंब निदेशालय चंबाघाट के निदेशक ने निदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट रखी। मेले में 17 राज्यों के करीब 1200 किसानों ने भाग लिया। इस मेले में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, चंडीगढ़, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर सहित अन्य राज्यों के किसानों ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्यातिथि डॉ. आनंद कुमार कंपोस्ट पास्चराइजेशन इकाई, प्रदर्शनी का उद्घाटन और पौधरोपण किया। डॉ. वीपी शर्मा ने उत्पादन कक्षों और एससीएसपी

योजना के तहत बने कम लागत मशरूम घर का भ्रमण करवाया। इस अवसर पर निदेशालय के वार्षिक प्रतिवेदन और पांच तकनीकी फोल्डरों जिनमें वर्ष भर के विभिन्न जलवायु में उगने वाली ढींगरी खुंब, बेट बबल बिमारी, कॉर्डी शेप्स उत्पादन और पंच फसल उत्पादन का विमोचन किया।

300 बिस्तरों का अस्पताल, 50 बिस्तर का होगा ट्रॉमा सेंटर

द रीव टाइम्स, सोलन

क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के लिए प्रस्तावित नया अस्पताल 350 बिस्तरों का होगा। इसमें 300 बिस्तर सामान्य अस्पताल में होंगे जबकि 50 बिस्तरों की क्षमता ट्रॉमा सेंटर में होगी। पांच सदस्यीय चयन समिति ने अस्पताल के इस खाके पर अपनी सहमति दे दी है। नए अस्पताल के लिए गठित पांच सदस्यीय कमेटी ने कथेड़ में प्रस्तावित क्षेत्रीय अस्पताल की जमीन का दौरा किया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग आवश्यकता अनुसार मिलने वाली सभी सुविधाओं का ब्योरा आर्किटेक्ट विभाग शिमला को भेजेगा। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल बनाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। भूमि की डिमार्केशन के लिए राजस्व विभाग को पत्र भी भेज दिया है। डिमार्केशन होने के बाद भूमि की चारों ओर से तारबंदी की जाएगी। इस अस्पताल को भूकंपरोधी और दिव्यांग फ्रेंडली बनाने का विचार स्वास्थ्य विभाग पहले ही कर चुका है। कथेड़ में बनाया जाने वाला अस्पताल 300 बिस्तरों का होगा। इसके साथ 50 बिस्तरों वाला ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने

बताया कि चयनित जमीन को लेकर गठित पांच सदस्यीय कमेटी ने जमीन को दौरा किया। बैठक में अस्पताल निर्माण के लिए आगामी योजना तैयार की गई। अब अस्पताल में सुविधाओं को लेकर आर्किटेक्ट विभाग को ब्योरा भेजा जाएगा।

पांवटा साहिब में नहीं चलेंगे ई – रिक्शा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

उत्तराखंड और हरियाणा की सीमा से सटे पांवटा साहिब में चलने वाले ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लग गया है। हिमाचल प्रदेश में ई-रिक्शा के पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण यह कदम उठाया गया है। हालांकि, विभाग ने पंजीकरण के लिए नीति बनाने के बारे में सरकार को पत्र भेजा है। विभाग ने ई-रिक्शा संचालकों को उन राज्यों में पंजीकरण कराने का सुझाव दिया है, जहां पर इसका प्रावधान है। इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है, तब तक पांवटा साहिब में ई-रिक्शा नहीं चलेंगे। परिवहन विभाग जिला सिरमौर की ओर से पांवटा साहिब में लोगों को नए मोटर वाहन अधिनियम के बारे में जागरूक करने के लिए वीरवार को जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान आरटीओ सिरमौर ने ई-रिक्शा संचालकों को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। आरटीओ सिरमौर के मुताबिक पांवटा में 400 से 500 ई -रिक्शा चल रहे हैं। एक सप्ताह का समय ई-रिक्शा संचालकों को दिया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पंजीकरण संबंधित प्रदेशों में करवाने के लिए कहा गया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इनके लिए अभी कोई पॉलिसी ही नहीं बनी है। प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग को इनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम करने को पत्र भेजा गया है। पॉलिसी नहीं बनने तक पांवटा में ई-रिक्शा संचालन बंद रखा जाएगा। आरटीओ ने कहा कि नए ट्रैफिक नियमों से घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे नियमों को मानवीय जीवन बचाने के उद्देश्यों से बनाया गया है। इस अवसर पर रोड सेफ्टी क्लब अध्यक्ष भजन चौधरी व सुनील चौधरी, सिरमौर एजूकेशन सोसायटी सचिव एनएम वर्मा, एनपीएस नारंग, हिप्र शिक्षा बोर्ड से संबंधित निजी स्कूल संघ के प्रधान एमएस राठौर, सचिव अक्षय शर्मा, सिरमौर निजी बस ऑपरेटर यूनियन के प्रधान मामराज शर्मा, सचिव अखिल शर्मा, ऑटो यूनियन चेयरमैन जगजीत सिंह, प्रधान आशिक अली, सुनील चौधरी और पंचराम आदि मौजूद रहे।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

इन्वेस्टर मीट से पहले युद्ध संग्रहालय खोलने की तैयारी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

सूबे का पहला युद्ध संग्रहालय धर्मशाला में नवंबर महीने में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से पहले लोगों के लिए खुल सकता है। इसके लिए जिला प्रशासन व युद्ध संग्रहालय की समिति ने अपनी ओर से पुरजोर तैयारियां शुरू की हैं। उपायुक्त राकेश प्रजापति की अध्यक्षता में युद्ध संग्रहालय के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें विभिन्न युद्धों के इतिहास के बारे में स्क्रीन डिस्प्ले तथा क्योसक के माध्यम से लोगों को जानकारी देने की योजना बनाई गई। इसके लिए युद्ध संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर क्योसक मशीन स्थापित की जाएगी। साथ ही इसी महीने भारतीय वायु सेना के विजयंता टैंक को युद्ध संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एयरक्राफ्ट के 22 के करीब मॉडल नेवल शिप की पेंटिंग भी स्थापित करने पर भी विचार किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि 21 परमवीर चक्र विजेताओं को लेकर एक डिस्प्ले बुक भी तैयार की जा रही है। युद्ध संग्रहालय को अनूठा स्वरूप देने के लिए सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों, विशेषज्ञों तथा अन्य लोगों का सहयोग लिया जा रहा है। इसके लिए एक कोर कमेटी भी गठित की गई है। यहां देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी चीजों और सैन्य साजो सामान की प्रदर्शनी वाला संस्थान होगा। इसके अलावा विभिन्न रेजिमेंट्स जहां पर हिमाचली सैनिक तैनात हैं, उन रेजिमेंट्स के एनक्लोजल भी म्यूजियम में स्थापित किए जाएंगे। इसे ऐसी जगह विकसित किया जा रहा है जहां लोग सैनिकों तथा राष्ट्र की सुरक्षा में किए गए असाधारण प्रयासों के प्रति सम्मान व्यक्त करेंगे।

कृषि विकास अधिकारी कार्यालय के टूटे ताले

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

स्वारघाट स्थित कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में चोरों ने ताले तोड़ कर अंदर रखे सामान को उड़ा लिया। चोरों ने कुछ दिन पहले रात के समय वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी अगले दिन सुबह लगी जब कर्मचारी कार्यालय में पहुंचे। इधर, पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कृषि विकास कार्यालय स्वारघाट के कर्मचारी जब सुबह अपनी ड्यूटी पर आए तो उन्होंने कार्यालय व स्टोर के तीन ताले टूटे हुए देखे। कार्यालय व स्टोर सामान बिखरा हुआ पड़ा था। बता दें कि जहां चोरी की वारदात हुई है यह कार्यालय एसडीएम व बीडीओ कार्यालय के साथ सटा हुआ है तथा नेशनल हाईवे चंडीगढ़ - मनाली के सड़क किनारे पर है। उपरोक्त सारे घटनाक्रम की सूचना कृषि विकास अधिकारी प्रताप सिंह चंदेल ने स्वारघाट पुलिस थाने में जाकर दी है। सूचना के बाद स्वारघाट पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य जुटा कर कर्मचारियों के बयान भी कलमबद्ध किए हैं। बताया जा रहा है कि घटना की रात को कृषि विकास अधिकारी कार्यालय के कमरों व स्टोर में हुई चोरी की घटना में तीन हहर्स पावर 2 इलेक्ट्रिक मोटरें जिनकी सब्सिडी पर कीमत साढ़े आठ हजार हैं, जबकि बाजार में इन दोनों की कीमत बीस हजार से भी ऊपर है। इसके साथ हो अज्ञात चोरों ने 5 टूल किट चोरी किए हैं जिनकी कीमत 7 हजार बताई गई हैं। कृषि विभाग में सब्सिडी के कारण ये किसानों को कम कीमत पर सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा स्टोर में रखा हुआ सब्जी आदि का बीज भी चोरी हुआ है। डीएसपी नयनादेवी संजय शर्मा ने चोरी की घटना की पुष्टि की है।

दो महीने में तैयार होगी बिलासपुर में एम्स की आयुष ओपीडी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने हाल ही में डाक विभाग महानिदेशक मीरा हांडा और सदर के विधायक सुभाष ठाकुर के साथ निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद उन्होंने बताया कि एम्स वर्ष 2022 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। आयुष ओपीडी दो महीने में तैयार हो जाएगी जबकि अन्य सभी ब्लॉक भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। एम्स के भीतर बस स्टैंड, छात्र और छात्रा हॉस्टल की सुविधा भी मिलेगी। प्रीति सूदन ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान उन्हें मैप दिखाकर एम्स का विवरण दिया गया। इस दौरान विधायक सुभाष ठाकुर भी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों को एम्स का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

जनमंच में मंत्री के सामने जमकर हंगामा, उलझे रामलाल और रणधीर शर्मा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

बिलासुपर के दयोथ में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा उस समय हुआ जब हाईवे का मुद्दा जनमंच में चल रहा था। उसी समय श्री नयनादेवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने मुद्दा उठाया कि नेशनल हाईवे की हालत खराब है। जबकि अन्य सड़कें भी सफर करने लायक नहीं रह गई हैं। हालत ऐसी है कि सेब और सब्जी की गाड़ियां समय पर मंडियों में नहीं पहुंच पा रही हैं। इस पर भाजपा के पूर्व विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि रामलाल ठाकुर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसके बाद रामलाल ठाकुर ने पूछा कि बताएं हाईवे की हालत सुधारने के लिए कितना बजट आया? इस पर विभाग का कोई भी अधिकारी जवाब नहीं दे पाया। वहीं गुस्साएं लोगों ने भाजपा के पूर्व विधायक रणधीर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान मंत्री मंच पर मौजूद थीं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि जनमंच में शिकायतें लेकर पहुंचे लोगों को उपायुक्त बिलासपुर के पास समस्या लेकर जाने को कहा जा रहा है। अगर उपायुक्त ने ही समस्या का समाधान करना है तो फिर सरकार के जनमंचों का क्या औचित्य है? उन्होंने जनमंच में सवाल उठाए तो पूर्व विधायक रणधीर शर्मा मंत्री का बचाव करने लगे। इस कारण गुस्साए लोगों ने जनमंच में जम कर नारेबाजी की। इधर, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व श्री नयनादेवी के विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि जन मंच में सड़कों के मरम्मत करने के कार्य का मुद्दा उठा था। इसके बाद कांग्रेस विधायक बोल पड़े कि बजट नहीं है। उन्होंने बताया कि नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर एस्टीमेट बनाकर भेज दिए गए हैं। इसके लिए केंद्र से भी पैसा आएगा और थोड़ा पैसा उपायुक्त के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। फिर विधायक भड़क उठे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा द्वारा करवाए जा रहे विकास को हजम नहीं कर पा रही है।

इन्वेस्टर मीट में आएंगे पीएम मोदी, अमित शाह को भी दिया न्यौता

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

नवंबर माह में धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे।

वहीं हिमाचल सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह को भी इस निवेशक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। अगर सब ठीक रहा तो 8-9 नवंबर को धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि निवेशक सम्मेलन में अधिक से अधिक इन्वेस्टर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं इसके लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि नवंबर माह में होने वाली इन्वेस्टर मीट में 80 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला-मैक्लोडगंज में बनने वाले रोप-वे का निर्माण कार्य अगले साल मई-जून माह में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य को इस वर्ष दिसंबर माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में यह संभव नहीं हो पाया है। इसके चलते अब रोप-वे के निर्माण कार्य को मई माह में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं उन्होंने कहा कि हिमानी चामुंडा-डाढ रोप-वे का पहला चरण भी पूरा हो चुका है। जल्द ही इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

अब ऑनलाइन भरने होंगे प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंक

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की मार्च - 2020 में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक अब ओएमआर शीट में भरकर नहीं भेजे जाएंगे। अब विद्यालयों को प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक ऑनलाइन भरने होंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ओएमआर शीट पर प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक भरकर भेजने की पद्धति को समाप्त कर दिया है। मार्च - 2020 से ऑनलाइन ही अंक भेजे जाएंगे। इस संबंध में बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड के इस फैसले से जहां प्रैक्टिकल परीक्षाओं की गोपनीयता बनी रहेगी, वहीं इसमें तेजी भी आएगी। इससे पूर्व ओएमआर शीट में प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंक भरकर भेजे जाते रहे हैं। अध्यापक डाक के माध्यम से बोर्ड कार्यालय को इसे भेजते थे। कई बार डाक के माध्यम से ओएमआर से भेजे गए अंकों को मिलने में भी देरी होती थी। उधर, राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि मार्च - 2020 से दसवीं और जमा दो की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंकों को ओएमआर शीट में भेजने की बजाए स्कूल के यूजर आईडी के माध्यम से ऑनलाइन भेजने की व्यवस्था की गई है। प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंकों को स्कूल के यूजर आईडी के माध्यम से भेजने के लिए दूरस्थ क्षेत्र के स्कूलों को छूट रहेगी। निर्धारित तिथि तक यदि स्कूल में इंटरनेट व्यवस्था न होने से यदि प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंक ऑनलाइन नहीं जमा करवा पाएंगे तो ऐसे स्कूल सामान्य पत्र में अंक सूची तैयार कर बोर्ड कार्यालय को भेज सकेंगे।

सऊदी अरब में आठ साल से बंधक विजय की नहीं हुई वतन वापसी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

नगरोटा बगवां के रौंखर गांव का विजय आठ साल से सऊदी अरब में बंधक की जिंदगी काट रहा है। बेटे की वतन वापसी के लिए परिजन मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक को अपना दुखड़ा सुना चुके हैं। इसके अलावा पीएमओ में भी पत्राचार कर चुके हैं। अभी तक आश्वासन ही मिले हैं। विजय कुमार के भाई अजय कुमार ने बताया कि उनका छोटा भाई 2011 में सऊदी अरब की एक कंपनी में कार्य करने के लिए गया। इस दौरान उसे वहां पर लोडर ऑपरेटर का काम सौंप दिया गया। उसके पास इसका कोई न तो लाइसेंस था और न ही अनुभव। विजय ने मेहनत से इस कार्य को बखूबी निभाया। इसी बीच 2013 में उसके बांग्लादेश के साथी की लोडर से गिर कर मौत हो गई। इसके बाद वहां की पुलिस उसे पकड़ कर ले गई और करीब 20 दिन बाद उसे छोड़ दिया गया। जब विजय का कंपनी के साथ तीन वर्ष का करार खत्म हुआ तो उसने घर जाने की इच्छा जताई। इस पर कंपनी ने उसे छह माह तक कार्य करने के लिए कहा। इसके बाद छह माह बीतने के बाद उसने पुन घर आने के लिए कहा, लेकिन कंपनी ने उसे वापस नहीं भेजा। कंपनी प्रबंधन ने कहा कि उस पर केस चला हुआ है, जिसके चलते उसे घर नहीं भेजा जा सकता। इसके बाद विजय ने भारतीय दूतावास से संपर्क किया और अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन वहां से भी उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसके बाद कंपनी प्रबंधन ने उसे बांग्लादेश दूतावास से क्लीन चिट्ट लाने को कहा, लेकिन यह क्लीन चिट्ट उसे अभी तक नहीं मिली है।

किराये में दो रुपये अतिरिक्त वसूलने पर एचआरटीसी को आठ हजार हर्जाना

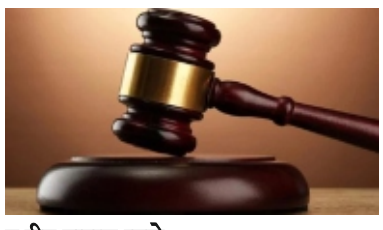

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल पथ परिवहन निगम के बस परिचालक को यात्री से दो रुपये अतिरिक्त वसूलना महंगा पड़ गया। जिला कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष भुवनेश अवस्थी, सदस्य कंचन बाला और अधिवक्ता सुशील शर्मा ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए एचआरटीसी को अतिरिक्त किराया राशि को 9 फीसदी ब्याज समेत लौटाने और आठ हजार रुपये बतौर हर्जाना देने का फैसला सुनाया है। गांव बढेड़ा, सब तहसील कांगू उपमंडल नादौन जिला हमीरपुर निवासी जमना दास अग्निहोत्री ने इस मामले की शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम हमीरपुर में की थी। अग्निहोत्री ने शिकायत में कहा था कि 22 जून 2018 को वह झनियारी से कांगू वाया रंगस के लिए चलने वाली एचआरटीसी हमीरपुर डिपो की बस में सवार हुआ। इस दौरान बस परिचालक ने उसे 13 किलोमीटर के लिए 21 रुपये वाला टिकट थमा दिया। यात्री ने विरोध करते हुए कहा कि सफर की कुल दूरी 12 किमी है, जिसका किराया 19 रुपये बनता है। लेकिन कंडक्टर ने कहा कि जो इलेक्ट्रानिक टिकट मशीन में दर्ज है, उसी के मुताबिक किराया वसूला जाएगा। इसके बाद 2 जुलाई 2018 शिकायकर्ता अपनी पत्नी और दोहती के साथ दोबारा निगम की बस में सवार हुआ। इस दौरान यात्री से पांच रुपये अतिरिक्त वसूले गए। 2 अगस्त 2018 को तीसरी बार अतिरिक्त किराया के रूप में कुल 10 रुपये वसूले गए। जमना दास अग्निहोत्री ने क्षेत्रीय प्रबंधक एचआरटीसी हमीरपुर के खिलाफ इस मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर दी। जिस पर उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है।

अब भोरंज अस्पताल में भी होंगे अल्ट्रासांउड

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

सिविल अस्पताल भोरंज में को अल्ट्रासांउड मशीन का शुभारंभ विधायक कमलेश कुमारी ने किया। अब भोरंज अस्पताल में भी लोगों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलेगी। इससे पूर्व अस्पताल में कई माह से अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे थे। मरीजों को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए हमीरपुर या दिम्मी जाने को मजबूर होना पड़ता था। अब लोगों को अल्ट्रासाउंड के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा सुविधा गर्भवती महिलाओं को होगी। इस अवसर पर विधायक ने लोगों को बधाई दी और कहा कि लोगों ने उन्हें विधायक चुना है और उनकी सेवा ही उनकी प्राथमिकता है। अस्पताल के उत्थान के लिए उनके प्रयास लगातार जारी हैं ताकि, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी हर सुविधा मिल सके। विधायक के प्रयास से ही 100 बिस्तर सहित फर्स्ट रेफरल यूनिट का दर्जा मिला और इसके भवन का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है जोकि 11 करोड़ की लागत से बनेगा। अस्पताल की अन्य कोई भी जरूरत होगी तो उसका निदान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इस अवसर पर बीएमओ डह. ललित कालिया, अशोक ठाकुर, ग्राम केंद्र अध्यक्ष ज्ञान चंद, वीरेंद्र, अजय आदि उपस्थित रहे।

स्क्रब टायफस की चपेट में बच्चे, मेडिकल कॉलेज में दो मामले पॉजिटिव

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में स्क्रब टायफस के दो मामले पॉजिटिव निकले हैं। दोनों पीड़ित बच्चे है और अस्पताल में भर्ती हैं। शिशु रोग विभाग में बुखार और सिर दर्द से परेशान बच्चों की जांच के बाद स्क्रब टायफस निकला है। वहीं, तीन अन्य बच्चे जिन्हें तेज बुखार और सिरदर्द की शिकायत होने पर टांडा मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए रेफर कर दिया है। जबकि, उनके ब्लड सैंपल जांच के लिए हमीरपुर में ही लिए गए हैं। उधर, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के शिशु रोग विभाग ने बच्चों के स्क्रब टायफस पहजिटिव होने की जानकारी मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में दे दी है। विभाग ने स्क्रब टायफस से बचाव को पूर्व में एडवाइजरी भी जारी की है। मेडिकल कॉलेज में रंगस क्षेत्र का दो वर्षीय बच्चा और कैहडरू क्षेत्र की 13 वर्षीय बेटी स्क्रब टायफस से पीड़ित पाई गई है। चिकित्सकों ने लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

मनाली इन्वेस्टर्स मीट कनक्लेव में 1500 करोड़ के एमओयू साइन

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

पर्यटन में रुचि दिखाते हुए मनाली इन्वेस्टर्स मीट कनक्लेव में निवेशकों ने एक दिन में ही 1500 करोड़ के एमओयू पर्यटन के क्षेत्र में ही साइन किए। इसके तहत नए रिजॉर्ट और होटलों का निर्माण होगा, जो पर्यटन कारोबार के लिए मील पत्थर साबित होंगे। 1500 करोड़ के इस निवेश से न केवल मनाली के पर्यटन की तस्वीर बदलेगी, बल्कि यहां पर विश्व स्तर की सुविधाएं भी पर्यटकों को मिलेंगी। एमओयू के तहत मनाली सहित समूची घाटी में विभिन्न स्थानों पर कई रिजॉर्ट और होटलों का निर्माण होगा। मिनी इन्वेस्टर्स मीट में निवेशकों ने हर क्षेत्र में निवेश की खासी दिलचस्पी दिखाई। निवेशकों ने पर्यटन क्षेत्र के अलावा बागवानी, हाईड्रो, एडवेंचर, हथकरघा सहित अन्य क्षेत्रों में उद्योग लगाने की इच्छा भी जाहिर की। एक दिन में 1500 करोड़ के एमओयू साइन होने का मतलब है कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बावजूद हिमाचल पर्यटन की दृष्टि से निवेशकों की पहली पसंद है। मुख्यमंत्री ने उनकी योजनाओं को जल्द स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन दिया है।

पांच करोड़ से बस अड्डे का होगा कायाकल्प

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

बंजार बस अड्डे का लगभग पांच करोड़ की लागत से जल्द कायाकल्प होने जा रहा है। इसके लिए बस अड्डा प्राधिकरण शिमला की टीम ने हाल ही में को बंजार विधायक सुरेंद्र शौरी के साथ निरीक्षण किया। डीपीआर को मंजूरी मिलते ही बस अड्डे के नवीनीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ समय पहले वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने भी इसका निरीक्षण कर नवीनीकरण का खाका तैयार करने को कहा था। इसके बाद इस पर कार्य शुरू हुआ। बंजार विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान अड्डा प्राधिकरण शिमला के साथ बैठक का आयोजन कर बंजार बस अड्डे के नवीनीकरण को लेकर चर्चा की गई थी, जिसके लिए अड्डा प्राधिकरण की टीम शिमला से यहां पहुंची है। बस अड्डे में बारिश से पानी जमा होता है। उसका समाधान करने के बस अड्डे के साथ तीन मंजिला पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इसमें लगभग 150 वाहनों को खड़ा करने के साथ बसों को भी पार्क करने की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही दो सुलभ शौचालयों का निर्माण और इसके स्टाफ का भी प्रबंध किया जाएगा। बंजार बस अड्डे पर सुलभ शौचालय की सुविधा मिलने से जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अड्डा प्राधिकरण शिमला की टीम ने निरीक्षण कर लिया है। जल्द ही डीपीआर तैयार करवा कर लगभग पांच करोड़ की लागत से बंजार बस अड्डे का नवीनीकरण किया जाएगा।

जनमंच में 177 शिकायतों पर हुई सुनवाई, 72 मौके पर निपटाई

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मण्डी

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में हाल ही में जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के कोट हटली में जन मंच आयोजित किया गया। इस अवसर पर 177 शिकायतें एवं मांगे प्राप्त हुई जिनमें से लगभग 72 का मौके पर निपटारा कर दिया गया। सुरेश भारद्वाज ने लोगों का सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के कैंसर, पार्किनसन्स, पैरालाईलिस, थैलेसिमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, किडनी विकारों जैसी गम्भीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने सहारा योजना आरम्भ की है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने सम्बन्धित विभागों, विशेषकर राजस्व, पेयजल, विद्युत, कृषि और परिवहन निगम को लोगों द्वारा उठाई गई समस्याओं के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने लाभार्थियों को 67 गैस कुनैक्शन तथा अन्य प्रमाण - पत्र भी वितरित किए। विधायक कर्नल इन्द्र सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

चारकुफरी में बनेगी आधुनिक सब्जी मंडी, जल्द मिलेंगी हाइटेक सुविधाएं

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

किसानों और बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। चारकुफरी में जल्द ही अति आधुनिक सब्जी मंडी की सुविधा मिलेगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने एफसीए की मंजूरी के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही सब्जी मंडी का निर्माण आरंभ किया जाएगा। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन बलदेव भंडारी ने चारकुफरी में प्रस्तावित सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चुराग स्थित अस्थायी सब्जी मंडी और करसोग में बंद पड़ी सब्जी मंडी का भी जायजा लिया। करसोग में कई वर्षों से नीलामी के लिए बंद पड़ी सब्जी मंडी खंडहर में बदल गई है। मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन ने लोगों को इन दोनों सब्जी मंडियों की हालत सुधारने का भी भरोसा दिया। इस अवसर पर करसोग के विधायक हीरा लाल, एपीएमसी मंडी के चेयरमैन दलीप सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। दावा किया गया कि इस निर्माण से हजारों किसानों और बागवानों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। चारकुफरी में 13 बीघा भूमि पर आधुनिक सब्जी मंडी का निर्माण होगा। इसके लिए 13 बीघा भूमि का चयन किया गया है। यहां नीलामी यार्ड के अलावा किसानों के ठहरने के लिए रेस्ट रूम की भी व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त बाहरी मंडियों से आने वाले लदानियों के लिए भी ठहरने का प्रबंध रहेगा। इस सब्जी मंडी में सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

भूकंप के झटकों से कांपा चंबा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

भूकंप के झटकों से जिलावासी खौफजदा हैं। बीते 9 सितंबर को रात 9 बजकर 27 मिनट पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। इससे पूर्व 9 सितंबर की सुबह से लेकर दोपहर तक तीन बार इसी तरह के झटके महसूस हुए। रात के समय आए भूकंप के झटके की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2 मापी गई है।

भूकंप का केंद्र जम्मू - कश्मीर और चंबा जिला रहा। भूकंप के दिन भर झटकों से सहमे लोगों को रात में नींद उड़ी रही। लोग यहां रिश्तेदारों के यहां दूरभाष के माध्यम से जानकारी लेते रहे।

चालीस किमी दूर फल – सब्जियां बेचने को मजबूर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

बड़े पैमाने पर फल और सब्जी का उत्पादन करने वाली सैंज घाटी में सब्जी मंडी खोलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। घाटी में सब्जी मंडी न होने से फिलहाल किसानों-बागवानों को 40 किमी दूर टकोली स्थित सब्जी मंडी में अपने उत्पाद बेचने पड़ रहे हैं। लारजी सब्जी मंडी कई सालों से बंद पड़ी है। लारजी में सब्जी मंडी बंद होने के बाद घाटी के बागवानों के पास एकमात्र विकल्प टकोली सब्जी मंडी ही है। बंजार में इस साल से विधिवत सब्जी मंडी खुल चुकी है। ऐसे में अब सैंज सब्जी मंडी खुलने से घाटी के किसानों, बागवानों को फायदा मिलेगा। सैंज घाटी में किसान बड़े पैमाने पर टमाटर, मटर, बंदगोभी आदि सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा घाटी में सेब उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। उन्नत किस्म के सेब के पौधे लगाने के बाद घाटी से रोजाना दर्जनों जीपें टकोली सब्जी मंडी जा रही हैं। बागवान प्रेम ठाकुर, तारा सिंह, राजकुमार, हरफी राम, बालमकुंद, रमेश चौहान, देस राज, लगन चंद, रोशन लाल और नरेश कुमार ने कहा कि सब्जी मंडी दूर होने से किसानों पर किराये का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। किसान सभा के जिला इकाई अध्यक्ष नारायण चौहान ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को किसानों और बागवानों की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। दस वर्षों से सैंज घाटी में फल और सब्जियों की बंपर पैदावार हो रही है। लेकिन बागवानों को सब्जी मंडी की सुविधा न मिल पाने से बाहर मंडियों में जाना पड़ रहा है। इससे उत्पाद की लागत बढ़ रही है। अगर सैंज में सब्जी मंडी खुल जाती है तो इससे किसानों-बागवानों के समय और धन की बचत होगी। बंजार किसान मोर्चा के अध्यक्ष शेर सिंह नेगी ने कहा कि सैंज में सब्जी मंडी खोलने की आवश्यकता है। सरकार के समक्ष इस मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा। इस संबंध में एपीएमसी कुल्लू के अध्यक्ष अमर ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। जिले में सैंज सहित कई अन्य जगहों पर सब्जी मंडी खोलने की योजना चल रही है।

खजियार झील में बन रही गाद का समाधान निकालेंगे वैज्ञानिक

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से विख्यात पर्यटन स्थल खजियार स्थित झील में बढ़ रही गाद का समाधान निकालने के लिए वैज्ञानिकों की टीम आज पहुंचेंगी। यह टीम तीन दिनों तक खजियार में यह जांच करेगी कि झील में गाद क्यों बढ़ रही है? इसके साथ ही झील के जीर्णोद्धार के लिए अपने सुझाव रिपोर्ट के माध्यम से तैयार करेगी। ऑल इंडिया रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तीन विज्ञान यह रिपोर्ट तैयार करेंगे और विभाग के उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे। इसके बाद झील से वैज्ञानिक तरीके से गाद निकालने का कार्य शुरू किया जाएगा।

ताकि खजियार झील की सुंदरता पहले की तरह कायम रहे। इसको लेकर हाल ही में एसीएफ चंबा संजय सिंह और वन्य प्राणी विभाग के उप मंडलाधिकारी राजीव कुमार ने खजियार झील का दौरा किया। इस दौरान झील में चारों ओर बढ़ रही गाद को लेकर भी चरचा की। झील के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए विभाग ने उच्च स्तरीय प्रयास करने पर रणनीति तैयार की गई। अधिकारियों ने बताया कि गाद को रोकने के लिए लिए मौके पर टीम पहुंची। खजियार झील से गाद निकालने और सौंदर्यीकरण के लिए 48 लाख का बजट विभाग के पास है। लेकिन विभाग ने अभी यह बजट खर्च नहीं किया है। विभाग वैज्ञानिक ढंग से गाद को निकालने और झील का सौंदर्यीकरण करवाना चाहते है। पर्यटन स्थल खजियार की सुंदरता को जहां देवदार के पेड़ शोभा बढ़ाते है तो वहीं झील भी सुंदरता पर चार चांद लगाती थी। लेकिन वर्तमान में झील गाद से भर रही है। ऐसा पिछले करीब डेढ़ दशक से हो रहा है। इस वजह से झील का दायरा लगातार सिकुड़ता जा रहा है। वन्य प्राणी विभाग के उपमंडलाधिकारी राजीव कुमार ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि विभाग झील के संरक्षण के लिए प्रयास कर रहा है। झील से गाद निकालकर झील को पहले की तरह सुंदर बनाया जाएगा।

एक करोड़ रुपये की राशि से तैयार होगा सलूणी में हेलीपैड

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

डलहौजी की ग्राम पंचायत सिंगाधार के कुंडी गांव में हेलीपैड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग यह कार्य करवाया जा रहा है। हेलीपैड निर्माण पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। जबकि शेष चालीस प्रतिशत कार्य दो माह के भीतर पूरा करने का दावा लोक निर्माण विभाग मंडल सलूणी के अधिशाषी अभियंता ने किया। हेलीपैड का निर्माण होने के बाद सीएम दिसंबर माह में सलूणी में पहली बार लैंड करेंगे। सरकार ने यहां हेलीपैड का निर्माण करने का मकसद क्षेत्र की दार्शनिक स्थलों तक पर्यटकों को पहुंचाना है। जानकारी के अनुसार हेलीपैड के निर्माण से जहां क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं, दूसरी तरफ बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साधन भी जुटेंगे। सरकार ने विभिन्न जिलों में पर्यटन को विकसित करने के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू की है। सलूणी में हेलीपैड का निर्माण होने के बाद सरकार क्षेत्र को भी इस योजना के तहत शामिल करेगी। इससे सरकार को जहां आमदनी होगी, तो वहीं क्षेत्र का पर्यटन व्यवसाय भी निखरेगा। वर्तमान में जिले के हर क्षेत्र में हेलीपैड का निर्माण हुआ है। जबकि सलूणी ही एक ऐसा क्षेत्र था, जहां हेलीपैड की दरकार थी। अब सरकार ने इस मांग को पूरा कर दिया है। इससे क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। स्थानीय निवासी रमेश कुमार, सुरेंद्र सिंह, प्रवीण कुमार, राजकुमार, उमेश कुमार ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और जिला भाजपा अध्यक्ष डीएस ठाकुर का आभार जताया है। लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हेलीपैड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

आईपीएच ने बंद किया पुलिस थाने का पानी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

पुलिस थाना पतलीकूहल में पिछले सप्ताह से पेयजल सप्लाई ठप है। इससे पुलिस कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। थाना में पुलिस कर्मियों के अलावा यहां रखे गए कैदियों को भी पानी की सप्लाई नहीं मिलने से दिक्कत हो रही है। पानी की सप्लाई को बंद करने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आईपीएच के एक अधिकारी की गाड़ी का चालान काटा था। इसके बदले में पुलिस थाने का पानी बंद करने की बात भी सामने आ रही है जबकि आईपीएच विभाग का कहना है कि पुलिस थाना पतलीकूहल का पिछले नौ माह से पानी का करीब 14 हजार रुपये बिल का भुगतान बकाया है। ऐसे में नियम के तहत सप्लाई बंद की गई है। हालांकि पानी की सप्लाई बंद करने को लेकर पतलीकूहल पुलिस ने कई बार आईपीएच विभाग से शिकायत कर बहाल करने की मांग की। लेकिन कोई पानी बहाल नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि पतलीकूहल पुलिस थाना के जवानों ने दो सप्ताह पूर्व सड़क पर बेतरतीब खड़े आईपीएच के अधिकारी के वाहन का चालान काट दिया था, क्योंकि इसकी वजह से जाम लग गया था। इसके कारण सेना के वाहनों की आवाजाई भी रुक गई थी। लिहाजा पुलिस ने आईपीएच अधिकारी के वाहन का चालान काट डाला। इसके कुछ दिन बाद से पतलीकूहल पुलिस थाना में पानी की आपूर्ति ठप हो गई।

सिंगाधार पंचायत में चल रही पेयजल किल्लत, ग्रामीण हुए परेशान

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

विकास खंड सलूणी की ग्राम पंचायत सिंगाधार में रहने वाले लोगों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। गांव को जिस पेयजल भंडारण टैंक से पानी दिया जा रहा है। वह अब पंचायत की आबादी के लिए आगे कम पड़ रहा है। पंचायत में 90 परिवार रहते हैं। जोकि कई दिनों से पेयजल किल्लत का सामना कर रहे हैं। पंचायत में सुबह के समय जो पानी की सप्लाई होती है। उससे सभी लोगों के घरों के बर्तन नहीं भर पाते। इस वजह से तीन या चार परिवारों को ही पर्याप्त पानी मिल रहा है। इसलिए ग्रामीणों ने आईपीएच विभाग से गांव के लिए नई पेयजल लाइन बिछाने की मांग की है। पंचायत प्रधान चतर सिंह, उपप्रधान हंसराज, ग्रामीण सुभाष कुमार, लेखराज, टेक चंद, चौन लाल, बिहारी लाल, दुनी चंद और रमेश कुमार ने बताया कि पंचायत के लिए पानी 35 किमी दूर स्थित पेयजल भंडारण टैंक से आता है। पेयजल टैंक और पंचायत के बीच में जो पेयजल लाइन डाली गई है। वहां से अन्य गांव को भी पानी की सप्लाई भी दी जा रही है। इसकी वजह से पंचायत में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने आईपीएच विभाग से पंचायत में चल रही पेयजल किल्लत का समाधान करने की मांग की है। आईपीएच विभाग के सहायक अभियंता आसीम ने बताया कि पंचायत के लिए नई पेयजल योजना का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने पर गांव के लिए नई पेयजल लाइन डाली जाएगी।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

कानून की यह जानकारी आपको बनाएगी जिम्मेदार और सजग नागरिक

भारत एक लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक प्रणाली में हर नागरिक को कुछ संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। चूंकि हर नागरिक को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, शिक्षा और जागरूकता के अभाव में बहुत सारे नागरिकों को अपने कानूनी अधिकार नहीं पता होते जिसकी वजह से हम परेशानी, भ्रष्टाचार और धोखेबाजी का शिकार हो जाते हैं।

1.आपके एल.पी.जी गैस कनेक्शन के साथ आपको 40 लाख रूपये तक की इंश्योरेंस स्वतः मिलती है। यानि खुदा-न-खास्ता यदि आपके गैस सिलिंडर में विस्फोट होता है तो आपको 40 लाख रूपये तक का मुआवजा मिल सकता है।

2.अगर आप किसी कंपनी द्वारा भेंट किये हुए तोहफे को स्वीकार करते हैं तो आप पर कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेने का मुकदमा चला सकता है। आजकल कंपनियों में लोगों को तोहफे भेजने की परम्परा बनती जा रही है। सरकार द्वारा इस तरह की परम्परा को खत्म करने के लिए वर्ष 2010 में एक कानून बनाया गया और इस कानून के मुताबिक अगर आप किसी कंपनी से किसी तरह का तोहफा लेते हैं तो उसको रिश्वत समझा जायेगा और आप पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है।

3. भारत में केवल महिला पुलिस अधिकारी के पास ही महिलाओं को गिरफ्तार करके सुरक्षित थाने में ले जाने का अधिकार होता है। अगर भारत में किसी महिला को पुरुष पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करके थाने में लेकर जाता है तो इसको अपराध माना जाता है और ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कानूनी कारवाई हो सकती है। अगर किसी महिला को रात के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे समय के बीच पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा जाता है तो उस महिला को अधिकार है कि वह पुलिस स्टेशन आने से मना कर सकती है।

4. इनकम टैक्स अधिकारियों या कर वसूल करने वाले अधिकारियों के पास आपको गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। अगर आप ने टैक्स नहीं दिया तो टी.आर.ओ के पास आपको गिरफ्तार करने का अधिकार होता है और उनकी अनुमति पर ही आप जेल से छूट सकते हैं। इस नियम का उल्लेख वर्ष 1961 के इनकम टैक्स एक्ट में किया गया है।

5. साइकिल चलाने वालों पर कोई मोटर व्हीकल एक्ट नहीं लागू होता। अगर आप रोजाना साइकिल चलाते हैं तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन साइकिल और रिक्शा नहीं आते।

6. महिलाएं, पुलिस को ई-मेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में महिलाओं को ऐसी सुविधा दी है जिनमें महिलाएं घर बैठे-बैठे अपनी शिकायत को ई-मेल के माध्यम से दर्ज करवा सकती हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

7. भारत में अभी भी बहुत सारे लोग लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी अपराध मानते हैं। भारतीय कानून के अनुसार लिव-इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है लेकिन लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष और महिला को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर लिव-इन रिलेशनशिप में बच्चे का जन्म होता है तो उसका माता-पिता की प्रॉपर्टी पर पूरा-पूरा अधिकार होगा।

8. राजनीतिक दलों के पास चुनाव के समय आप से वाहन किराए पर लेने का अधिकार होता है। अगर आप वाहन देने के लिए तैयार हैं तो चुनाव के समय राजनीतिक दल आपसे आपका वाहन किराए पर ले सकते हैं।

9. भारत में अगर आप पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से दिन में एक बार जुर्माना लग गया है तो आप पर पुलिस अधिकारी पूरे दिन फिर जुर्माना नहीं लगा सकते। उदाहरण के लिए अगर आप पर दिन में एक बार हेलमेट ना पहनने का चालान हो गया है तो रात तक आप बिना हेलमेट पहने घूम सकते हैं और ट्रैफिक अधिकारी आप पर जुर्माना नहीं लगा सकता।

10. आप के पास वस्तु की अधिकतम खुदरा मूल्य से कम कीमत देने का अधिकार होता है। आप दुकानदार से कोई वस्तु सौदे के साथ भी खरीद सकते हैं जैसे कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 रूपये है तो आप सौदा करके उस वस्तु को 90 रूपये में भी खरीद सकते हैं।

11. अगर कोई व्यक्ति आप से काम लेकर या आपसे पैसे उधार लेकर आपको भुगतान नहीं करता तो आप अदालत में उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारतीय अधिनियम के अनुसार अगर कोई आपको भुगतान नहीं दे रहा तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ अदालत में एप्लीकेशन लिख कर मामला दर्ज करवा सकते हैं। यह आपका कानूनी अधिकार होता है। आपके पास उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का तीन साल का समय होता है जिससे आप ने पैसे लेने हैं।

12. अगर आप सार्वजनिक जगह पर अश्लील गतिविधियां करते हैं तो आपको तीन महीने की सजा हो सकती है।

13. पुलिस का हैड-कांस्टेबल किसी ऐसे अपराध के लिए आपको दंड नहीं दे सकता जिसका जुर्माना 100 रुपये से अधिक हो। अगर आपने एक से अधिक कानून के नियमों का उलंघन किया तो आपका चालान किया जा सकता है।

14. वर्ष 1861 में बने पुलिस एक्ट के अनुसार भारत के हर राज्य का पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर रहेगा। अगर किसी जगह पर आधी रात को भी कोई अपराध या घटना होती है तो पुलिसकर्मी को यह कहने का कोई अधिकार नहीं होता कि वह ड्यूटी पर नहीं हैं क्योंकि पुलिस एक्ट के अनुसार पुलिसकर्मी बिना वर्दी के भी हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं।

15. वर्ष 1956 में बने हिंदू गोद और रखरखाव अधिनियम के अनुसार अगर आप हिंदू धर्म के हैं और आपके एक बच्चा है तो आप दूसरा बच्चा गोद नहीं ले सकते। अगर आपका कोई बच्चा नहीं है और आप बच्चा गोद लेना चाहते हो तो आपकी और बच्चे की उम्र में कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना आवश्यक है।

16. अगर पति पत्नी में सेक्स संबन्ध अच्छे नहीं हैं तो दोनों इस वजह को तलाक के सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार, आईआईआरडी, 94180 25649

आपका स्वास्थ्य हमारा परामर्श

बुखार (fever) क्या और उसका उपचार

बुखार को बहुत लोग रोग समझ लेते हैं, लेकिन यह एक चिकित्सकीय लक्षण है, जो विभिन्न प्रकार की शारीरिक बीमारियों के कारण प्रभाव में आता है। बुखार कान, फेफड़े, त्वचा, गले, मूत्राशय या गुर्दे से जुड़े संक्रमण, बीमारी के कारण हो सकता है। इसे ज्वर भी कहा जाता है, जिसमें शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होने लगता है।

बुखार के कारण

जीवाणु संक्रमण जैसे गले-नाक में सूजन, फ्लू, चिकनपॉक्स या निमोनिया, यूरिक इन्फेक्शन, टाइफाइड आदि।

आर्थराइटिस
दवाइयों का गलत प्रभाव
त्वचा संबंधी संक्रमण
सन स्ट्रोक
डिहाइड्रेशन
फेफड़े संबंधी बीमारी

बुखार के लक्षण

ठंड लगना
शरीर में कंपन
भूख न लगना

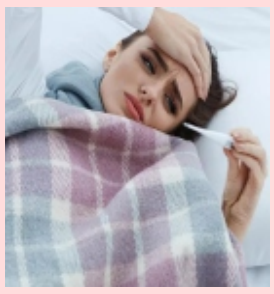

पसीना आना
शरीर में पानी की कमी
तनाव
हाइपरलेजेसिया (दर्द के लिए शरीर संवेदनशीलता बढ़ना)
सुस्ती
ध्यान केंद्रित करने में परेशानी

यदि आपका शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर बढ़ता है, तो आप बुखार से पीड़ित हैं। अपने स्थिति को गंभीर होने से बचने के लिए आपको पहले दिन से ही आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए।

सामान्य बुखार को ठीक होने में लगभग 3-8 दिन लग सकते हैं। अधिक गंभीर बीमारियों के मामले में, समय अवधि बढ़ सकती है।

डॉ0 के आर शांडिल
द रीव क्लिनिक, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें:hem.raj@iirdshimla.org

कैसे बन सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर

वर्तमान समय डिजिटल युग का है, इस डिजिटल युग में दिन-प्रतिदिन टेक्नोलॉजी का विस्तार होता जा रहा है, आज कल जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमारे देश में अधिकांश छात्रों की रूचि कंप्यूटर क्षेत्र में देखनें की मिल रही है, क्योंकि इस विस्तृत क्षेत्र में करियर की संभावनाए अधिक है, जैसे - कम्पूटर हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम आपरेटर आदि, यदि आप एक सहफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते है, तो, इसके बारें में आपको इस पेज पर विस्तार से बता रहे है।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कहते है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको कम्प्यूटर से सम्बंधित जानकारी के साथ-साथ कोडिंग तथा कंप्यूटर भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज HTML, CSS+, JAVA SCRIPT, C, C++ के माध्यम से ही सॉफ्टवेयर डेवलप किये जाते है।

शैक्षिक योग्यता

सॉफ्टवेयर इंजीनियर बननें के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12वीं विज्ञान वर्ग से 60 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग
बीसीए
बैचलर ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी

1.प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे

सहफ्टवेयर इंजीनियर बननें के लिए कंप्यूटर की भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, जैसे C लैंग्वेज , C++ , Java , पाईथन, सी शार्प इत्यादि, क्योंकि सॉफ्टवेयर का निर्माण इन्ही भाषओं के माध्यम से किया जाता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीसीए, बैचलर ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे डिग्री कोर्सेज में यह सभी भाषाए सिखाई जाती है।

C लैंग्वेज
C++ लैंग्वेज
Java लैंग्वेज
C शार्प लैंग्वेज

2. प्रोग्रामिंग लॉजिक पर विशेष महत्व

यदि आप एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाना चाहते है, तो इसके लिए आपको अपने लॉजिक को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि कंप्यूटर में बननें वाले सभी सहफ्टवेयर में लॉजिक लगाना होता है, इसके लिए बैचलर डिग्री जैसे की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको अलग से लॉजिक बिल्डिंग का कोर्स होता है, जिसकी सहायता से आप अपने लॉजिक को इम्प्रूव कर सकते है।

3.सॉफ्टवेयर बनाना सीखे

कंप्यूटर भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, आपको सॉफ्टवेर को बनाने का प्रयास करना चाहिये, इससे आपके अन्दर कोडिंग से सम्बंधित स्किल्स विकसित होगी और आप यह समझ पाऐंगे कि एक सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, तथा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

4. इंटर्नशिप करे

यदि आपने कंप्यूटर साइंस में डिग्री पूर्ण कर लिया है,इसके पश्चात आपको छोटे सॉफ्टवेयर बनाना आ गया, तो आपको किसी कंपनी में एक फ्रेशेर इंटर्नशिप के लिए जाना चाहिए, इससे आपको समझ पाएंगे कि सॉफ्टवेयर किस तरह बनता है ? और आपकी कोडिंग स्किल्स और अधिक इम्प्रूव होती चली जाएगी, इसके साथ ही आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अनुभव हो जायेगा।

5.कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री करे

आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजिनियर बनने के साथ-साथ अच्छी सैलरी भी प्राप्त करना चाहते है, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर में मास्टर डिग्री करना अति आवश्यक है। इसके लिए आप मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इत्यादि जैसे पाठ्यक्रम हेतु पढ़ाई कर सकते है।

सॉफ्टवेयर इंजिनियर बनने हेतु कोर्स

Software Courses Diploma in Web Hosting
Advanced Game Development Course Game Development Course
Data Bundle Course Joomla for Beginners
Database Basics Level 2 Certificate in Windows 7
Diploma in Cloud Computing Level 2 Certificate in Windows 8 OS
Diploma in Game Testing Programming and Database Course
Diploma in PC Security Programming for Beginners
Understanding Computer Virus Web Design Bundle Course
Video Creation Secrets Web Development Complete Course

सैलरी (वेतन)

प्राइवेट कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रारंभ में सैलरी 10 से 15 हजार रुपये प्राप्त होती है, अनुभव बढ़ने के आधार पर इसके वेतन में वृद्धि होती रहती है, तथा एक अच्छी कम्पनी में वेतन लगभग 42 से 80 हजार तक प्राप्त होता है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

MISSION RIEV IN THE CONTEXT OF FIT INDIA MOVEMENT

Fit India Movement launched by Prime Minister Narendra Modi on August 29, 2019 reminded us the bygone days of our village life where we used to spend days in forests with cattle grazing peacefully, occasionally used to plough the farmland, cut grass, harvest crops, carry the grass and crops on our back to home, construct small farm-based walls, work with masons and carpenters. Even the activities such as cutting tree branches in the forest for cooking purposes, getting dry leaves of pines for the cattle shed, and many more agrestic activities that we engaged in were wrought with pleasure.

The documentary shown during the live telecast on the launch of the Fit India Movement covered almost all the areas which we used to experience on a daily basis of our life in the village. The thoughts arose why such movements are needed when people in the villages are already exercising most of the things the Fit India Movement intends to promote. In fact, the worry of the nation is to make its people fit because "fit" means healthy citizens can have a sound mind and can contribute more effectively to the nation in terms of creating enterprises, adopting profession with more demands, put physical labour whenever required, create an environment for the betterment of all, and many more aspects required for holistic development, thereby contributing to the gross domestic product (GDP) of the country.

According to the recent studies, the contribution to our GDP is more from the urban areas and is estimated to around 75% by 2020. The lifestyle and food habits of people, especially belonging to the urban areas, are making them more prone to diseases and lethargic. People are living with obesity, high blood pressure, diabetes and a static mentale. This is all because of the absence of physical and mental exercises and this poses a big threat to our GDP if the remedial measures are not taken well in time.

PM Modi has been working equally on awakening the people through such thoughts, philosophies and initiations owning the responsibility to give direction to the nation being a leader at top pedestal.

The message of the Fit India Movement is perhaps more targeted to the urban population though it is the need of everyone, irrespective of their rural or urban milieu.

Walking every day should be made a part of our lives, if it does not go with our daily routine or the lifestyle. We need to take fibre-rich food which can be digested by our body easily and we need to indulge in some form of mental exercise like remembering the phone numbers without checking our mobile, do some calculations without the use of a calculator, etc. We need to exhaust slightly our body parts to support the body to generate sweat to flush out the toxins.

We need to have some time to play, have fun and relax, besides exchanging thoughts with others to supplement our mental food. We need to selflessly work with people, help our neighbours, which will act as a supplement or food for our soul and mind.

All these activities are naturally found in villages as a routine lifestyle, whereas special coaching and training are required in the city for getting all the above-mentioned attributes incorporated in our daily life.

Urban areas when given such exposer and orientation, as already available for the rural people, is the initiative of IIRD's flagship programme Mission RIEV which stands for "Ruralising India - Empowering Villages", launched in the year 2017. It does not mean to go against urbanisation, which is the need of the hour and is inevitable, but changing the lifestyle of urban population to make a bit rural-like, is the real meaning of "Ruralising India"; which very well fits within the framework of Fit India. Hence, Ruralising India is a preconceived notion of Fit India supplemented with "Empowering Villages" through facilitation support in different walks of life which makes Mission RIEV a wholesome concept. Thus, Mission RIEV envisages making India fit, healthy, progressive by engaging people to the maximum extent in different meaningful affairs for individual growth as well as national progress through the facilitation support.

Dr. L.C. Sharma
Editor in Chief
Mob.94180 14761, md@iirdshimla.org

THANK YOU M.A. JINHA

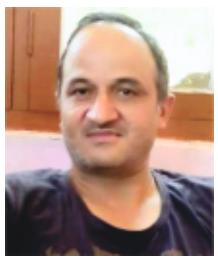

India by now would have been an Islamic Republic had Muslims not demanded a separate country in 1947. Al Utbi in his Tahreek-e-Yamini glorified India as "Golden Sparrow." Historical accounts substantiate that we had the most prosperous civilization making it vulnerable to plunders and repeated incursions. Soft targets always attract vicious onslaughts. Divided into small empires in absence of patron conglomeration capable of some sort of defiance, India fell prey to unsatiating lust of invaders for abounding riches of the subcontinent. Ming China took over India only in the 16th century as the richest region on earth. Till then India had testified a plunder of economy and culture for almost 10 centuries. Even totally devastated, India accumulated 25% of the world's total wealth five centuries ago. No doubt India was impoverished systematically but invaders successfully crippled the people of this country of their religious identities and Indianness. Foreign occupation in India for its wealth has not been as dangerous as was the onslaught on its culture and religion. Islamisation of India started at the break of the seventh century with Arab traders in southern India in the Malabar region. Nevertheless, series of attempts for Islamization of Indian subcontinent started with Muhammad bin Qasim in 712 AD to establishment of Mughal empire by Zahirudin Babur in 1526. Babur, an Uzbek, was the direct descendant of Amir Temur who had ravaged and plundered almost entire north-west India in 1398 AD. One after another Muslim invaders not just looted its riches but the attack on the indigenous religion and culture was more gruesome. It crippled the psyche of natives of the land irrevocably of their identities. Hindus, in particular, were forced to pay for their practice of religion. The imposition of 'jaziya' on those who had refuted religious conversion made them second-class citizens in their own homelands. Performance of Jauhar to protect their chastity for fear of rapes, abductions and conversions, though rarely touched on in our history books, today so as not to harm the communal fabric of the country. Indian Muslims are as remotely related to Babur or Temur, the way Indian Christians are to Macaulay or Curzon. Neither Muslims nor Christians are happy with their pre-conversion ancestry. Babur descended upon India with an army of 4 thousand soldiers of Uzbek origin. Which by any stretch of the imagination can not reproduce more than half a million Muslims within five centuries. Whereas the Indian subcontinent today comprises a Muslim population of more than 600 million, way above to comfort the claims of Indian Muslims of their Turkish and Arabic lineage. Once converted to Islam, they gave up all their affiliations to their forefathers. In the colonial era even, Indians on one side were battling for freedom, on the other hand, Muslims were more for the separate Islamic state. Alma Iqbal, the chief architect of the idea of Islamic Pakistan and two-nation theory was a grandson of a Hindu Brahmin of Kashmir, never felt comfortable with the religious identities of his forefathers. Same is with M.A. Jinha, a third-generation convert to Islam was instrumental in the amputation of the motherland into three pieces on religious lines. Most Indians though think otherwise and even today hold a lot against the idea of Pakistan but history teaches a different lesson. Hindu cleansing in Pakistan in the last seventy years compels us to think more rationally. Jinha, no doubt was vindictive towards Hindus, but his demand of Pakistan saved Hindus from total annihilation. In a sizable Muslim majority, the possibilities for coexistence evaporates and they start to rear the idea of Dar-ul-Islam. If twenty million Hindus were eliminated from Pakistan in the last seventy years, so were they forced conversions and exodus in a Muslim majority Kashmir. Evidently, imagining a united India by adding up four hundred million Muslims to present Indian population of India will not take long for Islamisation of the region. Thus we can safely conclude that the idea of Pakistan was an essentiality for Hindu existence. Neither Kashmir nor Palestine can be resolved given to Islamic teachings that promulgate the idea of Umma and the global caliphate. The only solution for Kashmir or Palestine is either to vacate every non-Muslim from there or to enforce the law with an iron fist. No matter how undiplomatic this may sound but Muslims in India or elsewhere in the world can coexist only if they are not allowed to outnumber non-Muslims.

Kamlesh Sharma, Shimla (HP)
(Guest Writer) 9817540956

लेखक के निजी विचार है, इसमें 'द रीव टाइम्स' की सहमति आवश्यक नहीं है

ऐ भाई ज़रा देख के चलाओ, आगे ही नहीं पीछे भी...

बड़ा देश, बड़ी सड़कें, बड़ी दुर्घटनाओं से बड़ी आबादी मौत के मुहाने पर

सरकार और नागरिक दोनों ही स्तरों पर सीख लेने की ज़रूरत

मेरा नाम जोकर फिल्म में मन्ना डे का एक गाना 'ऐ भाई ज़रा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी....' आज इस बात को तसदीक करता है कि सड़क सुरक्षा में हम जितने लापरवाह होते गए, ज़िंदगी हमसे उतनी ही दूर होती गई। आबादी बढ़ना किसी भी देश के लिए जनसंख्या लाभांश के प्रारुप को भी दर्शाता है लेकिन उसी टिड्डी दल सी आबादी में नियम-कायदे-कानून भी शिथिलता का आवरण ओढ़े रहते हैं । भारत विश्व का जनसंख्या के हिसाब से अभी दूसरा सबसे बड़ा देश है । भविष्य में नंबर एक का तमका भी हमसे दूर नहीं है । ऐसे में विकास की सबसे बड़ी दौड़ यहां सड़कों पर ही दौड़ी जाती है जिसे हम हमारी जीवन रेखा भी कहते हैं । आज भारत का संपूर्ण विकास इन्हीं जीवन रेखा पर टिका है । आज़ादी के बाद मीलों लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका है । जिस तादात में लोग वाहन खरीद रहे हैं, सड़कों का निर्माण भी भारत में उसी तेज़ी से हो रहा है । अब प्रश्न ये है कि क्या हम सड़क, सड़क सुरक्षा और कर्तव्यों में सामजस्य बिठा पा रहे हैं ? न हमें सड़क पर चलने की समझ है, न ही सड़क पर वाहन चलाने की समझ । स्वतंत्रता की भी ऐसी स्वतंत्रता अन्यत्र कहां ? हम सड़क को अपनी बपौती मान कर उस पर अधिकारवश कब्ज़ा जमाने की होड़ में अपराध में संलिप्त होते जा रहे हैं ।

सैंकड़ों ज़िंदगियों को सड़कें रोज लील रही

भारत में सड़क दुर्घटनाओं की फेहरिस्त रोज ही नई और लंबी होती जा रही है। औसतन 4,80,652 लाख दुर्घटनाओं में 1,50,000 लाख मौतें और तक़रीबन 5 लाख लोग घायल हो जाते हैं जो कि हैरान करने वाली बात है । एक सर्वे में रोज सड़क दुर्घटनाओं में 400 से अधिक लोग मारे जाते हैं । यानि किसी भी अन्य घटना जैसे युद्ध, बंब विस्फोट आदि में भी इतने लोग नहीं मारे जाते हैं । तो क्या सड़कें लील रही है ये ज़िंदगियां या इसमें हम भी कहीं पर स्वयं को जिम्मेवार मानते हैं ? सड़कों का निर्माण यदि हिमाचल के संदर्भ में कहें तो शिमला के ऊपरी इलाकों, किन्नौर, लाहौल-स्पिति आदि में तो तंग और जानलेवा सड़कें आज भी विद्यमान है । लेकिन शेष हिमाचल में आज खुली और चौड़ी सड़कों का जाल बिछता जा रहा है । ऐसे में वाहन की ओवरस्पीड, चालकों का ग़ैरजिम्मेदाराना रवैया और प्रशिक्षण के अभाव में सबकी ज़िंदगी दांव पर लग जाती है । सड़कों को भी पूरी तरह से सुरक्षित कहा जाए....यह भी उचित नहीं होगा । विशेष तौर पर जब बात पहाड़ी क्षेत्र के राज्यों की होती है तो सड़कें अपनी जटिलता और ख़ामियों के लिए हमेशा से ही भयावक रुप लिए हुए होती है । इसके बाद हमारी ज़ल्दबाजी और उतावलेपन की ड्राईविंग.....हमें मौत के मुंह में ले जा रही है । सड़कें तंग और कम चौड़ी है तथा लोग अपनी गाड़ियों की पार्किंग इन्हीं सड़कों के दोनों ओर करके आराम की नींद लेने पहुंच जाते हैं । अब विडंबना यह है कि न तो विभाग सड़कों को चौड़ी करने की योजना को सही प्रकार से क्रियान्वित कर रहा है और न ही लोग सड़कों से अपने मनमाने रवैये से पीछे हटने को तैयार हैं ।

सरकार की जिम्मेवारी तय नहीं

सड़क हादसों से देश सिहर उठा है । ऐसे में सरकार ने नया मोटर वाहन एक्ट जो कि पिछले एक्ट का परिष्कृत रुप ही है, ने देश भर में वाहन चालकों को सोचने पर मज़बूर कर दिया है । सोशल मीडिया पर जो भी जानकारी अभी तक प्राप्त हो रही है उससे तो लगता है कि सरकार अब किसी भी प्रकार की अवहेलना या ग़लती को बर्दाश्त करने के हक़ में नहीं है । इस एक्ट में चालान की दरें अनुशासन की ऐसी सीख दे रही है कि कोई भी वाहन चालक ग़लती करने से पहले कई बार अवश्य ही सोचेगा । सरकार इस विषय पर यूरोपीयन देशों का अनुसरण कर रही है और कड़ा अनुशासन दंड से ही संभव है...इस फार्मुले पर सख़्ती का संदेश दे रही है । चालान में कई गुणा वृद्धि अब चालान के साथ-साथ ड्राईविंग को भी पटरी पर लाने के लिए सरकार का एक वाज़िब क़दम तो कहा ही जा सकता है । ये नियम हमारी सुरक्षा की पूर्ण गारंटी तो नहीं परन्तु बहुत हद तक हमारी ज़िंदगी को बचाने की मुहिम के तौर पर ही देखा जाना चाहिए । जिन राज्यों में इसे लागु किया जा चुका है वहां के रुझान यानि परिणाम भी सामने आने लग गये हैं । वाहन की कीमत कम और चालान अधिक.....ऐसी स्थिति में बहुत जगह तो वाहनों को ही आग के हवाले कर दिया गया । यदि हम गंभीरता से मनन करें तो यहां बताऐ गए आंकड़े सख़्ती को अपनाने की आवश्यकता भी बता रहे हैं । लेकिन सरकार की जिम्मेवारी अभी सरकार को ही पता नहीं है शायद ।

बद्हाल सड़कें, पार्किंग नहीं...और शाही चालान

यहां दीगर बात ये है कि सरकार ने बिल तो संसद में पेश करके इसे सख़्ती से लागु करने की कवायद की है लेकिन क्या सरकार अपनी जिम्मेवारी में खरी उतर पा रही है ? सड़कों की हालात, गड्ढों से दागदार, रेलिंग या तो है ही नहीं है तो टूटी-फूटी, पार्किंग के नाम पर बहुत कम सुविधा.....और इस पर ये शाही चालान...तो लोगों का विरोध भी वाज़िब लगता है । सरकार सुविधा के नाम पर सिक्सलेन, फोरलेन या टूलेन में धूल तो उड़ा ही रही है लेकिन वास्तविकता अलग है ।

अधिकतर सड़क दुर्घटनाऐं बेहद लाचार सड़कों के कारण ही होते हैं । और जब हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो यहां स्थिति और बद्तर हो जाती है । तंग सड़कों और बिना रेलिंग वाली स्थिति में दुर्घटनाओं ने पहाड़ों को कई गहरे ज़ख्म दिऐ हैं और अभी न जाने कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा ? यहां तो स्थिति ये है कि इन तंग सड़कों पर दोनों ओर वाहन खड़े रहते हैं और सड़कों में जहां पक्के डंगों की आवश्कता है उसे विभाग बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाता है । जब दुर्घटना हो जाती है तो योजना, टेंडर आदि औपचारिकता होने लगती है और बाद में ठेकेदारी की दीमक उसे खाना शुरु कर देती है । सरकार अपनी भूमिका कानून को लागु करने तक सीमित करेगी तो प्रश्नचिन्ह लगना तो वाज़िब है ही । लोग गाड़ी को पार्क करें तो कहां.... न सरकार के पास पर्याप्त पार्किंग है और न ही वाहन खरीदने से पहले मालिक को पता है कि पार्क कहां करनी है ? सरकार ने हिमाचल में तो वाहन खरीदने से पहले पार्किंग का अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता रखी है लेकिन उसका जुगाड़ तो हर आदमी कर ही रहा है । उसके बाद वाहन सड़कों के किनारे ट्रैफिक और लोगों की समस्या का कारण बनते हैं । सरकार के सारे वायदे जो कि पार्किंग और सुविधाजनक सड़क को लेकर किए जाते रहे हैं, वो धरे के धरे रह गये हैं । आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी सड़कों की दशा पर यदि दुःख हो रहा हो तो इसे स्वीकार करने में हर्ज़ नहीं होना चाहिए कि हम खोखले पेड़ को ही सींचते रहे हैं ।

एक हादसा अभी पूर्व में ही शिमला के झंझीड़ी में हुआ । तंग सड़क के दोनों ओर वाहन खड़े थे । सड़क भी धंसने की स्थिति में थी । और फिर थोड़ी ही देर में बस सड़क से नीचे पलटी और लोगों के घर के चिराग बच्चे मौत के मुंह में समा गए । इतना बड़ा हो-हल्ला होने के बाद भी वहां स्थिति वैसी की वैसी ही है । सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगेती है । कांगड़ा का एक ऐसा ही हादसा याद आता है जिसमें बस के गिरने के कार 27 लोग मारे गए थे जिसमें 23 तो स्कूली बच्चें ही थे । और चालान के लिए नियमावली सरकार की प्राथमिकता है । सरकार अपनी जिम्मेवारी भी सुनिश्चित करें । कानून और बिल लाने से पहले सरकार को यह देखने की आवश्यकता होनी ही चाहिए कि हम विकासशील देश का हिस्सा हैं और 135 करोड़ से अधिक भी । ऐसे में यूरोपियन पद्धति को अपनाने के बजाए जिम्मेवारी के साथ सुविधाओं को तरहीज देते हुए कानून की अनुपालना करवाई जायें तो सरकार की मंशा को समर्थन मिल जाऐगा ।

एक्ट को लागु करने से पहले जागरुकता क्यों नहीं

सरकार की मंशा क्या है ये तो उसके वज़ीर ही समझ सकते हैं लेकिन एक आम इंसान की यह बात दीगर है कि कोई भी नया कानून या बिल जब पास होकर लागु होने की प्रक्रिया में आता है तो उसकी संपूर्ण जानकारी और ज्ञान लोगों तक पहुंचाना अति आवश्यक है । लेकिन इतने भारी-भरकम चालान काटने से पहले पूरे देश में क्या एक सक्षम जागरुकता अभियान की आवश्यकता सरकार को महसूस नहीं हुई ? समाचार पत्रों में, रेडियो, दूरदर्शन और निजी चैनलों पर इस प्रकार के विज्ञापन जो लोगों को सड़क सुरक्षा और नए नियमों की जानकारी देते हों....की जानकारी देना आवश्यक नहीं था ? ये एक प्रक्रिया है जिसमें ट्रैफिक के नए नियमों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से साझा करनी होती है ताकि आम नागरिक इससे जागरुक हो सके । घर-घर पर पंप्लेट्स आदि का वितरण हो । स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, टैक्सी युनियन आदि में इसके लिए जागरुकता करने की आवश्यकता है । लेकिन सरकार न इसे सीधा लागु कर दिया और इसके परिणाम ये थे कि लोग

सड़कों पर ही रोते-बिलखते रहे । हज़ारों से लाखों तक का चालान का भुगतान लगभग मुसीबत से कम नहीं है सबके लिए । चैनलों पर वाहन चालकों ने अपनी ग़लती मानी लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इसका चालान इतना होता है । सरकार अफरातफरी में इस सख़्ती से पहले जागरुकता का पक्ष भूल गई । केंन्द्रिय मंत्री नितिन गड़करी ने तो इसे और अधिक सख़्त करने की बात दोहराई है । यहां यह बात उद्धृत करने का अभिप्राय यह नहीं कि इस कानून में ख़ामियां है अपितु इसे लागु करने से पहले जागरुकता करना अति आवश्यक है । उसके बाद भी यदि लोग अवहेलना करते हैं तो कानून की अनुपालना सख़्ती से ही हानी चाहिए ।

पुलिस की भूमिका को पारदर्शी बनाना ज़रुरी

इस एक्ट के लागु होने के बाद सोशल मीडिया सबसे अधिक चर्चा पुलिस की भूमिका को लेकर ही हुई है । यहां लोग इस बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे कि पुलिस की भूमिका पारदर्शी रह पाती है कि नहीं । इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस की मुशक्क़त से ही इसका अनुपालन संभव हो पाऐगा लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि पुलिस पारदर्शी नहीं रहती है और चालान काटने में भाई-भतीजावाद या रिश्वत की ख़बरें आम हो जाती है । इससे भरोसा उठना लाज़मी है । पुलिस को दंडित करने की मानसिकता से अधिक लोगों को जागरुक करते हुए चालान काटने की प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता है । यदि पुलिस ही रिश्वत लेते हुए पकड़ी जाए या पक्षपात रवैया अपना रही है तो एक सार्वजनिक दूरभाष नंबर हो जिस पर तुरंत लोग शिक़ायत कर सके ।

सरकारी अभियान बने जन अभियान

सरकार एक बड़े बजट के साथ सड़क सुरक्षा पर लोगों को जोड़ने की बात कर रही है । ऐसे में यह बात सामान्य नहीं होगी कि पैसों को सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों पर आंखें बंद करके खर्च किया जा रहा हो और उसका परिणाम खाली हाथ ही मिले । सड़क सुरक्षा को लेकर मैराथन, खेल-कूद, भव्य कार्यक्रम, रंगारंग प्रस्तुतियों की चमक-धमक से अच्छा खर्च तो हो ही जाएगा लेकिन लोग कितने जागरुक होंगे, इस पर संदेह होता है । आम लोगों को कानून और नियम-कायदे बताने के साथ ही हम किस प्रकार स्वयं और परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, सड़क पर किन सावधानियों को ध्यान में रखना है, दुपहिया या चौपहिया वाहनों को चलाने आदि के बारे में जागरुकता दी जाए तो इन अभियानों की सार्थकता बन पाऐगी ।

स्वयं, परिवार और देश के लिए....सड़क स्वराज

अब समय आ गया है कि हम सड़क पर चलने, गाड़ी चलाने और नियमों का पालन करने के लिए स्वयं को मानसिक और शारीरिक रुप से तैयार कर लें । विकास हमेशा बलिदान के मार्ग से होकर गुजरता है । हमें अपनी ज़िद्द और लापरवाही का त्याग कर अपने और अपने परिवार के साथ समाजहित में कड़े अनुशासन से होकर निकलना होगा । दुपहिया वाहन पर आगे और पीछे बच्चों को स्कूल ले जाना वो भी बिना हेलमेट के स्वयं के साथ-साथ उन देश के होनहारों के साथ अन्याय ही कहा जाऐगा । इसमें उन बच्चों का कोई दोष नहीं जिन्हें हम अपने साथ ख़तरे में सफर करवाते हैं । सड़क सुरक्षा के अनुपालन में ही सड़क स्वराज आ पाऐगा । बेतरतीब वाहन पार्किंग और अनुशासनहीनता किसी भी राष्ट्र की उन्नति में निःसंदेह सबसे बड़ा अवरोधक है । जिस देश में सड़क पर ऐंबुलैंस को रास्ता देने के लिए नियम और कानून बनाने की आवश्यकता हो, जागरुक करने की आवश्कता हो, वहां पर हम किस शोचनीय स्थिति को बयां कर रहे हैं ..... इसे आप सहज ही अनुमान लगा पा रहे होंगे !

हेम राज चौहान
संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

बंडारु दत्तात्रेय हिमाचल के नए राज्यपाल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (नामित) बंडारू दत्तात्रेय का शिमला पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बंडारू दत्तात्रेय 11 सितम्बर को प्रातः 11 बजे हिमाचल प्रदेश के 27वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, महापौर कुसुम सदरेट, मुख्य सचिव डॉ. श्रीकान्त बाल्दी, पुलिस महानिदेशक एस.आर. मरडी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुण्डू, प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा गणमान्य व्यक्तियों ने राजभवन में उनका स्वागत किया।

इससे पूर्व, यहां अनाडेल हैलीपेड पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप, पुलिस अधीक्षक उमापति जमवाल तथा अन्यों ने बंडारू दत्तात्रेय का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने की फिजियोथैरेपिस्ट के रिक्त पदों को भरने की घोषणा
सभी मैडिकल कालेजों में फिजियोथेरेपिस्ट के पद भरे जाएंगे

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश सरकार सभी जिला अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर फिजियोथेरेपिस्ट के पदों को भरेगी। इसके अतिरिक्त किन्नौर और लाहौल-स्पीति के अलावा प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में फिजियोथैरेपिस्ट का एक अतिरिक्त पद भी सृजित किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विश्व फिजियोथैरेपिस्ट दिवस के अवसर पर इंडियन फिजियोथैरेपिस्ट ऐसोसिएशन के हिमाचल चैप्टर तथा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'हिमक्लेव-2019' के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फिजियोथैरेपिस्ट की बेहतर कार्यप्रणाली के लिए प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश फिजियोथैरेपिस्ट परिषद के गठन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण हिमाचल में सड़क दुर्घटनाओं की आवृति अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक रहती है जिसके दृष्टिगत फिजियोथैरेपिस्ट की भूमिका महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी छः मेडिकल कालेजों में फिजियोथैरेपिस्ट के 3-3 पद भरने की घोषणा की ताकि रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंनें कहा कि राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए वृद्धाश्रमों में फिजियोथैरेपिस्ट की सेवाएं प्रदान करने की पहल की है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में फिजियोथैरेपिस्ट के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा।

धर्मशाला कारागार का नामकरण
लाला लाजपत राय के नाम पर करने की घोषणा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के धर्मशाला में जिला कारागार (ओपन एयर) भवन के धरातल व प्रथम मंजिल की आधारशिला रखी। इस अतिरिक्त भवन के निर्माण को 82 लाख रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा जिसमें आगंतुक कक्ष, शस्त्रागार, सीसीटीवी निगरानी कक्ष, उप पुलिस अधीक्षक कक्ष, स्टोर, पैन्टरी, पैरा-लीगल कार्यालय तथा रिकार्ड कक्ष आदि शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कारागार परिसर में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की प्रतिमा का अनावरण किया। लाला लाजपत राय को 21 अप्रैल, 1922 से 9 जनवरी 1923 तक ब्रिटिश सरकार द्वारा इस कारागार में रखा गया था। उन्होंने इस कारागार का नामकरण लाला लाजपत राय करने की घोषणा की।

जन मंच में 1534 मांगपत्र और शिकायतें प्राप्त

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राज्य मुख्यालय पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में किन्नौर जिला को छोड़कर प्रदेश के 11 जिलों में जन मंच कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें लगभग 1534 शिकायतें एवं मांगपत्र प्राप्त हुए। इन शिकायतों में से 664 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया तथा शेष मामले सम्बन्धित विभागों को शीघ्र निपटारे के लिए भेजे गए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत महिला लाभार्थियों को 850 से अधिक गैस कनैक्शन वितरित किए गए।

जन मंच के राज्य समन्वयक ने कहा कि जनमंच के प्रभावी क्रियान्वयन से समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश में अपूर्व आयोजित जनमंच कार्यक्रमों में प्राप्त 40298 शिकायतों एवं मांगों में से 33129 का निपटारा कर दिया गया है। 62084 कन्याओं को बेटी है अनमोल तथा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सम्मानित किया गया है। 05 लाख 91 हजार 254 पात्र व्यक्तियों को डिजीटल राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 52808 परिवारों को हिमाचल गृहणी सुविधा योजना से लाभान्वित किया गया है। 45678 गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया गया है तथा 22551 पात्र व्यक्तियों को विभिन्न पैंशन योजनाओं से लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने किया लैंड रिकॉर्ड ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारम्भ

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हाल ही में डिजिटल इंडिया लैड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली का शुभारम्भ किया।

लैंड रिकॉर्ड के ऑनलाइन पंजीकरण का यह कार्यक्रम प्रायोगिक आधार पर सर्वप्रथम शिमला (शहरी) और शिमला जिला की कुमारसेन तहसील में शुरू किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया से राज्य में शीघ्र पंजीकरण के साथ ऑनलाइन मूल्यांकन और भुगतान की सुविधा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि इस पायलेट प्रोजेक्ट की सफलता के उपरांत इसे पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इसके द्वारा राजस्व रिकॉर्डों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ रोकने में भी सहायता मिलेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पहली कम्प्यूट्रीकृत भूमि पंजीकरण की प्रति भूमि मालिक राकेश कुमार और मीना को प्रदान की।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (भारत सरकार) के सचिव अजय प्रकाश सावहनी ने नई दिल्ली से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि एनजीडीआरएस एक यूनिफॉर्म सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग उपभोक्ताओं के लाभ के लिए पूरे देश में किया जा रहा है।

अब बच्चों से मोबाइल फोन-टीवी की आदत छुड़ाएगी सरकार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल और घंटों टीवी देखने की आदत छुड़ाने के लिए भी अब सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया जाएगा। छात्रों को नशे पर जागरूक करने के साथ-साथ स्वच्छता, योग और ईमानदारी की भी शिक्षा दी जाएगी।

संस्कार युक्त शिक्षा, रोड़ सेफ्टी और शौर्य कथाओं से स्कूली बच्चों को अवगत करवाया जाएगा। विद्यार्थियों का हैप्पीनेस स्तर बढ़ाने के लिए हिमाचल सरकार ने यह फैसला लिया है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 से नौवीं और दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह योजना बनाई गई है। नैतिक शिक्षा या सामाजिक विज्ञान विषय में ये पाठ शामिल किए जाएंगे। इसी सप्ताह संभावित स्कूल शिक्षा बोर्ड की बैठक में इस पर अंतिम फैसला होगा।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अगले साल से सरकार नई व्यवस्था करने जा रही है।

रोजाना कई घंटे टीवी-फोन देख रहे बच्चे

नशे पर जागरूक करने के लिए एससीईआरटी सोलन की ओर से सिलेबस तैयार किया जा रहा है।

इसे अगले से सत्र से नौवीं और दसवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा योग, स्वच्छता और रोड सेफ्टी को लेकर प्रैक्टीकल ज्ञान स्कूलों में दिया जाएगा। बैग फ्री डे और अंतर सदन प्रतियोगिताओं के दौरान ये गतिविधियां होंगी। इसके अलावा शौर्य कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं और संस्कार युक्त शिक्षा देने पर भी बल दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बीते दिनों आए एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि शहरों में दसवीं कक्षा के अधिकांश बच्चे रोजाना कई घंटे टीवी और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कारण बच्चे किताबों से दूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज और सरकार के लिए यह मामला चिंतनीय है। इस समस्या को कुछ हद तक दूर करने के लिए सरकार नए बदलाव कर रही है।

टेक्नोमैक की 288.91 करोड़ की संपत्ति सीज, प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई

द रीव टाइम्स ब्यूरो

4300 करोड़ से भी ज्यादा के बहुचर्चित टेक्नोमैक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की 288.91 करोड़ की संपत्ति को सीज किया है।

ईडी ने कंपनी की पांवटा साहिब में भवन जमीन और मशीनरी, जबकि दिल्ली के मेहरोली में कृषि भूमि सीज की है। यह संपत्ति मुख्य आरोपी व कंपनी के एमडी राकेश कुमार शर्मा के नाम पर है।

इसी कंपनी के निदेशक विनय कुमार शर्मा की पांवटा में कृषि भूमि भी सीज की है। बैंक से कंपनी के नाम पर 289 करोड़ का ऋण और 1335 करोड़ की कार्य पूंजी को बैंकों के कंसोरटियम से मंजूर कराया था। ईडी की जांच में कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि हुई है। अब हाईकोर्ट की मंजूरी के बावजूद राज्य कर विभाग पांवटा स्थित इस संपत्ति को नीलाम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत इस संपत्ति को अटैच कर दिया है।

भ्रष्टाचार आरोपी सहायक दवा नियंत्रक निशांत गिरफ्तार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भ्रष्टाचार के आरोपी सहायक दवा नियंत्रक निशांत सरीन को विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद विजिलेंस ने उसे कोर्ट परिसर में ही गिरफ्तार कर लिया। निशांत सरीन पर घूस के तौर पर दवा निर्माता कंपनियों के खर्च पर देश-विदेश घूमने, महंगे होटलों में ठहरने का आरोप है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थी से पूछताछ जरूरी है। मामले से जुड़े रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी निशांत सरीन की जमानत याचिका खारिज कर दी। सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने फार्मा कंपनियों की शिकायत पर गत 21 अगस्त को राज्य दवा नियंत्रक कार्यालय के सहायक दवा नियंत्रक निशांत सरीन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था।

जांच टीम को छापामारी के दौरान संपत्ति के साथ विदेशी शराब और अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। विजिलेंस के अनुसार कंपनी के प्रबंधकों ने बताया था कि एक अधिकारी उनसे पैसों की मांग करता है। इसमें कभी एयर टिकट तो कभी होटल सहित अन्य ऐश-ओ-आराम के खर्च शामिल हैं। आरोपी इससे पहले नाहन औद्योगिक क्षेत्र में तैनात था। उसे बद्दी में 12 जून को अतिरिक्त दवा नियंत्रक बनाया गया था। इससे पहले बिलासपुर में उसे एक बार रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा था।

ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट के सफल आयोजन के लिए नौ समितियां गठित

द रीव टाइम्स ब्यूरो

धर्मशाला में 7 व 8 नवम्बर, 2019 को आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार ने नौ समितियों का गठन किया है। इनमें आयोजन, आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल, परिवहन, शहर का सौन्दर्यीकरण एवं स्वच्छता, मीडिया, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक, सुरक्षा, अग्निशमन व आपातकालीन सुविधा और स्थानीय समन्वय समितियां शामिल हैं।

आयोजन समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है जो इस सम्मेलन के सामान्य निरीक्षण और सहयोग का कार्य करेगी। यह समिति प्रधानमंत्री कार्यालय, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, केंद्रीय मंत्रियों, देशों, राज्यों तथा राजदूतों से सम्पर्क रखेगी।

आतिथ्य और प्रोटोकॉल समिति की अध्यक्षता सचिव सामान्य प्रशासन करेंगे जो अति-विशिष्ट व्यक्तियों का प्रोटोकॉल सुनिश्चित करेगी और अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था करेगी।

परिवहन समिति की अध्यक्षता प्रधान सचिव परिवहन करेंगे। यह समिति इन्वेस्टर्ज मीट के लिए ट्रैवल पार्टनर का चुनाव और विशिष्ट व्यक्तियों और प्रतिनिधियों के लिए वाहनों का प्रबन्धन करेगी। उपायुक्त कांगड़ा को शहर के सौन्दर्यीकरण और स्वच्छता समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति धर्मशाला और इसके आस-पास के क्षेत्रों में होर्डिंग, बैनर आदि लगाने के अतिरिक्त सड़कों, हवाई अड्डा, धर्मशाला शहर, पर्यटक स्थलों की सफाई व मुरम्मत सुनिश्चित बनाएगी।

मीडिया समिति का गठन प्रधान सचिव सूचना एवं जन सम्पर्क की अध्यक्षता में किया गया है, जो आयोजन से पूर्व, इसके दौरान और इसके उपरान्त मीडिया में प्रचार-प्रसार और अति-विशिष्ट व्यक्तियों की प्रेस वार्ताएं आयोजित करेगी। प्रधान सचिव (शिक्षा) प्रदर्शनी समिति की अध्यक्षता करेंगे, जो प्रदर्शनी क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं जैसे डिजाइन आदि को स्वीकृत करेगी। यह समिति कम्पनियों, संस्थाओं और सरकारी उपक्रमों को प्रदर्शनी के लिए स्टॉलों का आवंटन भी करेगी। सुरक्षा, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा समिति का गठन पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में किया गया है। यह समिति आयोजन स्थल, होटलों, हवाई अड्डा और अन्य स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियों, एसपीजी आदि से सम्पर्क में रहेगी।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे का निधन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इमरसन मंगांगवा ने रॉबर्ट मुगाबे के निधन की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट के द्वारा दी। उन्होंने कहा कि देश तथा महाद्वीप में रॉबर्ट मुगाबे द्वारा किये गये योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्हें आजादी के नायक के रूप में भी जाना जाता है लेकिन वे बहुत से विवादों में भी घिरे रहे। रॉबर्ट मुगाबे साल 1980 से जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता के बाद से ही सत्ता में थे। वे साल 1980 में प्रधानमंत्री बने थे।

भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक मनाली में

द रीव टाइम्स ब्यूरो

यह ट्रैक अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण खेल संस्थान मनाली के निदेशक कर्नल नीरज राणा की देखरेख में बनाया गया है। स्काई साइकिलिंग ट्रैक से सरकारी राजस्व को भी बहुत मजबूती मिलेगी।

इस ट्रैक से सैलानियों को भी साहसिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिल सकेगा।

स्काई साइकिलिंग और जीप लाइन हेतु कुछ स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो इनका संचालन करेंगे। आठ युवाओं को अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान मनाली द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्काई साइकिलिंग ट्रैक 9,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है।

भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास–2019

द रीव टाइम्स ब्यूरो

यह अभ्यास 18 सितंबर 2019 को समाप्त होगा। युद्ध अभ्यास - 2019 सबसे लंबे चलने वाले संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यासों में से एक है। यह युद्धाभ्यास भारत तथा अमेरिका के बीच एक प्रमुख द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का प्रयास है। यह भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्ष सहयोग है। यह युद्धाभ्यास दोनों देशों के बीच बारी - बारी से आयोजित किए जाते है। यह युद्धाभ्यास का 15वां संस्करण है।

10 पब्लिक सेक्टर बैंक का विलय कर 4 बैंक बनाये जायेगें

द रीव टाइम्स ब्यूरो

वित्त मंत्री के अनुसार, सरकारी बैंकों में बड़े सुधार की जरुरत है। अब बैंकों ने कदम उठाने शुरू कर दिए है। वित्त मंत्री ने कहा की सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों का असर है कि बैंक एनपीए में कमी आई है। यह घटकर 7.90 लाख करोड़ रुपए ही बचा है।

18 पब्लिक सेक्टर बैंकों में से 14 प्रॉफिट में हैं। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और युनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय होगा। विलय के बाद बनने वाला बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक होगा। अब इसका कुल कारोबार 18 लाख करोड़ रुपए का होगा। केनरा बैंक का विलय सिंडीकेट बैंक साथ होगा।

भारतीय वायुसेना की बढ़ी ताकत, आठ अपाचे हेलिकॉप्टर वायुसेना में शामिल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

एयरबेस पर अपाचे की तैनाती से भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। अमेरिका से भारतीय वायसेना को कुल 22 अपाचे हेलिकॉप्टर मिलेंगे। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ की मौजूदगी में पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर 8 अपाचे हेलिकॉप्टर को शामिल कराया गया। अपाचे विश्व के सबसे आधुनिक लड़ाकू हेलिकॉप्टरों में एक है। अमेरिकी सेना भी दुश्मनों के विरुद्ध इसे अपना संकटमोचक मानती है।

RBI का बड़ा आदेश, 1 अक्टूबर से सभी बैंक जोड़ें रेपो रेट से लोन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आरबीआई ने सभी बैंकों को 01 अक्टूबर से रेपो रेट के साथ होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन और एमएसएमई सेक्टर के सभी प्रकार के लोन को जोड़ने का आदेश दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट जैसे बाहरी बेंचमार्क के अंतर्गत ब्याज दरों में तीन महीने में कम से कम एक बार बदलाव करने को कहा है। आरबीआई दरअसल पिछले कुछ महीनों से लगातार सभी सरकारी और प्राइवेट बैंको से रेपो रेट के साथ बैंक लोन को जोड़ने के लिए कह रहा था।

रेपो रेट को ब्याज दर से जोड़ने की व्यवस्था लागू होने का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। क्योंकि आरबीआई अब आगे से जब - जब रेपो रेट में कटौती करेगा तब बैंकों के लिए भी ब्याज दर में कटौती करना अनिवार्य हो जाएगा। इस कटौती का असर यह होगा कि किसी भी प्रकार के लोन की ईएमआई दर में कमी आएगी। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है।

हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 115वीं जयंती

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मेजर ध्यानचंद का आज ही के दिन साल 1905 में इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया था। उनके सम्मान में 29 अगस्त को प्रत्येक साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था। भारत ने साल 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। जर्मन तानाशाह हिटलर ध्यानचंद का खेल देख इतना प्रभावित हुआ था कि उनको जर्मनी के लिए खेलने का ऑफर तक दे दिया था। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद राजस्थान के माउंट आबू में कोचिंग कैंप में पढ़ाया भी था।

नागल, फेडरर के खिलाफ पहला सेट जीतने वाले पहले भारतीय

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सुमित नागल ने पहले ही सेट में विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी और पुरुष एकल में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता रोजर फेडरर को 6–4 से हराकर सबको चौंका दिया। सुमित नागल किसी सेट में रोजर फेडरर को हराने वाले पहले भारतीय हैं। यह कमाल उनसे पहले कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं कर पाया है। सुमित नागल विश्व के ऐसे चौथे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने यूएस ओपन में रोजर फेडरर के विरुद्ध पहला सेट जीता है।

एस धामी ने रचा इतिहास, बनीं देश की पहली महिला फ्लाइंग यूनिट कमांडर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

धामी देश की पहली ऐसी महिला वायुसेना अधिकारी हैं जिन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने हाल ही में हिंडन वायुसैनिक अड्डे में चेतक हेलीकॉप्टर के फ्लाइट कमांडर का प्रभार ग्रहण किया है। विंग कमांडर एस धामी हिंडन एयरबेस पर 'चेतक' हेलिकॉप्टर की एक यूनिट की फ्लाइट कमांडर का जिम्मेदारी संभालेंगी। एस धामी पंजाब के लुधियाना में पली - बढ़ी हैं।

वे बचपन से ही पायलट बनना चाहती थी। विंग कमांडर एस धामी भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी भी हैं जिन्हें लंबे कार्यकाल के लिए स्थायी कमीशन प्रदान किया जाएगा। उनके पास 2300 घंटे तक उड़ान भरने का अनुभव है।

मिताली राज ने टी 20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने मिताली राज के इस बड़ी घोषणा की पुष्टि कर दी है। मिताली राज के नाम टी20 क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा मैच खेलने और सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। मिताली राज ने 89 टी-20 इंटरनेशनल मैचों में कुल 2,364 रन बनाए हैं जो इस फॉर्मेट में किसी भी भारतीय द्वारा सबसे ज्यादा है। वे अब ओडीआई पर फोकस करेंगी और साल 2021 विश्व कप की तैयारियों में अपनी ऊर्जा लगाएंगी। मिताली राज ने भारतीय टीम की कप्तानी साल 2012 (श्रीलंका) में, साल 2014(बांग्लादेश) में तथा साल 2016(भारत) में टी20 विश्व कप में की थी। वे भारत के लिए सबसे पहले टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी थीं। उन्होंने भारतीय पुरुष टीम के सदस्य रोहित शर्मा तथा कप्तान विराट कोहली से भी पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन पूरे किए थे।

पी.वी. सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड चौम्पियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पीवी सिंधु ने बैडमिंटन वर्ल्ड चौम्पियनशिप 2019 के फाइनल में जीत दर्ज करते हुए स्वर्ण पदक भी जीता है। वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। पी.वी. सिंधु ने जापान की खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड चौम्पियनशिप का खिताब जीता है। पी.वी. सिंधु द्वारा जीत दर्ज करने के कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको ट्वीट करके बधाई दी। प्रधनामंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अति प्रतिभावान पीवी सिंधु ने एक बार फिर भारत को गौरवान्वित किया है। सिंधु इस टूर्नामेंट में पांच पदक जीत चुकी हैं। इनमें एक स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य पदक शामिल हैं। पी.वी. सिंधु ने कहा कि ओलंपिक जीतना उनका सपना है। अपने पुरस्कार की अलमारी में ओलंपिक गोल्ड के लिए अभी रिक्त स्थान है।

भारत की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य का निधन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कंचन चौधरी भट्टाचार्य 1973 बैच की आईपीएस अधिकारी थीं। उन्होंने साल 2004 में उस समय इतिहास रचा था जब वे उत्तराखंड की पुलिस महानिदेशक बनीं थीं। 31 अक्टूबर 2007 को वे पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुईं। वे मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थीं।

कतर 2022 – विश्व कप के लिए लोगो जारी किया गया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कतर ने 2022 के विश्व कप के लोगो जारी करने का जश्न दोहा और दुनिया भर के शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करके मनाया। अधिकारिक लोगो का अनावरण स्थानीय समयानुसार रात 8:22 बजे पर हुआ। देश की कई प्रतिष्ठित इमारतों में हजारों लोगों ने एक ही समय पर जारी किये गये लोगो को देखा।

यह लोगो कतर के झंडे के बरगंडी रंग के साथ स्थानीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक देश कतर में 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही हैं।

चंद्रयान – 2 नही हुई सॉफ्ट लैंडिंग

द रीव टाइम्स ब्यूरो

चंद्रयान-2 अब चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के लिए 48 दिन की यात्रा शुरू हो गई थी। भारत इससे पहले चंद्रयान - 2 की लॉन्चिंग 15 जुलाई को करने वाला था, लेकिन क्रॉयोजेनिक इंजन में लीकेज के कारण रोक दिया गया था। चन्द्रयान - 2 मिशन का मुख्य उद्देश्य चांद की सतह का नक्शा तैयार करना, खनिजों की मौजूदगी का पता लगाना, चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करना और किसी न किसी रूप में पानी की उपस्थिति का पता लगाना था। चंद्रयान - 2 के अंतिम चरण में भारत के मून लैंडर विक्रम से उस समय संपर्क टूट गया था जब वह चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ रहा था। इसरो के अनुसार, रात 1:37 बजे लैंडर की चांद पर 'सॉफ्ट लैंडिंग' की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लेकिन लगभग 2.1 किमी ऊपर संपर्क टूट गया था। इसरो के अध्यक्ष के. सिवन ने कहा की डेटा की समीक्षा की जा रही है। चंद्रयान 1 की खोजों को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रयान - 2 को भेजा गया है।

भारत बुलेटप्रूफ जैकट निर्यात करने वाला चौथा देश बना

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत ने हाल ही में यूरोपीय देशों सहित 100 से अधिक देशों को अपने मानकों के मुताबिक बुलेट प्रुफ जैकेटों का निर्यात शुरू कर दिया है। भारत अमेरिका, ब्रिटेन तथा जर्मनी के बाद चौथा ऐसा देश है जिसने बुलेटप्रूफ जैकेट पर अपना राष्ट्रीय मानक रखा है। यह मानक 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करता है। हाल ही में नीति आयोग के सदस्य तथा रक्षा शोध विकास संगठन (डीआरडीओ) के पूर्व प्रमुख वीके सारस्वत के मुताबिक देश के सैन्यबलों को तीन लाख बुलेटप्रूफ जैकेटों की जरूरत है। विभिन्न आकार के जैकेट सैनिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाए जा सकें इसके लिए कड़े मानक तैयार किए जा रहे हैं।

डॉ. राधाकृष्णन की 131वीं जयंती मनाई

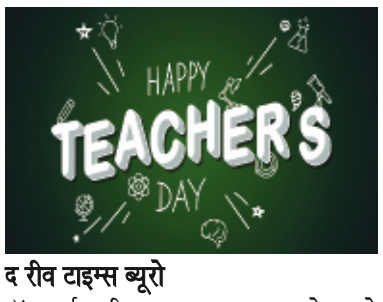

द रीव टाइम्स ब्यूरो

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉ. राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर, 1888 को हुआ था। शिक्षक दिवस - 2019 के अवसर पर डॉ. राधाकृष्णन की 131वीं जयंती भी मनाई जाएगी। डॉ. राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षकों के पास देश का सर्वश्रेष्ठ दिमाग होना चाहिए। वर्ष 1962 से, जिस वर्ष वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने, शिक्षक दिवस उनके जन्मदिन पर मनाया जाने लगा। डॉ. राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनके छात्रों और दोस्तों ने उनसे उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति देने का अनुरोध किया, लेकिन जवाब में डॉ. राधाकृष्णन ने कहा कि "मेरे जन्मदिन को अलग से मनाने के बजाय, यह सौभाग्य की बात होगी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए।" डॉ. राधाकृष्णन को 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

भारत मलेरिया के मामलों में दुनिया में चौथे स्थान पर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत मलेरिया के मामलों में विश्व में चौथे स्थान पर है। 'द लैंसेट' पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 में मच्छर काटने से होने वाली घातक बीमारी मलेरिया के कुल मामलों में भारत का स्थान चौथा रहा है। नवीनतम लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व से मलेरिया का उन्मूलन संभव है। इस रिपोर्ट को दुनिया भर के 41 वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों और नीति - निर्माताओं द्वारा तैयार किया गया है। वर्ष 2000 से 2017 तक 20 देशों से मलेरिया की समाप्ति घोषित की गई। इसी तरह के प्रयासों से 2050 तक सभी देशों से मलेरिया की समाप्ति हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस बीमारी से संक्रमित चौथा सबसे बड़ा देश है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

ये हैं दुनिया के वो खूबसूरत देश जहां गर्व से बोली जाती है हिंदी भाषा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिंदी भाषा भारत की आधिकारिक भाषा और संयुक्त अरब अमीरात में मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक भाषा है। हिंदी भारत में लगभग 4.25 करोड़ लोगों की पहली भाषा है और करीब 12 करोड़ लोगों की दूसरी भाषा है।

हिंदी का नाम फारसी शब्द ''हिंद'' से लिया गया है, जिसका अर्थ है ''सिंधु नदी की भूमि''। फारसी बोलने वाले तुर्क जिन्होंने गंगा के मैदान और पंजाब पर आक्रमण किया, 11वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया था।

आज हम आपको उन देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां 'हिंदी' बोली जाती है।

नेपाल नेपाल में हिंदी भाषी लोगों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। लगभग आठ मिलियन नेपाली हिंदी भाषा बोलते हैं। हालांकि, एक बड़ी आबादी द्वारा हिंदी बोले जाने के बावजूद, नेपाल में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। 2016 में सांसदों ने हिंदी भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में शामिल करने की मांग की थी।

संयुक्त राज्य अमेरिका जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदी भाषी लोगों के तीसरे सबसे बड़े समूह का घर है। लगभग 650, 000 लोग यहां हिंदी भाषा बोलते हैं, जो इसे संयुक्त राज्य में 11वीं सबसे लोकप्रिय विदेशी भाषा बनाती है।

हालांकि, अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व के कारण भाषा बोलने वाले ज्यादातर इसका इस्तेमाल घर पर करते हैं। संयुक्त राज्य में हिंदी के मूल वक्ता बहुत कम हैं, जिनमें से अधिकांश भारत के अप्रवासी हैं।

मॉरीशस मॉरीशस के एक तिहाई लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। देश का संविधान राष्ट्रीय भाषा को स्पष्ट नहीं करता है, हालांकि अंग्रेजी और फ्रेंच संसद की आधिकारिक भाषा हैं। अधिकांश मॉरीशस मूल भाषा के रूप में मॉरीशस क्रियोल बोलते हैं।

फिजी फिजी में हिंदी भाषा भारतीय मजदूरों के यहां आगमन के बाद आई। फिजी में ये उत्तर पूर्वी भारत से आए, जहां अवधी, भोजपुरी और कुछ हद तक मगही बोलियां बोली जाती थीं। इन बोलियों को उर्दू के साथ जोड़ा गया, जिसके परिणामस्वरूप एक नई भाषा का निर्माण हुआ, जिसे शुरू में फिजी बाट के रूप में जाना जाता था।

न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड - भारत सस्टेनेबिलिटी चैलेंज 2017 के अनुसार, हिंदी न्यूजीलैंड में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। दोनों देशों के बीच बढ़ते सांस्कृतिक संबंध इसकी बड़ी वजह है।

जर्मनी जर्मनी में तो कई दशकों से हीडलबर्ग, लीपजिग और बॉन सहित विश्वविद्यालयों और शहरों में हिंदी और संस्कृत पढ़ाई जा रही है।

पाक के बलूचिस्तान में है खौफनाफ मंजर, वहां के राजनीतिक कार्यकर्ता ने बताई असलियत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

बलूचिस्तान में किसी प्रकार का कोई लोकतंत्र नहीं है। यह दावा बलूच मानवाधिकार काउंसिल के उपाध्यक्ष हसन हमदम ने किया। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान की स्थिति बहुत ही खराब है। वहां हर अपहरण, हत्या और लोगों को फेंका जाता है। हमदम ने बताया कि बलूचिस्तान में कभी किसी प्रकार का लोकतंत्र नहीं रहा। बलूचिस्तान में सीधे पाकिस्तानी सेना का शासन इस्लामाबाद द्वारा किया जाता है। यहां के लोगों का पाकिस्तानी सरकार द्वारा शोषण किया जाता है और उनके संसाधनों को उनसे छीन कर पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में इस्तेमाल जाता है।उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बलूच लोगों और उसके विकास से कोई सरोकार नहीं है। बलूचिस्तान के लोग सिर्फ रोने के लिए ववविश हैं क्योंकि यह क्षेत्र संसाधानों से समृद्ध है। दुर्भाग्य से वहां पाकिस्तान में रहने वाले सबसे गरीब लोग हैं। वहां बच्चों को कोई शिक्षा नहीं मिलती है। उनको कोई नौकरी, संसाधन की सहूलियत, पानी इत्यादि नहीं है। वहां के लोगों को कोई अधिकार नहीं है। यही कारण है कि क्षेत्र में विद्रोह काफी उग्र है।

पत्रकार खशोगी की हत्या को लेकर तुर्की के अखबार ने खोले अहम राज

द रीव टाइम्स ब्यूरो

तुर्की के अखबार सबा ने सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी के अंतिम पलों की बातचीत का ब्योरा प्रकाशित किया है। अखबार ने आडियो रिकार्डिग के हवाले से दावा किया है कि सऊदी सरकार के मुखर आलोचक और वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार खशोगी की हत्या बैग से मुंह दबाकर की गई थी। पिछले साल दो अक्टूबर को इस्तांबुल स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास में खशोगी की हत्या कर दी गई थी। अखबार का कहना है कि यह रिकार्डिग दूतावास के अंदर की है और उसे तुर्की के अधिकारियों ने बरामद किया था। इसमें कथित तौर पर खशोगी की आखिरी बातें रिकार्ड हो गई थीं। अखबार के अनुसार, खशोगी की हत्या के लिए आई सऊदी टीम में एक फोरेंसिक विशेषज्ञ भी था। यह विशेषज्ञ वाणिज्य दूतावास में खशोगी के पहुंचने से पहले उन्हें बलि का जानवर बता रहा था। खशोगी के दूतावास पहुंचते ही उन्हें बताया गया कि इंटरपोल के आदेश के चलते उन्हें सऊदी अरब की राजधानी रियाद जाना होगा। उन्होंने इस आदेश को मानने से इन्कार कर दिया और तुरंत अपने बेटे को मैसेज किया। इसके बाद उन्हें नशीला पदार्थ खिला दिया गया था। अखबार के मुताबिक, खशोगी के आखिरी शब्द थे कि उनका मुंह बंद ना किया जाए क्योंकि उन्हें अस्थमा है। इस रिकार्डिग में फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा खशोगी के शव के टुकड़े किए जाने की भी जानकारी है।

तेजी से कंगाली की ओर जा रहा पाकिस्तान मूडीज ने बताया गंभीर हैं आर्थिक हालात

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दुनिया की बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान के आर्थिक हालात को लेकर चेतावनी दी है। मूडीज ने पाकिस्तान को उन देशों में रखा है, जिनपर अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। पाकिस्तान की ये आर्थिक हालत इसलिए हुई है क्योंकि उसकी विदेशी मुद्रा पर निर्भरता और बाहरी ऋण भुगतान ने पाकिस्तान की हालत कमजोर कर दी है।

मूडीज ने कहा है, सबसे बड़ा जोखिम एशिया-प्रशांत मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बी-रेटेड देशों पर है। कमजोर ऋण वहन क्षमता, विदेशी मुद्रा पर निर्भरता के कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। एजेंसी ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ-साथ कुछ अन्य देशों को गंभीर आर्थिक हालातों को लेकर अवगत कराया गया है। एजेंसी ने आगे चेतावनी देते हुए कहा है कि कर्ज लेने के कारण पाकिस्तान, श्रीलंका, मिस्र, अंगोला और घाना आने वाले समय में सबसे ज्यादा गिरावट देखेंगे।

पाकिस्तान के कर्ज में और बढ़ोत्तरी ही हुई है। 39 महीने के आईएमएफ समझौते के साथ पाकिस्तान को 6 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता दी गई है, जिससे वो अपनी आर्थिक हालत को ठीक कर सके। पाकिस्तान के राजकोषीय घाटे में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है।

चांद पर भारत के विक्रम से 1134 किमी. दूर है चीन का लैंडर

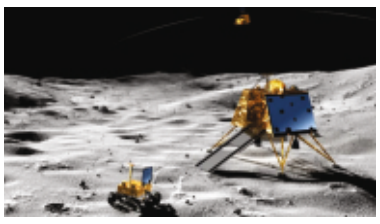

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जैसे-जैसे समय बीत रहा है वैसे-वैसे चांद की सतह पर मौजूद लैंडर विक्रम से संपर्क साधने की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। हालांकि इसरो को ऑर्बिटर द्वारा भेजी गई लैंडर की थर्मल इमेज के जरिए उसकी पॉजीशन का पता जरूर लग गया है। बहरहाल, उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। गौरतलब है कि 6-7 सितंबर को लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर चांद के दो क्रेटर्स मजिनस सी और सिमपेलियस एन के बीच वाले मैदान में लगभग 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर उतरना था। इन दोनों के बीच की दूरी करीब लगभग 45 किमी है। लेकिन सतह छूने से दो किमी पहले ही यह अपने मार्ग से भटक गया और इसका संपर्क इसरो के मिशन कंट्रोल से टूट गया। 9 सितंबर को ऑर्बिटर ने न सिर्फ लैंडर विक्रम की पॉजीशन का पता लगाया था बल्कि उसकी थर्मल इमेज भी खींची थी। बहरहाल, नासा ने भी विक्रम की खोज में सहायता करने की बात कही है।

चांद पर लैंडिंग को लेकर इस साल अब तक दो मिशन गए थे जिनमें भारत के अलावा एक चीन का भी था। चीन का Chang'e 4 probe 3 जनवरी 2019 को चांद की धरती पर सफलता पूर्वक उतरा था। चीन के इस लैंडर का मॉडल काफी कुछ भारत के विक्रम से मिलता-जुलता था। गौरतलब है कि Chang'e 4 probe भी चांद के उस हिस्से में ही उतरा था जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। चांद का यह हिस्सा भी साउथ पोल में ही आता है। लेकिन यदि भारत के विक्रम लैंडर और चीन के Chang'e 4 probe के लैंडिंग एरिया के बीच की दूरी की बात करें तो यह काफी है।

गुजरात में लगेगा फ्लाइंग कार बनाने का प्लांट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

गुजरात में जब फ्लाइंग कार (उड़ने वाली कार) का प्लांट लगने की चर्चा चली तो लोगों की रुचि इसमें और बढ़ गई। बीते दिनों एक डच कंपनी PAL-V ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से मुलाकात की थी। कंपनी ने गुजरात में फ्लाइंग कारों का पहला प्लांट लगाने को लेकर चर्चा की थी। PAL&V दुनिया की पहली फ्लाइंग कार पेश करने वाली कंपनी है। दरअसल कंपनी भारत में फ्लाइंग कार का प्लांट लगाकर पूरे एशिया में पांव पसारने की इच्छुक है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी कंपनी के प्रस्ताव को हाथों-हाथ लिया है। उन्होंने कंपनी अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि अगर वह गुजरात में प्लांट लगाते हैं तो उन्हें जमीन से लेकर बिजली, पानी जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं और सरकार की तरफ से सभी मदद उपलब्ध कराई जाएगी।

कंपनी ने दिसंबर-2018 से इन कारों की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी अधिकारियों का दावा है कि वह 2020 तक अपने पहले ग्राहक को पहली फ्लाइंग कार मुहैया करा सकती है। यही वजह है कि कंपनी जल्द से जल्द अपना प्लांट सेटअप करना चाहती है।

गुजरात मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद डच कंपनी के अधिकारियों ने बताया था कि वह अन्य राज्यों में भी प्लांट के लिए बेहतर विकल्प की तलाश कर रहे हैं। कंपनी के अधिकारियों का मानना है कि वर्ष 2040 तक दुनिया भर में फ्लाइंग कार का बाजार डेढ़ ट्रिलियन डॉलर (1068 खरब रुपये से ज्यादा) का होगा। कंपनी अधिकारियों के अनुसार फ्लाइंग कार का भविष्य बेहतरीन है। इस दिशा में तमाम देशों में लगातार खोजें और ट्रायल चल रहे हैं।

कश्मीर पर 70 सालों से पाखंड कर रहा पाकिस्तान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पाकिस्तान जिनेवा में कश्मीर मुद्दे को उठाने को चाहे जितना भी उठाने की कोशिश कर रहा हो, पाकिस्तान का हर मंसूबा नाकाम हो रहा है। पूरी दुनिया से उसे कश्मीर पर कोई समर्थन नहीं मिल पा रहा है तो अब गिलगित-बाल्टिस्तान भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की कलई खोल रहा है। पाकिस्तान को एक पाखंडी करार देते हुए, गिलगित-बाल्टिस्तान(Gilgit&Baltistan) के एक कार्यकर्ता सेंज एच सेरिंग ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो जबरन कब्जा करने में भरोसा करता है।

इस तरह देखा जाए तो पाकिस्तान का कश्मीर के लोगों को समर्थन झूठा और सतही है। इसका जीता जागता सबूत पिछले 70 सालों से पीओके (गुलाम कश्मीर) में पाकिस्तान का अत्याचार बता रहा है। जिनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 42वें सत्र के मौके पर गिलगित-बाल्टिस्तान स्टडीज के निदेशक एसएच सेरिंग ने कहा, गिलगित -बाल्टिस्तान के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक पाखंडी है, उसके दोहरे मापदंड हैं, जम्मू-कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं करता है, वह एक आपराधिक देश और एक व्यवसायी देश है।

भविष्य में सच होगा दूसरे ग्रहों पर घर बनाने का सपना, वैज्ञानिकों ने पहली बार बनाई सीमेंट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

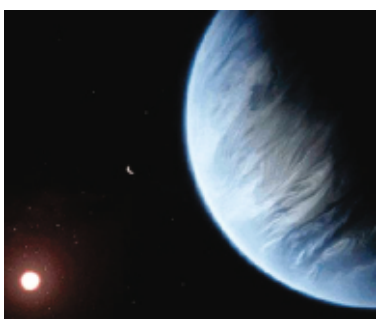

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आइएसएस) में अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में सीमेंट के प्रमुख घटक में पानी मिलाकर उसे ठोस बनाया है। नासा ने बताया कि इससे भविष्य में दूसरे ग्रहों पर मनुष्यों को विकिरण और अत्यधिक तापमान से बचाने में मदद मिल सकती है। शोधकर्ताओं ने ठोस हुए सीमेंट की जांच भी की। दरअसल, वह यह समझना चाहते थे कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के तहत हुई प्रक्रिया में रसायन विज्ञान और सूक्ष्म संरचनाएं किस तरह से बदली हैं। अपने प्रयोग को नासा ने माइक्रोग्रेविटी इंवेस्टिगेशन ऑफ सीमेंट सॉलिडीफिकेशन (एमआइसीएस) प्रोजेक्ट नाम दिया है। इस प्रयोग में शोधकर्ताओं ने सीमेंट के लोकप्रिय घटक ट्राइ कैल्शियम सिलिकेट और पानी को पृथ्वी के बाहर पहली बार आपस में मिलाया। नासा ने बताया कि एमआइसीएस प्रोजेक्ट में अंतरिक्ष विज्ञानियों ने पता लगाया कि क्या सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में सीमेंट जमाकर एक मजबूत स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है।

वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में बनाए गए ठोस सीमेंट के सैंपल (नमूने) और धरती पर बनाए गए सैंपल की तुलना भी की। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा कि जब मनुष्य चांद या मंगल पर रुकने के लिए जाएगा। उसे मजबूत जगह का निर्माण करना होगा, जिसमें वह रहकर काम कर सके। यह कंक्रीट ही है जो पृथ्वी में सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला बिल्डिंग मैटेरियल है।

ट्रेड वार थमने के संकेत, अब 16 तरह के अमेरिकी सामानों पर टैरिफ में छूट देगा चीन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर के थमने के संकेत मिल रहे हैं। हालिया पहलकदमी चीन की ओर से की गई है। चीन ने घोषणा की है कि वह 16 तरह के अमेरिकी सामानों पर लगने वाले टैरिफ में अब छूट देगा। गौर करने वाली बात यह है कि चीन की ओर से यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब उसकी अगले महीने से अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर के मसले पर फिर से वार्ता शुरू होनी है। चीन की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अमेरिकी सामानों पर दी गई यह टैरिफ छूट 17 सितंबर से प्रभावी होगी। जिन उत्पादों पर छूट दिए जाने की बात कही गई है उनमें सी फूड प्रोडक्ट्स और कैंसर रोधी दवाएं शामिल हैं।

अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग में 2-3 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है और यह 51.2 फीसद से गिरकर 49.1 फीसद पर आ गई है। वहीं चीन की आर्थिक वृद्धि दर भी पिछले 27 वर्षों में सबसे कम दर्ज की गई है। ट्रेड वार के बीच चीन की मुद्रा युआन भी लगातार नीचे आ रही है। आलम ये है कि बीते 11 सालों में युआन सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

करंट अफेयर्स

THE CURRENT AFFAIRS 2019

- जिसे भारतीय वायु सेना की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है - शालिजा धामी
- हिमाचल प्रदेश के जिस शहर में पर्यटन स्थल गुलाबा में 9,000 फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा 'स्काई साइकिलिंग ट्रैक' बनाया गया है - मनाली
- विश्व का पहला देश वह है, जिसने नाविकों के फेशियल बायोमैट्रिक डेटा का संग्रह कर बायोमैट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज जारी किया है - भारत
- भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मॉस्को में भारतीय दूतावास में जिस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया - महात्मा गांधी
- वनडे इंटरनैशनल में सबसे तेजी से 50 विकेट लेने वाले जिस देश के स्पिनर अजंता मेंडिस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है - श्रीलंका
- 12वें इंडिया सिक्योरिटी शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में जिस स्थान पर किया गया - नई दिल्ली
- वह खिलाड़ी जिसके जन्मदिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है - मेजर ध्यानचंद
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के जिस स्टेडियम से 'फिट इंडिया मूवमेंट' की शुरुआत की है - इंदिरा गाँधी इंडोर स्टेडियम
- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने देश में 2021–22 तक जितने अतिरिक्त सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दे दी है - 75
- हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यह घोषणा की है कि आने वाले कुछ हफ्तों के लिये नासा के वैज्ञानिकों और जिस ग्रह पर मौजूद अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बीच संपर्क रुक जाएगा - मंगल ग्रह
- भारतीय रिजर्व बैंक की बिमल जालान समिति ने संशोधित आर्थिक पूंजी नियम की जितने साल में समीक्षा करने की सिफारिश की है - पांच साल
- वार्षिक वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख तीन महीना बढ़ाकर जितने तारीख तक कर दी है - 30 नवंबर
- भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में जिसको संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का अगला राजदूत नियुक्त किया है - पवन कपूर
- भारतीय रेलवे ने शताब्दी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस और गतिमान एक्सप्रेस में जितने फीसदी किराया कम करने की योजना को लागू करने जा रहा है - 25 फीसदी
- वह आईपीएस अधिकारी जिसका तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार - 2018 के लिए चयन हुआ है - अपर्णा कुमार
- हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत के जिस तेज गेंदबाज ने सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं - जसप्रीत बुमराह
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन तथा जिस मंत्रालय ने हाल ही में एड्स के प्रसार को रोकने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- भारत के जिस राज्य में स्थित डंपा बाघ अभयारण्य को क्लाउडेड लेपर्ड के अध्ययन स्थल के रूप में चुना गया है - मिजोरम
- भारतीय तीरंदाज कोमालिका बारी ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व कैडेट वर्ग के फाइनल में जिस देश की सोनोदा वाका को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया - जापान
- जिस हॉलीवुड कलाकार के एनजीओ अर्थ अलायन्स ने अमेजन वर्षावन में लगी आग पर काबू पाने के लिए 5 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की - लियोनार्डो डीकैप्रियो
- हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने जिस देश में 200 साल पुराने श्रीकृष्ण मंदिर के लिए 4.2 मिलियन डॉलर की पुनर्विकास परियोजना का शुभारंभ किया - बहरीन
- केंद्रीय सतर्कता आयोग ने जिस पूर्व सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में बैंकिंग धोखाधड़ी के लिये सलाहकार बोर्ड का गठन किया है - टी.एम. भसीन
- हाल ही में जिस आयोग द्वारा किये गए सर्वे के अनुसार अभ्रक खनन क्षेत्र में 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के 5000 से अधिक बच्चे शिक्षा से वंचित हैं - राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
- मंगल ग्रह के बाद अब वैज्ञानिक जिस ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की तलाश करने में लगे हैं - बृहस्पति ग्रह
- भारत की जिस पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) का लंबी बीमारी के बाद मुंबई में निधन हो गया - कंचन चौधरी भट्टाचार्य
- हाल ही में जिस देश ने जून 2020 तक देश से सभी शांति सैनिकों को वापिस बुलाए जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध किया है - सूडान
- वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिसने रोजर फेडरर के खिलाफ पहला सेट जितने में कामयाबी हासिल की है - सुमित नागल
- रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को सरप्लस फंड और डिविडेंड के रूप में जितने रुपये दिए जाने की घोषणा की है - 1.76 लाख करोड़ रुपये
- नागर विमानन महानिदेशालय ने जिस वस्तु को विमानों में ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है - एप्पल मैकबुक
- हाल ही में जिस राज्य से टाइगर स्टेट का दर्जा वापस ले लिये जाने के बाद राज्य सरकार बाघों की सुरक्षा हेतु टाइगर स्ट्राइक फोर्स का गठन करने जा रही है - मध्य प्रदेश
- भारत के जिस पहलवान को विश्व चैंपियनशिप में शीर्ष वरीयता दी गई है - बजरंग पुनिया
- बहामास में आये चक्रवाती तूफान का यह नाम है जिससे वहां लगभग 40 लोगों की मौत हो गई है - डोरियन
- वह खिलाड़ी जिसने सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनने का रिकॉर्ड बनाया है - राशिद खान अफगानीस्तान
- विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में भारत को विश्व यात्रा, पर्यटन प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक में जो स्थान प्राप्त हुआ है - 34वाँ
- हाल ही में जिस देश के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया है - जिम्बाब्वे
- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हाल ही में साइबर अपराध जांच और साइबर फोरेंसिक पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जिस शहर में आयोजित किया - नई दिल्ली
- हाल ही में 'वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल' द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में स्वर्ण भंडार के मामले में जिस देश का 10वाँ स्थान है - भारत
- भारत सरकार ने हाल ही में एड्स, टीबी और मलेरिया हेतु वैश्विक फंड के लिये जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है - 22
- वह राज्य जिसने पुलिस विभाग को राज्य में चलने वाले निजी वाहनों पर जाति, पद, गांव का नाम और विभिन्न चिन्हों, स्लोगन के इस्तेमाल बंद कराने के निर्देश दिए हैं - राजस्थान
- इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार विश्व का जो शहर रहने योग्य स्थानों की सूची में पहले स्थान पर है - वियना
- जिसे हाल ही में लेसोथो में नया भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है - जयदीप सरकार
- 'इंडिया - अफ्रीका पार्टनरशिप' पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जिस शहर में आयोजित किया गया - नई दिल्ली
- हाल ही में लैंसेट में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार जिस देश में कार्डियो-वैस्कुलर रोगों के कारण होने वाली मृत्यु - दर उच्च है - भारत
- भारत का वह राज्य जिसमें हाल ही में कांगो फीवर के मामले सामने आये हैं - राजस्थान
- वह देश जिसमें वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप आयोजित किया जायेगा - कतर
- वह क्रेटर जिसकी चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने हाल ही में फोटो खींचकर पृथ्वी पर भेजी है - मित्रा क्रेटर
- कुपोषण मुक्त भारत अभियान को तेज करने के लिये भारत सरकार द्वारा सितंबर महीने को घोषित किया गया है - पोषण माह
- वह प्रतिष्ठित स्थान जिसे स्वाच्छता प्रतिष्ठित संस्थानों की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है - वैष्णो देवी
- वह शहर जहां साउथ एशियन स्पीकर्स समिट का आयोजन किया गया - माले
- वह विश्व - प्रसिद्ध गैर-सरकारी संस्था जिसने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने का निर्णय लिया है - बिल एंड गेट्स फाउंडेशन
- केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया लोगो इन्होंने डिजाईन किया है - रोहित देवगन
- हॉन्गकॉन्ग में लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच चीन की जिस नीति प्रणाली फिर से चर्चा में आ गई है - एक देश दो प्रणाली
- हाल ही में भारतीय वायुसेना में जितने अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है - आठ
- खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने बेकार बर्तनों के पुनः उपयोग के लिए वाराणसी में जिस पहल का उद्घाटन किया - टेराकोटा ग्राइंडर
- Eastern Economic Forum की पांचवीं बैठक जिस देश में आयोजित की जा रही है - रूस
- ISSF विश्वकप शूटिंग चैंपियनशिप में भारत जितने स्वर्ण पदकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर रहा - 5
- वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में किसानों का 4750 करोड़ रुपये का ऋण माफ करने की घोषणा की है - हरियाणा
- हाल ही मे जिस देश ने अंतरिक्ष युद्ध के लिये समर्पित एक स्पेस कमांड स्पेसकॉम की स्थापना की है - अमेरिका
- जिस देश के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में की गई एक घोषणा के अनुसार, बोर्नियो द्वीप के पूर्वी कालीमंतन प्रांत को देश की नई राजधानी बनाया जाएगा - इंडोनेशिया
- पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका मिशन (NERLP) के तहत चार राज्यों मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और जिस राज्य में ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाकर उनकी आजीविका में सुधार किया गया है - सिक्किम
- हाल ही में जिस देश के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने प्रवासी परिवारों को अनुमति देने संबंधित एक नया विनियमन प्रस्तुत किया है - अमेरिका
- श्रीलंका के तेज गेंदबाज जो टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं - लसिथ मलिंगा
- भारत की यशस्विनी देसवाल ने रियो डी जेनेरियो में जारी आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की जितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता - 10 मीटर
- हाल ही में जिस लेफ्टिनेंट जनरल ने आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ का पदभार ग्रहण किया है - मनोज मुकुंद नारावने
- वैज्ञानिकों ने जिस देश में मानव की लगभग 3.8 मिलियन वर्ष पुरानी खोपड़ी की खोज की है - इथियोपिया
- केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के जितने बैंकों का विलय करने की घोषणा की है - 10
- सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर सिर्फ जितनी फीसदी रह गई है - 5 फीसदी

हिमाचल सामान्य ज्ञान

- हिमाचल सरकार किस वरिष्ठ नेता के जन्मदिवस को हिमाचल प्रदेश में सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी - नरेंद्र मोदी
- राष्ट्रीय कृषि एं ग्रामीण विकास बैंक ने सौर सिंचाई योजना के लिए हिमचल प्रदेश को कितने करोड़ का बजट दिया है - 75 करोड़
- हिमाचल हाईकोर्ट का नया न्यायाधीश किसे बनाया गया है - वी रामासुब्रमनियन
- किस जिले से हाल ही में पोषण अभियान की शुरूआत की गई - सिरमौर
- शशि जिन्होंने भारतीय टीम में एशियन पैरा कब्बड्डी मैच में गोल्ड मैडल जीता, उनका संबंध हिमाचल के किस जिले से है - मंडी-करसोग
- हिमाचल सरकार ने सिरमौर जिले के पच्छाद में कितने करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरूआत की है - 42.32 करोड़
- हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में इलेक्ट्रिक बस शुरूआत की जाएगी - 8
- हिमाचल प्रदेश के किस विभाग को हाल ही में दिल्ली में द स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गसा - शिक्षा विभाग
- किस दर्रे को जल्द ही रोप वे से जोड़ा जाएगा - रोहतांग दर्रा-3,978 मीटर
- हिमाचल प्रदेश के किस स्कूल को देश भर में स्वच्छता में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है - बिलासपुर के नंदग्राम स्कूल को
- प्रदेश में एकलव्य स्कूलों का निर्माण करने के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी - 392 करोड़
- प्रदेश के कितने अध्यापकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला - 12
- राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित होने वाले शिक्षक - चंबा से
- हाल ही में निर्वासित तिब्बत सरकार ने कौन से डेमोक्रेसी डे धर्मशाला में मनाया - 59वां. पहली बार 2 सितंबर 1960 को मनाया गया था
- हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जल्द ही नेशनल बाक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाऐगा - शिमला
- प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए विश्व बैंक कितने करोड़ देगा - 500 करोड़

आर्थिक सर्वेक्षण

- हिमाचल में किस प्रमुख बागवानी फसल के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई - सेब
- चंबा से कौन सा कल्सटर रूर्बन मिशन के तहत शामिल किया गया है - सिंहुता
- हिमाचल में ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट समृद्धि योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है - 11 हजार प्रतिवर्ष
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत हिमाचल के कौन से जिले शामिल किए गए हैं - हमीरपुर और कांगड़ा
- हिमाचल में चाय की खेती के तहत कुल क्षेत्रफल कितना है - 2310 हैक्टेयर
- हिमाचल में कहां पर लेबर कोर्ट कम - इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल स्थापित किए हैं - शिमला और धर्मशाला
- हिमाचल की कुल पनबिजली क्षमता क्या है - 27,436
- फ्रूट क्राप्स के तहत कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है - 49 प्रतिशत
- विश्व महिला उत्थान योजना में शामिल किए गए 100 जिलों में हिमाचल के किन जिलों को शामिल किया गया है - ऊना
- बगवानी के संवर्धन के लिए ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला मॉडल फ्लावर कल्टीवेशन सेंटर के तहत किस स्थान पर स्थापित की गई है - पालमपुर
- कृषि उपज के विपणन के लिए किस स्थान पर एक आधुनिक बाजार परिसर कार्यात्मक रहा - सोलन
- किन स्थानों पर सीए स्टोर खोले गए - गुम्मा और जलोड़ टिक्कर
- राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक बैंक कौन सा है - यूको बैंक
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितने पैसे दिए जाते हैं - 40 हजार

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

मुख्यमंत्री लोक भवन योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में सामुदायिक सदभाव को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लोक भवन योजना लांच की है। लोक भवन योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में तीस लाख रुपये की लागत से एक सामुदायिक भवन बनाया जाता है। इलाके के सांसद और विधायक द्वारा सामुदायिक भवन के लिए योगदान भी स्वीकार किया जाता है। इसके बाद भवन का एरिया और बड़ा हो सकता है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोक भवन योजना के लिए साल 2018–19 के बजट में 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।

लोक भवन योजना का उद्देश्य

राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य हर इलाके में एक सामुदायिक भवन का निर्माण करना है जिसमें सामाजिक - सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जा सके। लोक भवन का उपयोग इलाके की व्यवसायिक गतिविधियों के लिए भी किया जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार ने गैर-सामाजिक संगठनों व स्वयं सहायता समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप) द्वारा भी विभिन प्रकार के उत्पादों की बिक्री, प्रदर्शनी के लिए लोक भवन का इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्य के किसी इलाके के छात्रों से संबंधित सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों के लिए भी लोक भवन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही इलाके के लोगों के लिए सरकार द्वारा आयोजित कार्यशाला एवं शिविर का आयोजन भी लोक भवन में हो सकता है। लोक भवन में किसी धार्मिक संस्था या राजनीतिक दल की कार्यशाला और कार्यक्रम नहीं हो सकते।

निर्माण की प्रक्रिया

हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अधीनस्थ मंडल स्तर पर संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा भवन के मानदंड तैयार किए जाते ह।। इसमें बिजली - पानी - शौचालय और रसोई इत्यादि का भी प्रावधान किया जाता है। लोक भवन योजना के तहत बिल्डिंग बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 30 लाख रुपये की रकम स्वीकृत की जाती है। इसे 2 किश्त में संबंधित जिला अधिकारी के जरिये खंड विकास अधिकारी को भेजा जाता है। लोक भवन का निर्माण शुरू होने पर पहली किस्त के रूप में 20 लाख रुपये जबकि दूसरी व अंतिम किश्त 10 लाख रुपये कार्य पूर्ण होने पर जारी होती है।

लोक भवन के उपयोग पर फीस लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था से एक तयशुदा फीस लेने का भी प्रावधान है। यह फीस उस इलाके की पंचायत समिति तय कर सकती है। इस फीस से ही लोक भवन के रख-रखाव पर खर्च किया जायेगा। इसी रकम से बिजली-पानी के बिल एवं अन्य कर का भुगतान किया जा सकेगा। पंचायत समिति इसका हिसाब-किताब रखेगी। लोक भवन के लिए भूमि का चुनाव हिमाचल सरकार द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक लोक भवन किसी सरकारी या निजी भूमि पर बन सकता है।

विधानसभा सदस्य के अनुमोदन पर इलाके के उपायुक्त इस भूमि का चुनाव कर सकते हैं। लोक भवन दो बीघे में बनाया जा सकता है।जमीन विवादित नहीं होनी चाहिए। अगर लोक भवन निजी जमीन पर बनाया जा रहा है तो इस जमीन को हिमाचल सरकार के नाम हस्तांतरित करना चाहिए। सामुदायिक भवन का निर्माण भूमि चयन के बाद दो साल में पूरा कर लिया जाना चाहिए।

लोक भवन योजना से फायदे

- पंचायत समिति के लिए आमदनी का स्रोत बनेगा।
- लोगों को सांस्कृतिक-सामाजिक कार्यक्रम के लिए जगह मिलेगी। इलाके के सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक छत के नीचे बैठकर योजना बनाने में मदद मिलेगी।
- इलाके के शिल्पकारों, कलाकारों को प्रदर्शनी के लिए मामूली शुल्क पर जगह मिल सकती है।
- छात्रों, युवाओं को अपने कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल मिल सकेगा।
- इलाके की महिलाएं - छात्राएं सामाजिक - सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल हो सकेंगी।

मुख्य मंत्री कन्यादान योजना

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में महिलाओं और बेटियों के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपको प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाई जा रही दो महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। इसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि योजनाओं के लिए क्या पात्रता है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्य मंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार का इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो अपनी बेटी के विवाह की लागत का खर्च नहीं उठा सकते हैं।

पहले इस योजना के तहत 25,000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 40 हजार रूपये कर दिया गया है।

ये हैं पात्र

अनाथ लड़कियों, नारी निकेतन, बालिका आश्रम में रहने वाली लड़कियों, तलाकशुदा और तलाकशुदा दंपति की लड़कियों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाती है।

नियमों के तहत कन्यादान राशि प्राप्त करने के लिए संबंधित लड़कियां पंचायत, स्थानीय निकाय, बाल कल्याण परियोजना अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी, नारी सेवा सदन, नारी निकेतन और अधीक्षक बाल आश्रम के पास आवेदन कर सकती हैं। आवेदन पत्र की जिला परियोजना अधिकारी से पुष्टि की जाएगी।

जरुरी दस्तावेज

आवेदन में जन्मतिथि का सुबूत, जिस लड़के से शादी हो रही है, उसका पूरा विवरण, शादी की तारीख की स्थानीय स्तर से पुष्टि, आय के प्रमाणपत्र भी देने होंगे। सभी आवेदनों की पूरी जांच होने के बाद जिला परियोजना अधिकारी की ओर से कन्यादान राशि जारी की जाएगी।

मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के लाभ

- यह योजना पात्र लड़कियों को वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्रदान करती है।
- इस योजना के तहत 40,000 रूपये की वित्तीय सहायता लाभार्थी लड़कियों को उनकी शादी के लिए प्रदान की जाती है।

आवश्यक पात्रता और शर्तें

- योजना हिमाचल प्रदेश की निवासी लड़कियों के लिए है।
- लड़कियां जो अनाथ हैं या जिनका पिता शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अक्षम या अस्पष्ट है, योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- वार्षिक आय 35,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन

योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। गूगल पर एचपी वूमैन एंड चाइल्ड वैल्फेयर डिपार्टमेंट का लिंक डालते ही विभाग की योजना जान सकते हैं। यहां पर डाउनलोड लिंक पर जाकर योजना फार्म डाउनलोड किया जा सकता है। इस योजना के लिए आप हिमाचल प्रदेश के सामाजिक एवं महिला कल्याण विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं।

योजना का अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से भी जानकारी ले सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आप जिला कार्यालय के पास संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार आप हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।

हिमाचल प्रदेश मे विधवा पुन विवाह योजना

महिला और बाल विकास मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी विधवा पुन विवाह योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवाओं के पुन विवाह में मदद करना है और विधवाओं के साथ पुनर्विवाह करने के लिए पुरुषों को प्रोत्साहित करना। यह योजना ऐसी विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत रुपये 50, 000 की राशि दी जाती हैं जिसमें से रुपये 20,000 का नकद अनुदान दिया जाता है विवाह के समय और रुपये 30,000 को कम से कम पांच साल के लिए संयुक्त रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखा जाएगा। पहले इस योजना के तहत भी 25 हजार देने का ही प्रावधान था लेकिन बाद में योजना नियमों संशोधन कर राशि को दोगुना कर दिया गया। इस पहल ने राज्य के कई असहाय विधवाओं की मदद की है। हिमाचल की सभी विधवा स्थायी निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक विवरण और आवेदन फार्म निकटतम जिला कल्याण कार्यालय, हिमाचल प्रदेश सरकार, में प्राप्त किया जा सकता है।

विधवा पुन विवाह योजना के लाभः

यह योजना पात्र विधवा को वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्रदान करती है इस योजना के अंतर्गत रुपये 25,000 की राशि दी जाती हैं जिसमें से रुपये 10,000 का नकद अनुदान दिया जाता है विवाह के समय और रुपये 15,000 को कम से कम पांच साल के लिए संयुक्त रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखा जाएगा

आवश्यक पात्रता और शर्तें

- महिला और पुरुष दोनों हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए
- पुरूष की उम्र 21 से कम न हो
- महिलाओं की आयु 18 वर्ष से कम न हो

- **आवश्यक दस्तावेज**
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- बैंक पासबुक की प्रतिलिपि
- पहचान प्रमाण
- पुरुष और महिला दोनों के निवासी प्रमाण
- आधार कार्ड
- विधवा से विवाह करने वाले व्यक्ति का नाम और पता
- फिर से पुनर्विवाह की तिथि
- पहली शादी की तिथि
- वह तिथि जब वह विधवा हो गई

आवेदन करने की प्रक्रियाः

आवेदक को वित्तीय सहायता के लिए आवेदन विवाह करने के छह माह के भीतर करना अनिवार्य है। इसके लिए योग्यता की पुष्टि करनी भी जरूरी है और जिला या तहसिल कल्याण कार्यालय में आवेदन करना चाहिए। आवेदन पत्र उसी कार्यालय में प्राप्त किया जा सकता है या नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

सेतु भारतम योजना

मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। यह स्लोगन नरेन्द्र मोदी की सरकार ने एक साल पूरा होने पर दिया था। कोई माने या न माने, वाकई में देश की गाड़ी आगे बढ़ी है। लोग जीडीपी की बाल उधेड़ें, बेरोजगारी की बात उठाएं लेकिन सच यह है कि देश तेजी के साथ पुलों और सड़कों का निर्माण हो रहा है। भारत को जोड़ने और लोगों को नजदीक लाने में पुलों का योगदान कितना होता है, यह बताने की जरूरत नहीं और सरकार इसी पर जोरशोर से काम कर रही है।

सरकार ने सेतु भारतम नाम से योजना की शुरुआत की है जिसके जरिए रेलवे क्रासिंग पर पुलों का निर्माण हो रहा है। रेलवे क्रासिंग पर आपका और हमारा कितना वक्त बर्बाद होता है, यह बताने की जरूरत नहीं। एक्सप्रेस वे व फोरलेन नेशनल हाइवे पर तो रेलवे क्रासिंग पर पुल बना दिए गए हैं लेकिन डबल लेन नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर रेलवे क्रासिंगों की भरमार है। क्रासिंग पर अगर एक बार जाम लग गया तो फिर भगवान ही मालिक है।

इसी समस्या को देखते हुए सेतु भारतम योजना के तहत रेल ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ। इसके साथ ही पुराने रेलवे ओवर ब्रिज की भी मरम्मत करवाई जा रही है। जहां पर जरूरत है, पुल के पैरलल दूसरा पुल भी बनाया जा रहा है। कहां कितने पुल बन रहे हैं, इसका विस्तृत विवरण आपको यहां बताते है। सेतु भारतम योजना के तहत पूरे देश मे 20 हजार 800 करोड़ की लागत से 208 रेल ओवर ब्रिज व रेल अंडर ब्रिज का निर्माण करवाया जा रहा है।

सेतु भारतम योजना के तहत सबसे अधिक पुल बन रहे आंध्र में

इस योजना के तहत सबसे अधिक रेल ओवर ब्रिज आंध्र प्रदेश में बन रहे हैं। यहां पर 33 रेल ओवर ब्रिज या रेल अंडर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही असम में 12, बिहार में 20, गुजरात में 8, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 5, झारखंड में 11, कर्नाटक में 17, केरल में 4, मध्य प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 12, ओडिशा में 4, पंजाब में 10, राजस्थान में 9, तमिलनाडु में 9, उत्तराखंड में 2, उत्तर प्रदेश में 9 और पश्चिम बंगाल में 22 पुलों का निर्माण या तो हो रहा है या पूरा हो चुका है।

2015 में शुरू हुई इस योजना के तहत काम तेजी से चल रहा है। कई राज्यों में कई रेल ओवर ब्रिज व रेल अंडर ब्रिज चालू भी हो चुके हैं। इससे लोगों को काफी राहत मिली है। जिन राज्यों में काम बाकी है, उसे भी युद्धस्तर पर करवाया जा रहा है। पहले फेज में 73 पुलों को स्वीकृत किया गया था जिनमें से 90 प्रतिशत जनता को सौंपे जा चुके हैं। बाकी राज्यों के रेल ओवर ब्रिज को भी चरणबद्ध तरीके से स्वीकृति दे दी गई।

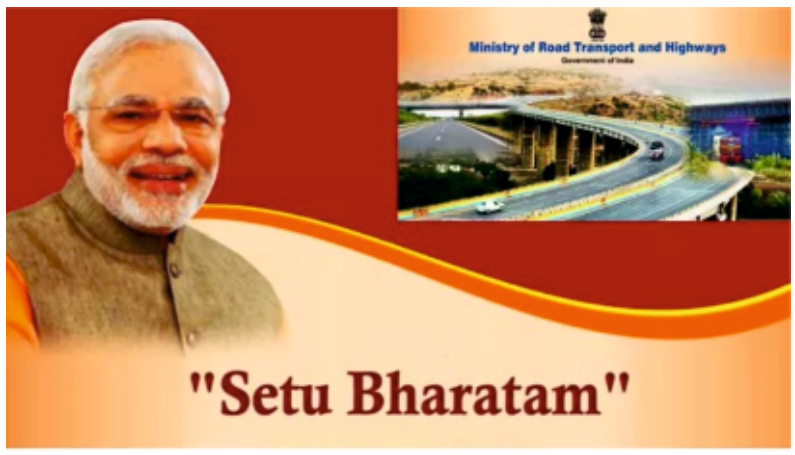

1500 पुराने पुलों की हो रही मरम्मत

सेतु समुद्रम योजना के तहत देश भर में 1500 ऐसे पुलों को भी चुना गया जिनकी हालत खस्ता हो चुकी थी या इन पर ट्रैफिक का लोड काफी ज्यादा था। कभी चौड़े रहे पुल ट्रैफिक का लोड बढ़ने के बाद संकरे हो गए। इस बात के देखते हुए सरकार ने 30 हजार पुलों के सुधार का काम चरणबद्ध तरीके से शुरू करवा दिया है।

जो पुल कमजोर हो गए थे, उनकी मम्मत करवाई जा रही है। पुल का जो हिस्सा काफी कमजोर पड़ चुका था, उसे बदला गया है। इसके अलावा जिन पुलों पर लोड ज्यादा था, उनके बगल में एक नया पुल भी बनाया जा रहा है। कई का काम अब पूरा होने के कगार पर है।

50 हजार पुलों का तैयार किया गया ब्योरा

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यूपी में नोएडा स्थित इंडियन एकेडमी फॉर हाइवे इंजीनियर में भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली की भी स्थापना की है। इसका मकसद मोबाइल इंस्पेक्शन यूनिटों की मदद से देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने सभी पुलों की कंडीशन का सर्वे करना है। इस काम के लिए 11 सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। अब तक यह समिति 50 हजार पुलों का निरीक्षण करने के बाद ब्योरा एकत्र कर चुकी है।

यह समिति बताएगी कि किस पुल में कौन सी खामी है और इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। नए पुल के लिए भी यही समिति सुझाव देगी। इन्हीं सुझावों के आधार पर बाकी के रेल ओवर ब्रिज व फ्लाई ओवर की मरम्मत या चौड़ीकरण पर काम शुरू होगा। इसके लिए बजट का प्रावधान अलग से होगा। सरकार की कोशिश है कि जितनी भी जल्दी हो सके, पुलों के जीणोद्धार व चौड़ीकरण का काम शुरू हो।

रुट को डायवर्ट किया गया

जिन रेलवे क्रासिंग्स पर पुलों का निर्माण हो रहा है, वहां पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया जा रहा है। पुलों के निर्माण में पहले से तैयार बीम का प्रयोग किया जाता है। कई जगह पर स्लैब भी ढाले जा रहे हैं। बस क्रासिंग के ऊपर के हिस्से पुल को ढालने का काम रेलवे का होता है। पुल के बाकी के हिस्से का निर्माण राजमार्ग मंत्रालय द्वारा करवाया जाता है। रेलवे अधिकांश जगहों पर क्रासिंग के ऊपर लोहे के गार्डर को रखती है जिस पर आरसीसी से ढलाई की जाती है।

उत्तर प्रदेश में काम सबसे तेज

रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज व अंडर ब्रिज को बनाने का काम उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से चल रहा है। यहां पर एक, दो को छोड़कर बाकी के पुल बन चुके हैं। महाराष्ट्र में भी काम तेजी से चल रहा है। सबसे अधिक धीमी गति पश्चिमी बंगाल में है। जब यह सारे काम पूरे हो जाएंगे तो जिन 50 हजार पुलों का सर्वे किया गया है, उन पर काम शुरू होगा। सारे पुलों की मरम्मत व चौड़ीकरण में 10 साल से अधिक का वक्त लगेगा।

टोल फ्री हैं सारे पुल

जिन राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल पहले से लगता है, वहां पर रेलवे ओवर ब्रिज के लिए अलग से टोल नहीं लिया जा रहा है। जो टोल फ्री राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वहां पर पुलों पर किसी भी प्रकार का टोल नहीं लिया जाएगा। यानि नए बने रेल ओवर ब्रिज पर आना जाना बिल्कुल फ्री है। आगे भी जिन पुलों का निर्माण होगा, उस पर भी कोई टोल नहीं लिया जाएगा।

पुलों का निर्माण या तो सरकारी एजेंसी करवा रही हैं या इसके लिए टेंडर निकाले गए हैं। जिन पुलों के निर्माण का काम टेंडर के जरिए प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है, उनकी गुणवत्ता की निगरानी मंत्रालय के अफसरों के साथ ही थर्ड पार्टी से भी करवाई जा रही है। मंत्रालय की ओर से नामित एजेंसी हर पुल की गुणवत्ता पर नजर रखती है और अपनी रिपोर्ट देती है।

इसी रिपोर्ट के आधार पर पुल में सुधार करवाए जाते हैं। अगर रिपोर्ट निगेटिव होती है तो कंपनी का भुगतान तक रोकने का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं पुलों की गुणवत्ता से समझौता करने वाली कंपनी पर हैवी पेनाल्टी तो लगाई ही जाएगी, उसे ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा। ब्लैक लिस्टेड होने का मतलब है कि यह कंपनी फिर सरकारी काम नहीं कर सकेगी।

हिमाचल प्रदेश मे मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना

द रीव टाइम्स ब्यूरो : महिला और बाल विकास मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना शुरू की गई है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों का कल्याण है। अनाथ बच्चा वह है जिसका माता पिता मृत, अज्ञात है, या उसे स्थायी रूप से त्याग दिया है, इस तरह के बच्चों की देखभाल और रखरखाव के लिए यह योजना हैं। इस योजना के तहत हिमाचल सरकार को मुफ्त आश्रय, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त भोजन और पेशेवर मार्गदर्शन और कई अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई हैं। राज्य में सभी अनाथ बच्चों की सहायता करने के लिए, बाल उधार योजना का हिस्सा बनने और योजना द्वारा प्रदान किए गए सभी लाभ प्राप्त करने के लिए रिश्तेदार मदद करें। महिलाओं और बाल विकास कार्यालय में अधिक विवरण और आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है ।

मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना के लाभः

अनाथ बच्चों को कई लाभ प्रदान करने के लिए बाल कल्याण योजना

इस योजना के तहत, हिमाचल सरकार ने अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, आवास, खाना, व्यावसायिक मार्गदर्शन और कई अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई हैं

मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना के लिए आवेदन करने की आवश्यक पात्रता और शर्तें

- हिमाचल प्रदेश के अनाथ लड़की या लड़के

मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना के लिए आवेदन करने वाले आवश्यक दस्तावेजः

- पहचान प्रमाण
- आवेदन पत्र (कार्यालय में उपलब्ध)
- निवासी प्रमाण

मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत अब किसान अपनी पसंद की कंपनी से करवा सकेंगे सोलर फेंसिंग

द रीव टाइम्स ब्यूरो

फसल को जंगली जानवरो से बचाने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत अब किसान अपनी पसंद की कंपनी से सोलर फेंसिंग करवा सकेंगे। जिसके लिए सरकार ने 32 विभिन्न कंपनियों को सोलर फैंसिंग के लिए मान्यता दी है। अगर किसानों को एक कंपनी का प्रोजैक्ट पसंद नही आता है तो वह दूसरी कंपनी से सोलर फैंसिंग लगवा सकता है ।

वहीं अगर किसान इसी सोलर प्लांट प्रोजैक्ट को सामूहिक रूप से लगवाते हैं तो इन्हें 85 फीसदी तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। जबकि एकल किसान को इस योजना के तहत सोलर फैंसिंग लगाने पर 80 फीसदी अनुदान का प्रावधान है।

इच्छुक किसान अपनी जिला कृषि खंड में जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब यह योजना पूर्व सरकार में शुरू की गई थी तो इस पर किसानों को 60:40 के अनुपात में अनुदान किसानों को दिया जा रहा था। लेकिन इस अनुपात में किसानों को इसका खर्च काफी ज्यादा पड़ता था। जिससे किसानों ने इस योजना से किनारा ही कर लिया। जिसके बाद इस योजना पर 80 फीसदी का अनुदान कर दिया गया।

सोलर प्लांट में भी तकनीकी दिक्कतें आने के बाद किसान अब सोलर फैंसिंग के स्थान पर कांटेदार तार या जालीदार जाल लगवाने की मांग करने लगे हैं। किसान वर्ग का मानना है कि सोलर प्लांट योजना उत्पाती जानवरों के लिए उचित नही है। इसमें लगने वाली तार को जंगली जानवर एक ही झटके में तोड़ देंगे।

वहीं अगर इस सोलर फैसिंग का घास टच करता है तो इसमें लगा करंट काम नही करेगा। जिससे बरसाती दिनों में इसका रखरखाव काफी मुश्किल हो सकता है। मुख्यमंत्री खेत सरंक्षण योजना के तहत सोलर प्लांट में तार लगाने के तीन अलग-अलग प्रोजैक्ट हैं। जिनमें पांच फीट, सात फीट व नौ फीट ऊंचाई के प्रोजैक्ट हैं। अब यह किसान पर निर्भर करता है कि वह कौन सा प्रोजैक्ट लगवाना चाहता है, किसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है।

इस योजना के तहत खेत का चारो तरफ से कवर करने के लिए 1500 मीटर रनिंग में तार लगाई जाएगी। 1500 मीटर तार को करंट देने के लिए एक सोलर प्लांट भी स्थापित होगा। इसी सोलर प्लांट से खेत के चारों तरफ लगाई गई तार में करंट दौड़ेगा। सोलर फैसिंग में इसके आसपास हर समय घास कटा हुआ चाहिए। 32 कंपनियों को सोलर फैंसिंग लगवाने के लिए सरकार ने मान्यता दे दी है। किसान अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी का प्रोजैक्ट खेत में लगवा सकता है।

घरेलू उत्पाद में लगभग 30 प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्र का है। जंगली और बेसाहरा जानवर किसानों के लिए विकराल समस्या बने हुए हैं। फसलों को नुकसान पहुंचाने के चलते किसान खेतीबाड़ी से छोड़ने को मजबूर होने लगे थे। किसानों द्वारा समय-समय पर प्रदेश सराकर के समक्ष भी यह गंभीर समस्या लाई जा रही थी । प्रदेश सरकार ने किसानों के फसलों को बचाने और प्रदेश की उपजाऊ भूमि को हराभरा रखने के लिए महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना तैयार की जिससे किसानों के खेतों को बाड़ लगाकर फसलों को बचाया जा सके । सरकार ने खेतों की बाड़ बंदी के लिए मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना में सौर उर्जा आधारित बाड़ लगाने की योजना तैयार की। इस योजना में किसानों को सौर बाड़ 80 प्रतिशत उपदान पर उपलब्ध करवाई गई। सौर बाड़ में हल्का सौर आधरित करंट होता है और जैसे ही कोई जानवर इसके संपर्क में आता है उसको हल्का करंट लगता है और जानवर यहां से भाग जाता है। करंट हल्का होने के चलते इंसान के इसके संपर्क में आने से उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। सौर उर्जा आधारित बाड़ के काफी सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं और किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए यह बाड़ लगाने के लिए आगे आने लगे हैं। पालमुपर उपमण्डल के गांव गदियाड़ा, डाकघर सल्याणा के भूतपूर्व सैनिक कै० प्यार चंद लावारिस पशुओं के खौफ से लगभग अपने खेतों की बीजाई का कार्य छोड़ चुके थे। विभाग की योजनाओं से अवगत करवाने के लिए विभाग समय-समय पर जागरूकता कैंप और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

तुर्की में है नर्क का दरवाजा, जहां अंदर जाने वाला नहीं लौटता

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं, जो किसी न किसी वजह से रहस्यमयी बनी हुई हैं। एक ऐसी ही जगह तुर्की के प्राचीन शहर हेरापोलिस में है, जहां एक बेहद ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यहां नर्क का द्वार है, जिसके अंदर जाना तो दूर, पास जाने वाला भी कभी लौटकर वापस नहीं आया।

कहा जाता है कि इस मंदिर के संपर्क में आते ही इंसान से लेकर पशु-पक्षी तक मर जाते हैं। कई साल पहले तक यह जगह रहस्यमयी बनी हुई थी, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि यहां आने वालों की मौत यूनानी देवता की जहरीली सांसों की वजह से हो रही है। यहां लगातार हो रही मौतों की वजह से लोग इस मंदिर के दरवाजे को नर्क का द्वार कहने लगे। कहते हैं कि ग्रीक, रोमन काल में भी लोग मौत के डर की वजह से यहां जाने से डरते थे। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा लोगों की रहस्यमयी मौतों की गुत्थी सुलझा ली गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर के नीचे से लगातार जहरीली कार्बन डाई ऑक्साइड गैस रिसकर बाहर निकल रही है, जिसके संपर्क में आते ही इंसानों और पशु-पक्षियों की मौत हो जाती है। वैज्ञानिकों के शोध के मुताबिक, मंदिर के नीचे बनी गुफा में बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाई ऑक्साइड गैस पायी गई है। जहां आमतौर पर मात्र 10 फीसदी कार्बन डाई ऑक्साइड ही किसी भी इंसान को महज 30 मिनट में मौत की नींद सुला सकता है, वहीं यहां गुफा के अंदर इस जहरीली गैस की मात्रा 91 फीसदी है। आश्चर्यजनक रूप से गुफा के अंदर से निकल रही भाप की वजह से ही यहां आने वाले कीड़े-मकोड़े और पशु-पक्षी मारे जाते हैं। ये जगह पूरी तरह से वाष्प से भरी होने की वजह से काफी धुंधली और घनी है, जिसकी वजह से यहां जमीन भी मुश्किल से ही दिखाई देती है।

यहां हर वक्त कड़कती है आसमानी बिजली, वैज्ञानिक भी हैरान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विज्ञान आज भले ही कितनी भी तरक्की कर चुका है, लेकिन धरती पर आज भी ऐसी बहुत ही जगहें हैं, जहां का रहस्य सुलझाने में वैज्ञानिक भी नाकाम रहे हैं। ऐसी ही एक जगह दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में भी है, जहां एक झील के ऊपर हर वक्त बिजली कड़कती रहती है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई भी जान नहीं पाया है।

दुनिया को हैरान कर देने वाले इस रहस्य को बीकन ऑफ मैराकाइबो कहा जाता है। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे कि कैटाटुम्बो लाइटनिंग, एवरलास्टिंग स्टॉर्म, ड्रैमेटिक रोल ऑफ थंडर। इस जगह को दुनिया का कुदरती बिजली घर भी कहते हैं। बीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, वेनेजुएला में कैटाटुम्बो नदी जिस जगह पर मैराकाइबो झील में मिलती है, वहां साल में 260 दिन तूफानी होते हैं। इन 260 दिनों की तूफानी रातों में यहां रात भर बिजली चमकती रहती है। मैराकाइबो झील का नाम सबसे ज्यादा बिजली चमकने वाले स्थान के तौर पर गिनीज बुक में दर्ज है। सर्दियों के मौसम में तो कम, लेकिन बरसात के मौसम में यहां खूब बिजली चमकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस मौसम में यहां हर मिनट 28 बार बिजली चमकती है। इस आसमानी बिजली की चमक इतनी ज्यादा होती है कि यह 400 किलोमीटर की दूरी से भी दिखाई देती है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक शोध किया था, जिसके मुताबिक झील के पास के तेल क्षेत्रों में मीथेन की प्रचुर मात्रा होने के चलते आकाश में बिजली ज्यादा चमकती है। हालांकि यूरेनियम और मीथेन वाला सिद्धांत प्रामाणिक तौर पर साबित नहीं हो सका है। इसलिए यह जगह अब भी रहस्य ही बनी हुई है।

दुनिया के वो पांच देश, जिनके पास नहीं है अपनी कोई सेना

द रीव टाइम्स ब्यूरो

किसी भी देश में सुरक्षा के दो स्तर होते हैं, पहला पुलिस और दूसरा सेना। जहां पुलिस की जिम्मेदारी देश की आंतरिक सुरक्षा की होती है, तो वहीं सेना की जिम्मेदारी बाहरी सुरक्षा की होती है यानी बॉर्डर (सीमा) की सुरक्षा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं, जिनके पास अपनी कोई सेना है ही नहीं। इनमें से कुछ देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो दूसरे देश उठाते हैं।

वैटिकन सिटी, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, उसके पास किसी तरह की कोई आर्मी (सेना) नहीं है। यहां पहले नोबल गार्ड हुआ करते थे, लेकिन साल 1970 में इस संस्था को ध्वस्त कर दिया गया। इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी इतालवी सेना की है। मोनैको भी एक छोटा सा देश है, जहां 17वीं शताब्दी से ही किसी तरह की कोई सेना नहीं है। हालांकि यहां दो छोटी-छोटी फौजी टुकड़ियां हैं, जिसमें से एक राजकुमार की सुरक्षा करती है और एक नागरिकों की। फ्रांस की सेना इसे सुरक्षा प्रदान करती है।

मॉरीशस एक बहुसांस्कृतिक देश है। यहां भी साल 1968 से ही किसी तरह की कोई सेना नहीं है। हालांकि यहां 10,000 पुलिस कर्मी हैं, जो आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं।

यूरोप के दूसरे सबसे बड़े द्वीप आइसलैंड में भी साल 1869 से ही कोई सेना नहीं है। यह देश नाटो का सदस्य है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है।

मध्य अमेरिका के कैरिबियाई क्षेत्र में स्थित देश कोस्टा रिका में साल 1948 के बाद से कोई भी सेना नहीं है। 1948 में यहां भयंकर गृहयुद्ध छिड़ गया था, जिसके बाद इस देश ने अपनी सेना समाप्त कर दी। यह देश बिना सेना के चलने वाले बड़े देशों में शुमार है।

चांद नहीं होता तो क्या होता...

द रीव टाइम्स ब्यूरो

चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह खुद से नहीं चमकता बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चांद पर अब तक 12 लोग कदम रख चुके हैं, लेकिन अगर चांद नहीं होता तो धरती पर दिन-रात 24 घंटे के बजाए सिर्फ छह से 12 घंटे का ही होता। एक साल में 365 दिन नहीं बल्कि 1000 से 1400 के आसपास दिन होते। अगर चांद नहीं होता तो रोशनी भी नहीं होती। हर जगह गहरा अंधेरा ही छाया रहता। चांद अगर नहीं होता तो धरती पर न तो चंद्रग्रहण होता और ना ही सूर्यग्रहण, क्योंकि सूरज को ढंकने के लिए चंद्रमा होता ही नहीं। वैज्ञानिकों की मानें तो अगर चांद नहीं होता, तो शायद पृथ्वी पर मानव जाति का उदय भी नहीं हुआ होता, क्योंकि समुद्रों में ज्वार भाटा ही नहीं आता, जिससे जमीन और समुद्री जल के बीच पोषक तत्वों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया धीरे हो जाती और धरती पर मानव जाति होती भी या नहीं, ये कहना मुश्किल है।

शुरू होने वाला है विश्व का सबसे लंबा केबल ब्रिज

द रीव टाइम्स ब्यूरो

एशिया में इन दिनों सबसे लंबा पुल बनाने की होड़ मची हुई है। खास तौर पर भारत और चीन के बीच। पिछले साल ही भारत ने एशिया का सबसे बड़ा पुल शुरू किया है। अब चीन जल्द ही दुनिया का सबसे लंबा पुल शुरू करने जा रहा है। चीन द्वारा बनाए जा रहे पुल की खासियत ये है कि इसमें नदी के किनारों पर केवल दो पिलर होंगे। नदी के ऊपर पूरा पुल केबल पर टिका होगा। इस पुल को हवा में तैरने वाले पुल की तकनीक पर बनाया जा रहा है। मतलब ये पुल हवा में झूलता रहेगा।

सिन्हुआ न्यूज के अनुसार, चीन में बन रहा दुनिया का सबसे लंबा केबल ब्रिज किंगशान यांग्त्जी नदी पर बनाया जा रहा है। इसका निर्माण चीन की रेलवे मेजर ब्रिज इंजीनियरिंग ग्रुप कंपनी द्वारा किया जा रहा है। मालूम हो कि चीन की किंगशान यांग्त्जी नदी, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी भी है। इस पर बन रहे दुनिया के सबसे लंबे केबल ब्रिज का काउंट डाउन शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 2020 की शुरुआत में इस पुल पर ट्रैफिक शुरू कर दिया जाएगा। पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और फिलहाल इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

एक गांव जो बसा है जमीन के नीचे

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दुनिया में एक ऐसा गांव भी है, जहां की पूरी आबादी जमीन के अंदर ही रहती है। इस अनोखे गांव का नाम है कूबर पेडी, जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि यहां के लगभग सभी लोग अंडरग्राउंड घरों में रहते हैं। बाहर से देखने पर ये घर भले ही साधारण लगें, लेकिन अंदर का नजारा किसी होटल से कम नहीं होता।

दरअसल, इस इलाके में ओपल की कई खदानें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कूबर पेडी में माइनिंग का काम साल 1915 में शुरू हुआ था। दरअसल, यह एक रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए यहां पर गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा और सर्दियों में बहुत कम हो जाता है। इस कारण यहां रहने वाले लोगों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता था। इसका यह हल निकला कि लोग माइनिंग के बाद खाली बची खदानों में रहने के लिए चले गए। कूबर पेडी के इन अंडरग्राउंड घरों में न तो गर्मियों में ए सी की जरूरत पड़ती है और न ही सर्दियों में हीटर की। आज के समय में यहां पर 1500 से ज्यादा ऐसे घर हैं, जो जमीन के अंदर हैं और लोग यही पर रहते हैं।

पाकिस्तान के मीठी में मुसलमानों से ज्यादा रहते हैं हिंदू

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पाकिस्तान में हिंदुओं की खराब हालत से पूरी दुनिया वाकिफ है। यहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और जबरन धर्म परिवर्तन की खबरें हमेशा मीडिया में सुर्खियां बनी रहती हैं, लेकिन यहीं पर एक शहर ऐसा भी है, जहां से कभी भी इस तरह की खबरें नहीं आतीं। इस शहर में मुसलमानों से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। इस शहर का नाम है मीठी, जो मीठी थारपारकर जिले में स्थित है। यह शहर पाकिस्तान के लाहौर से करीब 875 किलोमीटर, जबकि भारत के गुजरात के अहमदाबाद से करीब 340 किलोमीटर दूर है। इस शहर में हिंदू-मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल देखने को मिलती है। मीठी की कुल आबादी करीब 87 हजार है, जिसमें से करीब 80 फीसदी लोग हिंदू हैं, जबकि पूरे पाकिस्तान में करीब 95 फीसदी मुसलमान हैं। कहा जाता है कि इस शहर में जब भी कोई धार्मिक त्योहार या सांस्कृतिक आयोजन होता है तो हिंदू-मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग उसमें मिल-जुलकर हिस्सा लेते हैं।

मीठी में हिंदू लोग मुहर्रम के जुलूसों में हिस्सा लेते हैं और कई बार तो मुसलमानों के साथ रोजे भी रखते हैं। वहीं, हिंदुओं के धर्म का सम्मान करते हुए यहां के मुसलमान गाय को नहीं काटते। यहां तक कि वो बीफ भी नहीं खाते।

इस शहर में क्राइम रेट पाकिस्तान के दूसरे शहरों की अपेक्षा बिल्कुल कम है। यहां अपराध दर महज दो फीसदी है और सबसे खास बात कि यहां धार्मिक असहिष्णुता कभी भी देखने को नहीं मिलती। इस शहर में कई मंदिर भी हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध श्रीकृष्ण मंदिर है। कहते हैं कि जब यहां हिंदू मंदिरों में पूजा करते हैं, तब अजान के लिए तेज आवाज में स्पीकर नहीं बजाए जाते हैं और नमाज के वक्त मंदिरों में घंटियां नहीं बजाई जाती हैं। यहां के मुसलमानों का कहना है कि 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में जब भारतीय सेनाएं मीठी तक पहुंच गई थीं, तब उन्हें रातोंरात यहां से भागना पड़ा था। हालांकि बाद में यहां रहने वाले हिंदुओं ने उन्हें फिर से यहां रहने के लिए मनाया, उसके बाद फिर से वो लोग यहां रहने आ गए।

भारत का वो अनोखा मंदिर, जहां हवा में लटके हैं खंभे

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत को अगर मंदिरों का देश कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां इतने मंदिर हैं कि आप गिनते-गिनते थक जाएंगे, लेकिन गिन नहीं पाएंगे। यहां ऐसे कई मंदिर हैं, जो अपनी भव्यता और अनोखी मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक अनोखा मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भी है। इस मंदिर की सबसे खास और रहस्यमयी बात ये है कि इसके खंभे हवा में लटके हुए हैं, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है।

लेपाक्षी मंदिर के अनोखे खंभे आकाश स्तंभ के नाम से भी जाने जाते हैं। ये खंभे जमीन से करीब आधा इंच ऊपर उठे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि खंभे के नीचे से कुछ निकालने से घर में सुख-समृद्धि आती है। यही वजह है कि यहां आने वाले लोग खंभे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। कहा जाता है कि मंदिर के खंभे पहले जमीन से जुड़े हुए थे, लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने यह जानने के लिए कि यह मंदिर पिलर पर कैसे टिका हुआ है, इसको हिला दिया, तब से ये खंभे हवा में ही झूल रहे हैं। इस मंदिर में इष्टदेव भगवान शिव के रौद्र रूप वीरभद्र हैं। वीरभद्र महाराज दक्ष के यज्ञ के बाद अस्तित्व में आए थे। इसके अलावा यहां भगवान शिव के अन्य रूप अर्धनारीश्वर, कंकाल मूर्ति, दक्षिणमूर्ति और त्रिपुरातकेश्वर भी मौजूद हैं। यहां विराजमान माता को भद्रकाली कहा जाता है। कुर्मासेलम की पहाडियों पर बना ये मंदिर कछुए की आकार में बना है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण विरुपन्ना और विरन्ना नाम के दो भाइयों ने 16वीं सदी में कराया था, जो विजयनगर के राजा के यहां काम करते थे।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

द रीव टाइम्स

संस्थापक: डॉ एल.सी. शर्मा

द रीव टाइम्स के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस, सायबू निवास समीप सेक्टर-2, बस स्टैंड, मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित

संपादक: हेम राज चौहान

फोन न. : 0177 2640761
आर.एन.आई. रिफ्रेंस नं. 1328500
टाइटल कोड : HPBIL00313
पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं. HP/129/SML/2019-2021

E-mail : hem.raj@iirdshimla.org
Website : www.therievtimes.com

आवश्यक सूचना

हिमाचल का सबसे तेज गति से उभरता पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स में मार्केटिंग हेतु युवाओं (लड़के/लड़कियों) की आवश्यकता है। एक स्थाई रोजगार एवं बेहतर वेतनमान के साथ आकर्षक कमीशन का प्रावधान रहेगा। इच्छुक शीघ्र ही संपर्क करें।

द रीव टाइम्स

दूरभाष : 9418404334

Chauhan.hemraj09@gmail.com, hem.raj@iirdshimla.org